चिंतन

प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आवश्यक

प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता, शुचिता और एकरूपता जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रतिभा को उचित अवसर मिले, यह कोशिश परीक्षा नियंत्रकों, भर्ती बोर्डों और आयोगों की ओर से होनी चाहिए, होती भी रही है, लेकिन साथ में भ्रष्टाचार की दीमक भी है। देश में अक्सर पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं, परीक्षा माफिया के सक्रिय होने और उसके साथ सरकारी मशीनरी के कुछेक लोगों की मिलीभगत होने से मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसे प्रवेश परीक्षाओं और नौकरियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में धांधली की खबरें आती रहती हैं। भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में कदाचार के चलते परीक्षाओं का रद होना, मामला कोर्ट तक जाना आम होने लगे हैं। इस बार नीट-यूजी परीक्षा में जिस तरह केवल कुछेक केंद्रों के 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क देने का मनमाना फैसला परीक्षा आयोजक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने किया, वह हैरान करने वाला था। क्योंकि, एग्जाम के पहले एनटीए की तरफ से जारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी ग्रेस मार्क्स देने के प्रावधान का जिक्र नहीं था। नीट-यूजी परीक्षा में चुनिंदा अभ्यर्थियों को ग्रेस देने का यह पहला मामला था। इस ग्रेस का नतीजा यह हुआ कि जहां 67 छात्रों को सर्वोत्तम 720 अंक मिले, वहीं एक ही सेंटर से 6-6 टॉपर हुए, 2 छात्रों को, जिनकी रैंक भी 68 और 69 आई, 718 और 719 नंबर दिए गए, जोकि नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से संभव नहीं हैं। आंसर सीट में गड़बड़ी से लेकर परीक्षा परिणाम में धांधली तक के आरोप सामने आए, विरोध प्रदर्शन से शुरू होकर मामला उच्चतम अदालत तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ग्रेस मार्क को निरस्त कर ग्रेस पाने वाले छात्रों को दुबारा परीक्षा देने का फैसला करने के बारे में कह कर, नीट-यूजी की साख जरूर बचाने की कोशिश की है, लेकिन एनटीए अभी भी सवालों के घेरे में है। जब से एनटीए गठित हुई है, उसकी कार्यप्रणाली संदिग्ध रही है। आखिर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय किस प्रकार से काम कर रहा है, उसे एनटीए के काम करने के तरीके के बारे में कैसे नहीं पता है, चुनिंदा अभ्यर्थियों को मनमाना ढंग से ग्रेस देने का फैसला किस आधार पर किया गया, प्रश्न पत्र देने में लेट होने पर समय बढ़ाया जा सकता था, पहले भी लेट होते रहे हैं, फिर ग्रेस नियम इसी बार क्यों बनाया गया, जबकि करीब 24 लाख छात्रा-छात्राओं ने मेडिकल में प्रवेश के लिए परीक्षा दी थी। एनटीए ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स देने के लिए क्या तरीका अपनाया? ग्रेस मार्क अब नहीं दिया जाएगा, पर एनटीए की कार्यप्रणाली पर दाग लग गए हैं। गेशक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सफाई दें कि एनटीए पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार है, इससे एनटीए का ग्रेस मार्क देने का फैसला सही नहीं हो जाएगा, फैसला सही होता तो रद क्यों करना पड़ता। अब ग्रेस पाए 1563 अभ्यर्थियों को फिर से 23 जून को परीक्षा देनी होगी, 30 जून को परिणाम आएगा, इनमें से जो परीक्षा नहीं देना चाहते, उसका परिणाम बिना ग्रेस अंक के जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी की समूची परीक्षा को रद नहीं किया है, कालेजों में नामांकन के लिए काउंसलिंग जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगना बनता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए, इसकी गरिमा पर दाग नहीं लगना चाहिए। ग्रेस मार्क देने के चलते हुई गड़बड़ी की जिम्मेदारी से एनटीए बच नहीं सकती।

समावेशी विकास पर देना होगा जोर

बजट उम्मीद
डॉ. ब्रजेश कुमार तिवारी

मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भारत वैश्विक स्तर पर 11वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, नई सरकार की नजर भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में ले जाने पर होगी। जल्द ही नया बजट पेश होगा ऐसे में सरकार को कुछ क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती महंगाई और बेरोज़गारी है। स्टार्टअप इंडिया योजना को और अधिक महत्व व बल देना होगा। देश के 85% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। ऐसे में हमें उन्हें ज्यादा समर्थन की ज़रूरत है। नई सरकार को कुछ श्रेणी में जीएसटी को भी युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है।

नई सरकार को भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना होगा। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भारत वैश्विक स्तर पर 11वीं से पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, नई सरकार की नजर भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में ले जाने पर होगी। जल्द ही नया बजट पेश होगा ऐसे में सरकार को कुछ क्षेत्र में जयदा ध्यान देने की ज़रूरत है।

मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती महंगाई और बेरोज़गारी है। तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोज़गारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। भारत में 94 प्रतिशत कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और देश का 35 फ़ीसदी उत्पादन इसी में होता है। कई सालों से असंगठित क्षेत्र में लगातार गिरावट आ रही है। आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस (एआई) का आगमन भारत में सेवा क्षेत्र के रोजगार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी में 50 फीसदी से अधिक का योगदान देता है। अगर बेरोजगारी रहेगी और आय नहीं बढ़ेगी तो चीजें कैसे खरीदी जाएंगी, इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग और निवेश का स्तर प्रभावित हुआ है तथा सरकार के लिए कर राजस्व कम हो गया है, इसलिए सबसे पहले सरकार को बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान देना होगा तभी जाकर समस्याएं कम होंगी। स्टार्टअप इंडिया योजना को और अधिक महत्व व बल देना होगा। आज देश के 85 प्रतिशत स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। ऐसे में हमें उन्हें ज्यादा समर्थन देने की ज़रूरत है। अग्निवीर सेना भर्ती की पुनर्विचार की ज़रूरत के साथ ही सरकारी भर्तियों में तेजी लानी होगी। इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र को हाशिए पर धकेलने वाली मौजूदा नीतियों में भी बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत होगी। आज भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,601 डॉलर है और 197 देशों में प्रति व्यक्ति इनकम के मामलों में भारत 142वें पायदान पर है। मुद्रास्फीति देश में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। वास्तव में किसी समस्या का समाधान यह स्वीकार करने से शुरू होता है कि समस्या मौजूद है और बेरोजगारी व महंगाई केवल राजनीतिक विषय नहीं हैं। पिछले कुछ समय से रसोई का बजट अनियंत्रित और असंतुलित हुआ है। मुद्रास्फीति में वृद्धि को मुख्य रूप से भोजन और ईंधन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आम लोगों पर महंगाई की मार के दूरगामी असर होते हैं, याद रहे महंगा भोजन स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है। आज हमें जीडीपी से ज्यादा ह्यूमन डेवलेपमेंट इंडेक्स पर फोकस करना चाहिए जिसमे शिक्षा व स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर है, जो चिंताजनक है। आज देश के सामने बड़ी चुनौतियाँ में अच्छी शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा हैं। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी ओर, उच्च शिक्षा के केवल कुछ संस्थान ही उन्नत अनुसंधान में शामिल हैं। भारत में शुरू से शिक्षा पर तुलनात्मक रूप से

सार्वजनिक व्यय कम रहा है। वहीं अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्यय-जीडीपी अनुपात में मात्र 0.7% है और 1.8% के विश्व औसत से भी बहुत कम है।

सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद आज भी अगर देश के 80 करोड़ लोग को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है तो निश्चित ही ये जनसंख्या अकुशल है। 'स्किल इंडिया' कई कारणों से अपेक्षित सफलता नहीं पा सका, जिसका मुख्य कारण प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे की कमी और निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी है। आज भी प्रशिक्षित, प्रमाणित और अंततः प्लेसमेंट पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच एक बड़ा बेमेल है। याद रहे एक कुशल और शिक्षित श्रम बल देश को उच्च विकास दर ले जाता है। कौशल व शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जहां निवेश के कई प्रभाव होते हैं। जब कार्यबल अधिक कुशल बनेगा, तब आर्थिक विकास की गति को बल मिलेगा, सामाजिक बुराइयां कम होंगी और महिलाएं भी सुरक्षित होंगी। परिणामस्वरूप देश का तेजी से विकास होगा। भारत चालू खाता घाटे से लगातार जूझता रहा है, जिसका अर्थ है कि भारत का आयात इसके निर्यात से अधिक है। पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, भारत दुनिया के निर्यात में बमुश्किल 1.6 प्रतिशत योगदान देता है। 'मेक इन इंडिया' अभियान का एक प्राथमिक उद्देश्य 2022 तक भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना था हालांकि पिछले 9 सालों में यह 14 से 16 प्रतिशत के बीच बना हुआ है। पीएम गति शक्ति, नेशनल सिंगल विंडो क्लीयरेंस, जीआईएस-मैप्ड लैंड बैंक, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना जैसी हालिया नीतियों के कार्यान्वयन से विनिर्माण क्षेत्र को लाभ होने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार के बीच भारत के लिए आर्थिक असमानता को पाटने की बड़ी चुनौती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्टः द इंडिया स्टोरी के अनुसार, भारत में सबसे अमीर 1 फीसद आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भले भारत की स्थिति पांचवीं हो गई हो, मगर विकास का हिस्सा बहुतों तक अभी पहुंच नहीं रहा है। पूंजीगत व्यय बढ़ने के बावजूद विश्व बैंक के अनुसार भारत का अवसंरचनात्मक अंतराल लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर के होने का अनुमान है। खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कृषि की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण बनी रहेगी। 2025 तक भारतीय एग्रीटेक बाजार की क्षमता 22 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें से अब तक बमुश्किल 2% पर ही हम पहुंच पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, कृषि आधारित औद्योगीकरण द्वारा संचालित होना चाहिए। सरकार के निवेश प्रोत्साहन पर निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया अपर्याप्त रही है, फिर भी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर सरकारी खर्च जारी रहना चाहिए वहीं नई सरकार को बॉण्ड बाज़ार, बीमा बाज़ार और पेंशन बाज़ार का विकास भी करना चाहिए।

नई सरकार को कुछ श्रेणी में जीएसटी को भी युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है। दूसरी तरफ, सरकार अगर चाहे तो कर राजस्व बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट कर, संपत्ति कर जैसे कर बढ़ा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ता क़र्ज़ भी ऐसी चुनौती है जिसका भविष्य में समाधान निकालना ही होगा। साइबर अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि ने आम लोगों को बहुत आर्थिक चोट पहुंचाई है। निजी निवेश में सुधार अर्थव्यवस्था में तरक्की का सबसे अहम कारक होगा और अगली सरकार को इस पर खास जोर देना चाहिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान करने का ऐलान किया है। सरकार को इस धन को शिक्षा व रोजगार निर्माण में लगाना चाहिए।

(लेखक जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

सारा संसार

गणेश टोंक गंगटोक में टीवी टॉवर के पास एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर है जिसकी गिनती भारत के प्रमुख गणेश मंदिर में की जाती है। हरी-भरी घाटियों और माउंट खंगचेंदजोंगा के सुंदर दृश्यों को प्रस्तुत करता हुआ यह मंदिर पर्यटकों और श्रद्धालुओं सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

श्रावण मास का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व

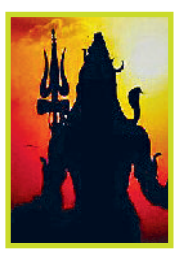

संकलित
दर्शन

भारतीय मनीषियों ने काल गणना के प्रसंग में संस्कृत के 12 मासों को वैज्ञानिकता की पृष्ठभूमि में निर्धारित किया है, जिसमें श्रावण मास चैत्रादि मासों के क्रम में पांचवें मास के क्रम में स्वीकार किया है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से श्रवण नक्षत्र में अण प्रत्यय के योग से श्रावण शब्द बनता है, जिसका अर्थ है श्रवण से संबंधित। ध्यातव्य है कि ज्योतिष शास्त्र में श्रवण नक्षत्र का स्वामी भगवान विष्णु को माना गया है। जिस महीने में श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा होती है, उसे ही श्रावण मास कहते हैं। कुछ विद्वानों के मत से सृष्टि का प्रारंभ जल से हुआ है और सावन मास जल के लिए जाना जाता है। अतः यह सृष्टि का पहला महीना है। वेद कहते हैं- 'अप एव ससर्जादौ' अर्थात विधाता ने सर्वप्रथम जल का निर्माण किया। महाकवि कालिदास जी कहते हैं- या सृष्टिः स्रष्टुराद्या अर्थात ब्रह्मा की पहली सृष्टि जल ही है। सावन मास में सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। कर्क राशि का सूर्य ही सावन मास है। इस महीने भगवान विष्णु जल का आश्रय लेकर क्षीरसागर में शयन करने चले जाते हैं। जल वृष्टि अधिक होने से पृथ्वी में कणों के गर्भांकुर फूट पड़ते हैं। गर्मी का ताप शांत हो जाता है। हृदयहारी वायु बहने लगती है। सभी चराचर जड़ चेतन जीव-जंतु हर्षित हो जाते हैं। प्रकृति का वातावरण सुरम्य हो जाता है। संपूर्ण जीव-जगत उल्लास से भर जाता है। ऊष्णता से संतप्त प्राणियों को शरण देने वाला श्रावण मास का शुभागमन परम आह्लाद देने वाला हो जाता है।

स्वयं के धर्म की चिंता

संकलित
प्रेरणा

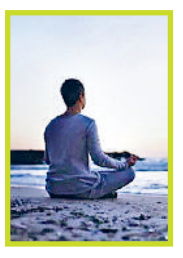

एक आदमी तालाब के किनारे बैठ कर कुछ सोच रहा था। तभी उसने पानी में किसी के डूबने की आवाज सुनी और उसने तालाब की तरफ देखा तो उसे एक बिच्छू तालाब में डूबता दिखाई दिया। अचानक ही वह आदमी उठा और तालाब में कूद गया। उस बिच्छु को बचाने के लिए उसने उसे पकड़ लिया और तालाब के बाहर लाने लगा। इससे घबराकर बिच्छू ने उस आदमी को डंक मारा। आदमी का हाथ खून से भर गया वो जोर-जोर से चिल्लाने लगा, उसका हाथ खुल गया और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। आदमी फिर उसके पीछे गया। उसने बिच्छु को पकड़ा। लेकिन बिच्छू ने फिर से उसे काट लिया। यह बार-बार होता रहा। यह पूरी घटना दूर बैठा एक आदमी देख रहा था। वो उस आदमी के पास आया और बोला - अरे भाई ! वह बिच्छू तुम्हे बार-बार काट रहा है। तुम उसे बचाना चाहते हो, वो तुम्हे ही डंक मार रहा है। तुम उसे जाने क्यूँ नहीं देते? मर रहा हैं अपनी मौत, तुम क्यूँ अपना खून बहा रहे हो? तब उस आदमी ने उत्तर दिया - भाई ! डंक मरना तो बिच्छू की प्रकृति है। वह वही कर रहा है लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ, और मेरा धर्म है दूसरों की सेवा करना और मुसीबत में उनका साथ देना। अतः बिच्छू अपना धर्म निभा रहा हैं और मैं मेरा।

विश्व रक्तदाता दिवस

अरुण कुमार कैहरबा

मानवता के अनूठे सिपाही रक्तदाता

खून के रिश्तों की सीमाएं जाति, धर्म-संप्रदायों की श्रेष्ठता को जन्म देते हुए अनेक संकीर्णताओं को जन्म देती हैं। इस श्रेष्ठता ग्रंथि का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। फिर भी इसके कारण इतिहास में अनेक युद्ध हुए हैं। हिटलर जैसे कट्टर लोगों ने फासीवाद जैसे क्रूर विचार को आगे बढ़ाते हुए लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरों का खून खून बहाने की भावना के विपरीत रक्तदान अहिंसा और सत्य के विचार को आगे बढ़ाता है। रक्तदाता दुनिया को बांटने-तोड़ने की बजाय जोड़ने का संदेश देता है। मानवता के अनूठे सिपाही बनकर रक्तदाता रक्त नालियों या सड़कों पर बहने की बजाय मनुष्य की नाड़ियों में बहाने का संदेश देते हैं। रक्तदान को बढ़ावा देने और रक्तदाताओं का सम्मान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 में हर वर्ष 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। सवाल यह है कि आखिर रक्तदाता दिवस के लिए यही दिन क्यों चुना गया। दरअसल यह दिन प्रसिद्ध जीव विज्ञानी एवं भौतिकीविद कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्मदिन (14 जून, 1868) है। लैंडस्टाइनर ने रक्त का ए, बी, एबी और ओ अलग-अलग रक्त समूहों में वर्गीकरण कर चिकित्सा विज्ञान में अहम योगदान दिया था। शरीर विज्ञान में उनके योगदान के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए यह दिन रक्तदाता दिवस के रूप में चुना गया। मकसद यही था कि रक्त का व्यापार ना हो। इसके साथ ही स्वास्थ्य संगठन ने शत-प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान नीति की नींव डाली, लेकिन अब तक लगभग 49 देशों ने ही इस पर अमल किया है। तंजानिया जैसे देश में 80 प्रतिशत रक्तदाता पैसे नहीं लेते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ही भारत में प्रतिवर्ष 1करोड़ यूनिट रक्त की ज़रूरत होती है, लेकिन उपलब्ध 75 लाख यूनिट ही हो पाता है। करीब 25 लाख यूनिट रक्त के अभाव में हर साल कितने ही मरीज दम तोड़ देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में हर साल 3 लाख 50 हजार रक्त यूनिट की आवश्यकता रहती है, लेकिन स्वैच्छिक रक्तदाताओं से इसका महज 30 फीसदी ही जुट पाता है। जो हाल दिल्ली का है वही शेष भारत का है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कुल रक्तदान का केवल 59 फीसदी रक्तदान स्वैच्छिक होता है। भारत में अनेक शख्सियतें हैं, जो रक्तदान की अलख जगा रही हैं। भारतीय सेना में ऑनरेरी कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए हरियाणा के सुरेश सैनी 144 बार रक्तदान कर चुके हैं। यही नहीं उन्होंने 97 बार प्लेटलेट और एक बार प्लाज्मा भी दान किया है। रक्तदान, प्लेटलेट और प्लाज्मा दान के मामले में 242 का आंकड़ा छूने वालों में वे देशभर के गिने-चुने नामों में से एक हैं। उन्होंने अपनी बेटी के विवाह में कन्यादान करने से पहले रक्तदान की रस्म अदा की। पुलिस अधिकारी डॉ. अशोक वर्मा, रैडक्रॉस करनाल में जिला प्रशिक्षण अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए एमसी धीमान भी ऐसे ही व्यक्ति हैं, जो खुद रक्तदान करते हुए भी रक्त की जरूरत पूरी करने में लोगों का स्वैच्छिक सहयोग करते हैं। संकट के समय तो रक्तदान की अहमियत और बढ़ जाती है। चाहे कोरोना के संकट का समय है या युद्ध या कोई अन्य प्राकृतिक एवं मानवीय आपदा। उस समय रक्तदाता की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। हम सभी को मिलजुल कर विश्व शांति, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए रक्तदान को प्रेरित करना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जल संकट

नई दिल्ली में चल रहे जल संकट के बीच विवेकानंद कैंप इलाके में एक महिला टैंकर से पीने का पानी भरकर ले जाती हुई। इन दिनों गर्मी में दिल्ली के अधिकांश इलाकों में पानी संकट चल रहा है।

आज की पाती

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की आग कब बुझेगी?

हाल ही में जम्मू के रियासी जिला में आतंकियों ने श्रद्धालुओं से भरी बस पर जो कायरतापूर्ण हमला किया, वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इससे पता चलता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। किसी भी धर्म में हिंसा का जिक्र नहीं है। इस आतंकी हमले पर कुछ बुद्धिजीवी और अन्य लोग यह तर्क भी दे रहे हैं कि यह हमला तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इस हमले पर राजनीति की रोटियां सेंकने की भी कोशिश कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। सवाल यह कि इस राज्य में आतंकवाद की आग कब बुझेगी?

-सुरेश देवांगन, जगदलपुर

करंट अफेयर

अर्जेंटीना की सीनेट ने दी प्रमुख सुधारों को मंजूरी

अर्जेंटीना की सीनेट ने राष्ट्रपति जेवियर मिलेई द्वारा प्रस्तावित प्रमुख राज्य सुधार और कर विधेयकों को मंजूरी दे दी है, जिससे उदारवादी नेता को क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के अपने वादों को पूरा करने के प्रयासों में प्रारंभिक विधायी जीत मिली है। सांसदों ने 11 घंटे की चर्चा के बाद बुधवार देर रात 36 के मुकाबले 37 मतों से सुधार विधेयक को मंजूरी दे दी। इस कानून के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया और अर्जेंटीना की कांग्रेस (संसद) में विधेयकों को लेकर पक्ष और विरोध में समान मत पड़ने के बाद उप राष्ट्रपति और सीनेट की सभापति विक्टोरिया विलारुएल ने मेइली के एजेंडे के पक्ष में निर्णायक मतदान किया। यह कानून ऊर्जा, पेंशन, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार प्रदान करता है। इसमें कई ऐसे उपाय शामिल हैं जिन्हें विवादास्पद माना जाता है, जिसमें विदेशी निवेशकों के लिए एक उदार प्रोत्साहन योजना, अघोषित संपत्ति वाले लोगों के लिए कर माफी और अर्जेंटीना की कुछ सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के निजीकरण की योजना शामिल है। संसद के उच्च सदन सीनेट के सदस्यों को इस विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद को भी स्वीकृति देनी होगी।

ऑफ बीट

ओजान परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन घट रहे

1985 में ओजोन परत में छेद की खोज के बाद से देशों ने इसकी बहाली में सहायता के लिए संधियों पर सहमति व्यक्त की है और उनमें संशोधन किया है। इनमें सबसे उल्लेखनीय ओजोन परत को ख़राब करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिसे व्यापक रूप से अब तक का सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अनुमोदित और पहली बार 1987 में अपनाए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य वायुमंडल में ओजोन-घटाने वाले पदार्थों की रिलीज को कम करना था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) हैं। 1989 से शुरू होकर, प्रोटोकॉल ने 2010 तक सीएफसी के वैश्विक उत्पादन को चरणबद्ध कर दिया और रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और इंसुलेटिंग फोम जैसे उपकरणों में उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। क्रमबद्ध रूप से इन रसायनों को हटाने से कम स्थापित अर्थव्यवस्था वाले देशों को विकल्पों में बदलाव के लिए समय दिया और उन्हें प्रोटोकॉल के नियमों का अनुपालन करने में मदद करने के लिए धन उपलब्ध कराया। आज, रेफ्रिजरेटर और एयरोसोल के डिब्बे में प्रोपेन जैसी गैसें होती हैं।

ट्रेंड

पुनः कार्यभार संभाला

मैंने रक्षा मंत्रालय का कार्यभार पुनः ग्रहण कर लिया। रक्षा मंत्रालय रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करना जारी रखेगा। हमारे सशस्त्र बल भारत की बाहरी सुरक्षा बनाए रखने में सराहनीय कार्य कर रहे हैं।

-राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री

सावधानी के साथ तैनाती

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ी सावधानी के साथ तैनात किया जा रहा है। सरकारों, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज को मिलकर एआई सुरक्षा के लिए नियम विकसित करने चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।

-एंटोनियो गुतरेस, यूएन महासचिव

यही खेल चल रहा

उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग से भर्तियों पर विचार किया जा रहा है। जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजा गया था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। भाजपा ने अग्निपथ स्कीम लाकर सेना को कमजोर किया। अब यूपी पुलिस में यही खेल चल रहा है।

-प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव

स्टारशिप सर्वाधिक शक्ति वाली

स्टारशिप अब तक बनाई गई सबसे अधिक शक्ति वाली उड़ने वाली वस्तु है। वर्तमान में सैटर्न वी के दोगुने से अधिक जोर और, भविष्य के उन्नयन के साथ, तीन गुना जोर (10,000 टन बल)।

-एलन मस्क, उद्योगपति

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

बराबरी का हक देने से ही मिटेगी असमानता

आजादी के करीब 77 साल बाद भी यदि हम लैंगिक समानता के मामले में दुनिया में 77वें स्थान पर भी नहीं आ पाए हैं तो मानना पड़ेगा कि तमाम वादों और दावों के बावजूद इस मामले में रफ्तार अभी बहुत धीमी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली भी है और हमें सीख देने वाली भी। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत में आर्थिक लैंगिक समानता का स्तर बहुत कम है। साफ शब्दों कहा जाए तो 146 देशों में हम 129वें नंबर पर ठहरते हैं। भारत में औसतन पुरुषों की 100 रुपए कमाई के मुकाबले महिलाएं 39.80 रुपए ही कमाती हैं।

कमाई के मामले में इस पिछड़ेपन की बड़ी वजह महिलाओं को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलना भी रहा है। भारत में जिस कार्य के लिए पुरुषों को 100 रुपए मिलते हैं, उसी काम के लिए महिलाओं को केवल 52 रुपए मिलते हैं। खास बात यह कि आर्थिक लैंगिक समानता के मामले में हम पिछले साल 127वें नंबर पर थे लेकिन अब 129वें स्थान पर जा पहुंचे हैं।

इस बात में कोई संदेह नहीं कि देश में महिलाओं के खाते में अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हैं। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि महिलाओं को उनका हक दिलाने में जिस गति से काम किया जाना था, हो नहीं पाया है। फोरम की रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो जाती है कि महिला उत्थान के तमाम दावों के बावजूद देश में यह असमानता दुनिया में हमें सवालों के कठघरे में खड़ा तो करती ही है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ऐसा पुरुष प्रधान मानसिकता के कारण है? या फिर सरकारें इस दिशा में ठीक से काम ही नहीं कर पा रहीं? देश की महिलाएं आज राजनीति से लेकर प्रशासनिक उच्च पदों पर काबिज हैं। महिला संगठन भी अपने-अपने तरीके से असमानता की इस खाई को दूर करने के लिए अनेक अभियान भी चल रहे हैं। इसके बावजूद सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर हम पिछड़ क्यों रहे हैं? क्या सरकारी योजनाओं में खामी है या फिर योजनाओं में जान-बूझकर अड़ंगा लगाया जा रहा है? वर्ष 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में आने के हमारे लक्ष्य में यह असमानता बाधक हो सकती है।

इस बाधा को दूर करने के लिए सबसे पहला काम महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़ाने का होना चाहिए। चिंता इस बात की ही है कि आज भी आधी आबादी की सत्ता में भागीदारी 15 फीसदी से आगे नहीं बढ़ पा रही। जिस दिन समुचित भागीदारी हो जाएगी, असमानता दूर होने की प्रक्रिया स्वतः ही दूर हो जाएगी। जरूरत इस दिशा में ईमानदारी से काम आगे बढ़ाने की है।

ब्रिटेन में चुनाव: करीब 100 सांसदों ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है जिनमें से अधिकांश कंजर्वेटिव पार्टी के हैं

समय से पहले चुनाव के दांव पर विश्व की निगाह

लंदन से 'पत्रिका' के पाठकों के लिए

'अमरीका बनाम अमरीका' पुस्तक के लेखक **द्रोण यादव** का ब्रिटेन के राजनीतिक परिदृश्य का एक विश्लेषण

@patrika.com

यह वर्ष दुनियाभर में राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे साल में करीब 70 देशों में चुनाव हो रहे हैं। भारत और रूस में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ब्रिटेन और अमरीका में चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं। 2024 का अंत होने के साथ दुनिया की करीब 25 प्रतिशत आबादी पुनः अपना प्रतिनिधि चुन चुकी होगी जो दुनिया की नई विश्वव्यवस्था को दिशा देगा। भारत में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है और गठबंधन सरकार बनी है। इससे भारत सरकार की विदेश नीति पर गठबंधन की अन्य पार्टियों की विचारधारा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

अब भारत के बाद अगला बड़ा चुनाव ब्रिटेन का है जो 4 जुलाई को होना है, हालांकि यह चुनाव साल के अंत में प्रस्तावित था लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने समय से पहले चुनावों की घोषणा कर सबको चौंका दिया। ब्रिटेन का इस बार का चुनाव केवल इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ब्रिटेन एक ताकतवर देश होने के नाते वैश्विक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण दखल रखता है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह है कि अगली ब्रिटिश सरकार की अंतरराष्ट्रीय नीतियां संपूर्ण यूरोप सहित एशिया व अमरीका को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। ब्रिटेन के चुनावों में देश की दो मुख्य पार्टियों-कंजर्वेटिव और लेबर में सीधी टक्कर है। एक ओर सत्तापक्ष की पार्टी कंजर्वेटिव है जिसके नेता प्रधानमंत्री सुनक के सामने यह चुनौती है कि 2010 से ब्रिटेन में सत्तारूढ़ अपनी पार्टी का शासन कैसे कायम रखें। दूसरी ओर लेबर पार्टी है जिसके नेता कीअर स्टार्मर लंबे समय से सत्ता से बाहर अपनी पार्टी को सत्ता दर्शन करवाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सुनक के चुनावों की घोषणा करने से पहले उनकी पार्टी कंजर्वेटिव की लोकप्रियता लगातार घट रही थी और यह आम धारणा बन चुकी थी कि चुनाव आते-आते लेबर पार्टी का राज आना लगभग तय सा ही हो जाएगा। एक आम धारणा यह भी हो गई है कि कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन के हालात को संभालने में सक्षम नहीं है। 2019 में जब कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुमत हासिल किया तब सबसे मुख्य मुद्दा ब्रेक्सिट था, जिसके चलते ब्रिटेन ने खुद को यूरोपीय संघ से अलग कर लिया था और उस परिस्थिति में ब्रिटेन की जनता ने बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी को देश संभालने योग्य समझा। इस बार के चुनाव के मुख्य मुद्दों में ब्रेक्सिट नहीं है। अब महंगाई, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था व प्रवास जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। 'यू-गॉव' नामक एक संस्थान का सर्वे बताता है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए ब्रिटेन में प्रवासियों का मुद्दा और पेंशन महत्त्वपूर्ण है, वहीं नौजवानों के लिए महंगाई, हाउसिंग और पर्यावरण आदि मुद्दे ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। यह देखना रोचक होगा कि ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी वापस ब्रिटेन की जनता का भरोसा जीतने में सफल होती है या नहीं। आज के हालात में कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी से पिछड़ी हुई है और उसके खिलाफ पिछले 14 साल में तैयार हुई विरोधी लहर का लेबर पार्टी भरपूर लाभ उठा रही है, एक ओर जहां लेबर पार्टी कंजर्वेटिव्स को आर्थिक हालात, बेरोजगारी, प्रवासन, स्वास्थ्य व पर्यावरण जैसे मुद्दों पर घेर रही है। वहीं दूसरी ओर कंजर्वेटिव पार्टी अपनी अंदर की राजनीतिक कलह से भी ग्रसित है। प्रधानमंत्री सुनक के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। यह कंजर्वेटिव पार्टी की आंतरिक अस्थिरता का ही नतीजा है कि 2019 के प्रचंड बहुमत के बावजूद दो प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और तीसरे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को अपनी कुर्सी बचाने के लिए तय तिथि से करीब 6 माह पहले ही चुनावों की घोषणा करनी पड़ी।

> यह कंजर्वेटिव पार्टी की आंतरिक अस्थिरता का ही नतीजा है कि प्रचंड बहुमत के बावजूद दो प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और तीसरे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने समय से पहले ही चुनावों की घोषणा की।

सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी की अस्थिरता के पीछे ब्रिटेन की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता एक बड़ा कारण है। ब्रिटेन हाल ही में बढ़ती महंगाई दर और बेरोजगारी से जूझ रहा था, उसी समय ब्रिटेन के राजनीतिक हालात भी गंभीर हो गए। सांसदों पर हमले की घटनाएं सामने आने लगीं। करीब 100 सांसदों ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है जिनमें से अधिकांश कंजर्वेटिव पार्टी से हैं और इस फेहरिस्त में पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा भी शामिल हैं। हालांकि सांसदों का चुनाव न लड़ने का फैसला नया नहीं है। 2010 में लेबर पार्टी के 13 वर्ष के शासन के बाद करीब 149 सांसदों ने ऐसा फ़ैसला किया था, जिनमें से करीब 100 लेबर पार्टी के थे। इस तरह के फैसले का कारण या तो यह होता है कि आने वाले चुनाव में उनको हार नजर आ रही होती है या फिर वे राजनीति त्याग कर किसी नए पेशे को अपनाना चाहते हैं। अभी के हालात में लगता है कि हमलों का डर भी एक कारण है। इसका एक उदाहरण कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद माइक फरीयर हैं, जिन्होंने तब चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया जब उनके संसदीय क्षेत्र के दफ्तर पर हमला हुआ।

कंजर्वेटिव पार्टी की गिरती लोकप्रियता को थामने के लिए समय से पहले चुनाव करवाना प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का एक अच्छा राजनीतिक दांव जरूर है, लेकिन यह दांव कितना सफल होगा इसका फैसला होना अभी शेष है। चुनाव की घोषणा होने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी की लोकप्रियता में करीब 3 अंक का सुधार होना इस बात का संकेत है कि कंजर्वेटिव पार्टी के हाथ से निकल चुके चुनाव को सुनक और उनकी पार्टी अब भी संभाल सकती है। दूसरी ओर यह भी नकारा नहीं जा सकता कि लेबर पार्टी के नेता कीअर स्टार्मर ने अपनी पार्टी के पक्ष में एक बड़ी लहर पैदा की है जिससे पार पाना कंजर्वेटिव पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा।

फैक्ट फ्रंट

अमरीका के राष्ट्रीय ध्वज को मिली मंजूरी

महाद्वीपीय कांग्रेस ने 14 जून 1777 को सितारों और पट्टियों को संयुक्त राज्य अमरीका के प्रथम राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मंजूरी दी। कांग्रेस की एक बैठक में देश के लिए 13 लाल और सफेद धारियों वाले नए झंडे का स्वरूप निर्धारित किया। इस दिन को 1885 से अमरीका में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राज्य के प्रतीक के तौर पर झंडे की नीली सतह पर 13 सफेद तारे अंकित थे, जिनकी संख्या में बाद में अमरीकी संघ में नए राज्य जुड़ने के साथ बदलती रही।

जीवन मंत्र: गीता में हमारे जीवन के सारे मुश्किल सवालों के जवाब

क्रोध को काबू में रखें, लोगों को माफ करना सीखें और आगे बढ़ें

अमितासन दास
अध्यक्ष, हरे कृष्णा मूवमेंट, जयपुर और मुंबई
@patrika.com

मुस्कुराना कौन नहीं चाहता, लेकिन न चाहते हुए भी क्रोध का आवेग हम पर हावी हो ही जाता है। प्रश्न यह है कि आखिर हमे गुस्सा आता क्यों है? दरअसल, यह मानव स्वभाव है। असल में हमेशा यही इच्छा होती है कि जीवन में जैसा हम चाहें वैसा ही हो। कुछ भी हमारी इच्छा के अनुसार न हो तो हम परेशान हो जाते हैं और हमें गुस्सा आने लगता है। हम दूसरों से एक तरह के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और जब वह व्यवहार हमें नहीं मिलता तो हम क्रोधित हो जाते हैं, अगर हमारी स्थितियां हमारे अनकूल नहीं होतीं तो भी हमें क्रोध आने लगता है और ऐसा करते-करते धीरे-धीरे हमारे जीवन में क्रोध और कुंठा का ग्राफ बढ़ता ही जाता है।

देखा गया है कि हम गुस्से में किसी को कुछ कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए और फिर बाद में पछतावा होता है। सभी जातने हैं कि क्रोध से नुकसान होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं और हमें गुस्सा आ ही जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमें गुस्सा आता ही क्यों है और यह हमारा कितना नुकसान करता है? इसका जवाब आपको श्रीमद्भगवद गीता में मिलता है। असल में गीता में हमारे जीवन के सारे मुश्किल सवालों के जवाब हैं, बस आप अर्जुन की जगह अपने आप को रखिए और देखिए कृष्ण कैसे आपको हर मुश्किल का समाधान देते हैं। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? कृष्ण, अर्जुन को कारण बताते हैं-

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्।।

रजोगुण में मानव को सांसारिक विषय भोगों की कामना होती है। यह भोग कुछ भी हो सकते हैं जैसे धन की इच्छा, शारीरिक लालसाएं, प्रतिष्ठा की अभिलाषा इत्यादि। और जब ये कामनाएं पूरी होती हैं तो फिर लोभ उत्पन्न होता है और यह बढ़ता ही जाता है, लेकिन जब इसकी संतुष्टि नहीं होती तो क्रोध का आवेग उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीन विकार ही नरक के द्वार हैं और इनसे ग्रसित होकर ही मनुष्य पाप करता है। सारी बुराइयों की जड़ ये तीन विकार ही होते हैं।

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते।
सङ्गात् संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।।

हमें जब भी गुस्सा आता है तो उसका वेग बहुत ही तीव्र होता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए आप कोशिश करें थोड़ी देर के लिए उस जगह से बाहर निकल जाएं और फिर जब यह आवेग रुक जाए, फिर शांत और ठंडे दिमाग से उस परिस्थिति या समस्या का समाधान सोचें। हमे 'रियेक्ट' करने के बजाय 'रिस्पोंड' करना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप गुस्से को नियंत्रण में रखें न कि गुस्सा आप को। अपने मन को शांत करने के लिए आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं, 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे'। एक बड़े काम की बात आपसे शेयर करता हूं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बड़ी मदद करेगी, कभी भी गुस्से के आवेग में ई-मेल का जवाब मत दीजिए। जब आप थोडा बेहतर महसूस करें तब ही ठंडे दिमाग से ई-मेल का उत्तर दें। लोगों को माफ करना सीखें और आगे बढ़ें, इससे आप अपने अंदर असीम शांति और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। यही ऊर्जा आपको जीवन में सफल बनाएगी और ईश्वर के और करीब ले जाएगी।

> गुस्से को हावी न होने दें, उस पर नियंत्रण रखें। गुस्सा आने पर थोड़ी देर के लिए उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं।

विकसित भारत का लक्ष्य: बढ़ती आर्थिक असमानता को लेकर चिंता बढ़ी

समृद्धि के युग की शुरुआत के लिए एकजुट होकर करें काम

जी.एन.बाजपेयी
सेबी और एलआइसी के पूर्व अध्यक्ष
(बिलियन प्रेस)
@patrika.com

लोकसभा चुनाव-2024 के नतीजे काफी चकित कर देने वाले हैं। अब नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ हो गई है। नई सरकार के कामकाज के एजेंडे पर ध्यान से नजर रखी जा रही है। मुझे अपनी उस तीर्थयात्रा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीन मंजिला सेल्युलर जेल, का स्मरण हो आता है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित यह तीन मंजिला इमारत स्वतंत्रता सेनानियों पर अमानवीय नृशंस अत्याचारों की मूक गवाह है। इसे अब राष्ट्र को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में समर्पित किया गया है। फांसी का इंतजार कर रहे कैदियों ने जेल की दीवार पर अपने साथियों के लिए लिखा है, 'मैंने अपना काम कर दिया है और अब आपकी बारी है।' अब हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम लोगों को आर्थिक गरीबी और कष्टों से मुक्ति दिलाने तथा समृद्धि के युग की शुरुआत करने के लिए एकजुट होकर काम करें।

मोदी 3.0 के पांच साल के इस कार्यकाल में -भारत को पूर्ण विकसित समाज के रूप में देखने और सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार से लड़ने- जैसे महत्वपूर्ण विचारों को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। देश को आजादी दिलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का संदेश तभी वास्तविकता में बदलेगा, जब भारत की प्रगति का लाभ अंतिम छोर पर खड़े सबसे कमजोर और सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचेगा। यह केवल तभी संभव है जब अगले दो दशकों के लिए न्यूनतम वार्षिक औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7 फीसदी से अधिक हो। हालांकि कहना जितना आसान है, करना उतना नहीं। पारंपरिक मानदंडों में, जीडीपी में वृद्धि में मुख्य रूप से उत्पादन के तीन कारकों की भूमिका होती है-भूमि, श्रम और पूंजी की उपलब्धता। मौजूदा भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि और वैश्विक आर्थिक माहौल में जीडीपी में वृद्धि के लिए लोकप्रिय समर्थन जुटाने, दूरदर्शी प्रबंधन और इष्टतम प्रयास तीनों के समन्वय की आवश्यकता है।

बुनियादी ढांचे के निर्माण और औद्योगीकरण में भूमि की उपलब्धता एक गंभीर बाधा बनी हुई है। भूमि अधिग्रहण का अक्सर नकारात्मक असर भी पड़ता है। जैसाकि अभी अयोध्या में देखा गया। माना जाता है कि चुनाव में फैजाबाद में भाजपा की हार का एक कारण यह भी है। भूमि अधिग्रहण के लिए हमें अधिक मानवीय तरीके अपनाने की जरूरत होगी। जीडीपी की वृद्धि दर बढ़ाने में कृषि क्षेत्र भी एक बड़ा मुद्दा है। विनिर्माण और निर्माण जैसे अन्य क्षेत्रों जितना ही यदि कृषि क्षेत्र का भी योगदान होता तो 2024 की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 10 फीसदी से अधिक होती। कहने की जरूरत नहीं है कि भूमि, श्रम और कृषि भावनात्मक मुद्दे हैं जिससे लोग गहराई से जुड़े हैं। भारत के जीवन्त और बहुदलीय लोकतंत्र में, भावनात्मक मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बनाना कठिन काम है। इसके लिए अटूट धैर्य, हितों और विचारों के समायोजन की आवश्यकता होती है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए न्यायपालिका में भी बड़े सुधारों की जरूरत है। बढ़ती आर्थिक असमानता को लेकर चिन्ताएं बढ़ रही हैं। उच्च जीडीपी विकास दर गरीबों के जीवन में उल्लास नहीं लाती है। आर्थिक असमानताएं 'समान अवसर' की कमी से उत्पन्न होती हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अन्य बातों के साथ-साथ 'अवसरों की समानता' की बात भी कही गई है। असमानता असंतुलित आर्थिक विकास का नतीजा है। इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

> आर्थिक असमानता बड़ी समस्या है। यह असंतुलित विकास का नतीजा है। समान अवसर की कमी भी इसका कारण है।

प्रसंगवश

सोसायटी की नाव में सवारी बदहाली के लिए जिम्मेदार

हालत यह है कि अधिकांश कॉलेज किराए के भवनों व दूसरी सरकारी इमारतों में चल रहे हैं

नई शिक्षा नीति के मापदण्डों पर खरे नहीं उतरने वाले कॉलेजों की समीक्षा का काम अब इसे लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय समिति करेगी। जाहिर है इन कॉलेजों की घोषणा करते समय इस बात की चिंता नहीं की गई कि जहां कॉलेज खोला जा रहा है, वहां विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या हो पाएगी या नहीं। कॉलेज भवन और अन्य भौतिक सुविधाओं के बारे में सोचना तो इसके आगे की बात थी। कोढ़ में खाज यह कि वाहवाही लूटने के लिए पिछले सालों में बजट दर बजट कॉलेज खोलकर इनका संचालन राजस्थान कॉलेज एज्युकेशन सोसायटी (राजसेस) के जिम्मे कर दिया गया। ऐसी-ऐसी जगहों पर कॉलेज खोल दिए गए जहां आसपास के गांवों को मिलाकर पचास का नामांकन भी नहीं हो सका। होना तो यह था कि जिन जनप्रतिनिधियों के दबाव में ये कॉलेज खुले वे जनप्रतिनिधि यहां छात्र-छात्राओं का दाखिला कराने में भी ताकत लगाते। हैरत की बात यह है कि बजट सरकार का, जमीन सरकार की और छात्रवृत्ति का भुगतान भी सरकार ही कर रही है पर कॉलेजों का संचालन खुद करने के बजाय उनको सोसायटी के भरोसे छोड़ दिया गया। राजसेस के माध्यम से संचालित होने वाले इन कॉलेजों में चहेतों को अस्थाई शिक्षकों के रूप में उपकृत करने का रास्ता भी खुल गया। इनमें अधिकांश कॉलेज किराए के भवनों, दूसरे सरकारी शिक्षण संस्थाओं व अन्य इमारतों में चल रहे हैं।

वर्ष 2019 में पिछली सरकार ने सबसे पहले बीस कॉलेज बिना जरूरी संसाधनों के खोल दिए। लम्बी लड़ाई के बाद बजट जारी हुआ। इसके बाद सरकार ने वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक ऐसे कुल मिलाकर तीन सौ से ज्यादा कॉलेज खोल दिए। सोसायटी के जरिए इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित करने के खराब अनुभवों से सबक लिया जाता तो कॉलेजों के रिव्यू करने की नौबत ही नहीं आती। सीधा सा सवाल है कि जब तीस हजार से ज्यादा फीस लेने वाले 60 इंजीनियरिंग कॉलेजों को ही सोसायटी नहीं चला पाई तो महज 1200 रुपए प्रति छात्र फीस लेने वाले ये कॉलेज कैसे चल पाएंगे? अच्छा तो यह होता कि सरकार छात्र संख्या का अनुमान लगाकर पहले संसाधन जुटाती और इसके बाद कॉलेज खोलने का ऐलान करती। कॉलेज ही नहीं स्कूल-अस्पताल खोलने में भी सरकारों का ऐसा ही रवैया सामने आता है जो उचित नहीं कहा जा सकता।

- चन्द्रप्रकाश जोशी
cp.joshi@in.patrika.com

बौद्ध भिक्षुओं की हुई परीक्षा: पालि भाषा में पारंगत होने की लागी लगन

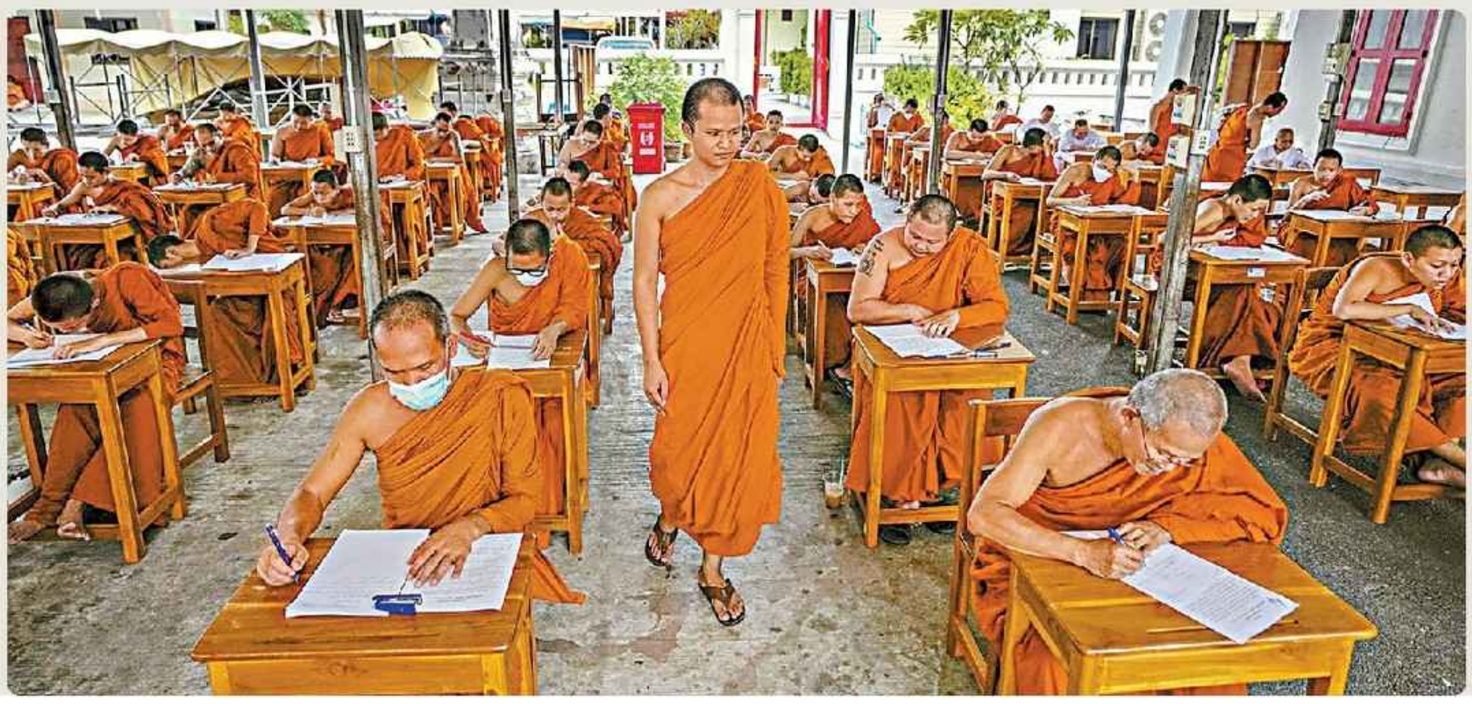

थाईलैंड के वाट मोलिलोक्यारम में पालि भाषा की परीक्षा देते भिक्षुओं को देखते हुए एक बौद्ध भिक्षु शिक्षक। बौद्ध भिक्षुओं को पालि भाषा अवश्य आनी चाहिए क्योंकि देश के थेरवाद बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पालि भाषा में हैं और भिक्षु धार्मिक समारोहों में पालि में मंत्रोच्चार करते हैं। पालि भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में एक है जिसे भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात लिपि ब्राह्मी में लिखा जाता था। इसका प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेखों और स्तंभों से प्राप्त होता है। बुद्धकाल में पालि भाषा भारत के जनमानस की भाषा थी। कुछ इतिहासकार पालि को संस्कृत का अपभ्रंश मानते हैं। मूल पालि साहित्य तीन भागों में विभक्त है, जिन्हें पिटक कहा गया है - 'विनयपिटक', 'सुत्तपिटक' और 'अभिधम्मपिटक'। पालि के इन तीन पिटकों में भगवान बुद्ध के विचारों और उपदेशों का एक विशेष शैली में संकलन किया गया है। इन तीनों पिटकों में परस्पर तारतम्य नजर आता है।

आपकी बात

परीक्षाओं को लेकर सवाल

ऐसा लगता है कि सरकार, परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के मामले में गंभीर नहीं है। आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यह एक गंभीर मामला है। परीक्षाओं की विश्वसनीयता जरूरी है, ताकि युवाओं में उत्साह बना रहे।

-आलोक वालिम्बे, बिलासपुर,छत्तीसगढ़

आज का सवाल

आग लगने की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल क्यों उठते रहते हैं?' ऑनलाइन भी देखें।
इसे स्कैन करें
rb.gy/cbhoqk

दीनता उस मानसिक दुर्बलता को कहते हैं, जो मनुष्य को दूसरों की दया पर जीने का प्रलोभन देती है।

– हजारीप्रसाद द्विवेदी

लालच की आग

कुवैत के मंगफ क्षेत्र में अग्निकांड के बाद खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय मजदूरों की बदहाली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मध्य पूर्व के इस देश में रोजगार की तलाश में गए 40 से अधिक भारतीय मजदूरों की मौत की घटना स्तब्ध करने वाली है। अग्निकांड के बाद भारत एवं कुवैत सरकार की तमाम एजंसियां सक्रिय हो गई हैं, लेकिन यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि वहां मजदूरों की जीवन दशा बेहद खराब है और इस बारे में अक्सर सवाल उठते रहे हैं, जिन्हें अनसुना किया जाता रहा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े हैं कि खाड़ी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में मजदूरों की 48095 शिकायतें मिलीं, जिनमें सबसे ज्यादा कुवैत में ही 23020 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों पर क्या कदम उठाए गए, इस बारे में तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। यह साफ है कि कुवैत में मजदूरों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। वहां पर खराब स्थिति और कम संसाधनों के बीच उन्हें रहने को मजबूर किया जाता है। जबकि, कुवैत की अर्थव्यवस्था जो इस समय आगे बढ़ रही है, उसमें भारतीयों की भूमिका सबसे ज्यादा है।

आरोप तो यहां तक लगते हैं कि कुवैत के स्थानीय लोग भारतीय मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। नियोक्ता तय वेतन से कम भुगतान करते हैं। सुविधाएं ना के बराबर हैं। एक-एक कमरे में 15 से 20 मजदूरों को ठूंस कर रखा जाता है। मंगफ क्षेत्र की जिस इमारत में आग लगी, उसकी सुरक्षा और सरकारी प्राधिकारों की अनुमति को लेकर भी सवाल उठे हैं। वहां जांच बिठा दी गई है। लेकिन अहम सवाल यह है कि व्यवस्था में सुधार को लेकर कोई पहल पहले क्यों नहीं दिखी। सवाल यह भी उठता है कि बदहाली के बावजूद कुवैत समेत खाड़ी देशों में मजदूरों की संख्या क्यों बढ़ रही है। एक रपट के मुताबिक, एक भारतीय मजदूर वहां चालीस से पचास हजार रुपए हर महीने कमा लेता है। जाहिर है, कुवैत में ज्यादा कमाई का लालच तो है ही। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 1990-91 के खाड़ी युद्ध में कुवैत में भारतीय समुदाय पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भारतीयों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। 1.7 लाख से ज्यादा भारतीयों ने देश छोड़ा। लेकिन इसके बाद ज्यादा कमाई के लालच में वहां संख्या बढ़ी। साथ ही, वहां की कंपनियों का सस्ते श्रम का लालच भी बढ़ा।

कुवैत में कई बार दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी के मामले आए हैं। शोषण की शिकायतें इतनी ज्यादा मिलने लगी हैं कि भारतीय दूतावास में एक शिकायत निपटान केंद्र खोलना पड़ा। वहां अधिकतर मजदूर केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से जाते हैं और उनके अनुभव आमतौर पर ठीक नहीं होते। मंगफ हादसे में मरे मजदूरों के बारे में ऐसी भी जानकारियां सामने आई हैं कि उनमें से कई को पर्यटक वीजा पर ले जाया गया। अब कुवैत सरकार ऐसे मजदूरों को अवैध मजदूर के तौर पर चिह्नित करने में जुटी है। पर्यटक वीजा पर भेजे गए मजदूरों का कोई रेकार्ड न तो दूतावास में होता है और न ही भारत सरकार के पास। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि भारत सरकार उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का गठन करके अपनी ओर से भी जांच बिठाए।

बराबरी का सवाल

पूरी दुनिया में लंबे समय से महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक और हिस्सेदारी की जरूरत की बात उठती रही है। सरकारों ने अनेक नीतियां बनाईं, कई नियम-कायदों में बदलाव किए गए। लेकिन शिक्षा, आय, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी के स्तर पर सवाल उठते रहते हैं। विश्व आर्थिक मंच की इस साल की लैंगिक अंतर सूचकांक रपट में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक आंका गया है। भारत दो पायदान नीचे खिसककर 129वें स्थान पर आ गया, जबकि आइसलैंड जैसे छोटे से देश ने सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। दक्षिण एशिया में भारत वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद पांचवें स्थान पर है। रपट में यह भी कहा गया है कि भारत ने 2024 में अंतर का 64.1 फीसद कम कर लिया है। भारत के आर्थिक समानता स्कोर में सुधार हो रहा है, लेकिन 2012 के 46 फीसद के स्तर पर लौटने के लिए इसे 6.2 फीसद अंक बढ़ाने की जरूरत है।

लैंगिक समानता के लिए विश्व भर की सरकारों ने अनेक नीतियां बनाई हैं, पर उनसे अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाए हैं। विश्व आर्थिक मंच की रपट से स्पष्ट है कि भारत में नीतियां फाइलों और घोषणाओं तक सीमित रह गई हैं। भारत पिछले वर्ष 127वें स्थान पर था और सूची में दो पायदान नीचे जाने की मुख्य वजहों में शिक्षा प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तीकरण मापदंडों में आई मामूली गिरावट है। यह स्थिति तब है, जब भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के मामले में भारत ने सबसे अच्छी समानता दिखाई है जबकि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण में अपना देश 65वें स्थान पर है। बीते 50 वर्षों में महिला/पुरुष राष्ट्राध्यक्षों के साथ समानता के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। स्पष्ट है कि लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव तो आ रहा है, लेकिन पुरुषवादी मानसिकता पूरी तरह खत्म नहीं हो रही है। इस स्थिति को बदलने के लिए समाज की मानसिकता को बदलना होगा।

हिंद महासागर का बिगड़ता मिजाज

एक अध्ययन के मुताबिक इक्कीसवीं सदी के अंत तक हिंद महासागर का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसकी सिर्फ सतह नहीं, बल्कि दस किलोमीटर नीचे तक पानी गर्म हो रहा है।

अखिलेश आर्येंदु

महासागरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इनमें हिंद महासागर तेजी से गर्म हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं बार-बार उथल-पुथल मचाने लगी हैं। इनकी वजह से तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिए खतरा पैदा हो गया है। विज्ञान पत्रिका 'जर्नल साइंस डायरेक्ट' में प्रकाशित अध्ययन से इसकी जानकारी मिली है। पिछले पांच दशक से प्राकृतिक संसाधनों में अनेक प्रकार के बदलाव देखे जा रहे हैं। इनके असर से ऋतुचक्र और वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह महज भारत की समस्या नहीं है, वैश्विक स्तर पर जलवायु में बदलाव देखा जा रहा है। पत्रिका के मुताबिक समुद्र की सतह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का अनुमान है। अध्ययन के मुताबिक हिंद महासागर का गर्म होना सिर्फ सतह तक सीमित नहीं है, इसके जल का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इससे समुद्री ऊष्म तरंगें बननी शुरू हो गई हैं। समुद्री जैव विविधता पर इसका बुरा असर देखा जा रहा है।

वैज्ञानिकों के अनुसार शताब्दी के अंत तक अत्यधिक द्विध्रुवीय घटनाओं में 66 फीसद तक वृद्धि का अनुमान है। एक अध्ययन के मुताबिक इक्कीसवीं सदी के अंत तक हिंद महासागर का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसकी सिर्फ सतह नहीं, बल्कि दस किलोमीटर नीचे तक पानी गर्म हो रहा है। महासागर का तापमान बढ़ने से कई देशों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका असर पर्यावरण पर व्यापक रूप से पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि वर्ष 2020 से 2100 के बीच हिंद महासागर की समुद्री सतह के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका है। इससे मानसून पर असर पड़ेगा, चक्रवात आएगा और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। आने वाले पचहत्तर साल में जैव विविधता पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। हजारों किलोमीटर की जैव विविधता नष्ट हो सकती है।

अध्ययन के मुताबिक समुद्री लू (समुद्र का तापमान असामान्य रूप से अधिक रहने का समय) वर्ष 1970 से 2000 के दौरान हर साल बीस दिन होती थी। अब उसके बढ़कर हर साल 220-250 दिन होने का अनुमान है। इसके चलते उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर इक्कीसवीं सदी के अंत तक स्थायी लू की स्थिति के करीब पहुंच जाएगा। इस हालात में समुद्र की पारिस्थितिकी पर गहरा असर होगा। समुद्र में पाए जाने वाली तमाम चीजों के रंग में बदलाव हो सकता है, जिसमें समुद्री घास, मूंगों और मछलियों का रंग भी बदल जाएगा। चक्रवात बहुत कम वक्त में ही जोर पकड़ने लगता है। समुद्र का तापमान बढ़ने से नई समस्याएं पैदा होंगी। समुद्र से इंसान का सीधा रिश्ता है, इसलिए वैज्ञानिक हिंद महासागर के बढ़ते तापमान से बेहद चिंतित हैं। जाहिर तौर पर धरती के बढ़ते तापमान के साथ समुद्र का तापमान बढ़ना मानव सभ्यता के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

'उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के लिए भविष्य के पूर्वानुमान' शीर्षक अध्ययन के मुताबिक, हिंद महासागर के जल के तापमान का तेजी से बढ़ना महज इसकी सतह तक सीमित नही है। हिंद महासागर में, ऊष्मा की मात्रा

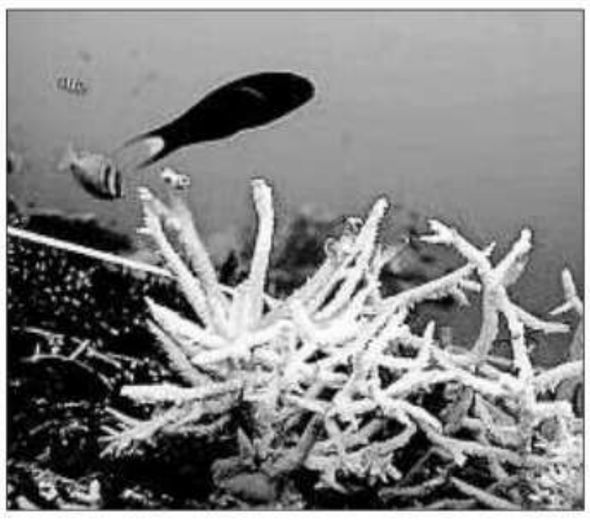

सतह से 2,000 मीटर की गहराई तक वर्तमान में 4.5 जेटा-जूल प्रति दशक की दर से वृद्धि होने का अनुमान है और आने वाले वक्त में इसके 16 से 22 जेटा-जूल प्रति दशक की दर से बढ़ने का अनुमान है। जाहिर तौर पर इससे हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास ही नहीं, कई किलोमीटर क्षेत्र में कई तरह के बदलाव होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऊष्मा की मात्रा में होने वाली वृद्धि एक परमाणु बम (हिरोशिमा में हुए) विस्फोट से पैदा होने वाली ऊर्जा के समान होगी। इसके अलावा, अरब सागर सहित उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी हो सकती है, जबकि सुमात्रा और जावा के तटों पर कम गर्मी होने का अनुमान है। बेहद तेज तूफानों से समुद्री तटों पर कई तरह के विनाशकारी मंजर नजर आ सकते हैं।

> **हिंद महासागर के साथ-साथ दूसरे महासागरों का तापमान बढ़ना किसी बड़े विनाश का सूचक बताया जा रहा है। महासागरों का तापमान गर्म होने के बीच, सतह के तापमान के मौसमी चक्र में बदलाव होने का अनुमान है। वर्ष 1980 से 2020 के दौरान हिंद महासागर में अधिकतम औसत तापमान पूरे साल 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वैज्ञानिक इससे अनुमान लगा रहे हैं कि भारी उत्सर्जन परिदृश्य के तहत इक्कीसवीं सदी के अंत तक न्यूनतम तापमान पूरे साल 28.5 डिग्री सेल्सियस और 30.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।**

हिंद महासागर के साथ-साथ दूसरे महासागरों का तापमान बढ़ना किसी बड़े विनाश का सूचक बताया जा रहा है। महासागरों का तापमान गर्म होने के बीच, सतह के तापमान के मौसमी चक्र में बदलाव होने का अनुमान है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं बढ़ सकती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 1980 से 2020 के दौरान हिंद महासागर में अधिकतम औसत तापमान पूरे साल 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वैज्ञानिक इससे अनुमान लगा रहे हैं कि भारी उत्सर्जन परिदृश्य के तहत इक्कीसवीं सदी के अंत तक न्यूनतम तापमान पूरे साल 28.5 डिग्री सेल्सियस और 30.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गौरतलब है कि 28 डिग्री सिल्सियस से ऊपर की सतह का तापमान आमतौर पर गहरे संवहन और चक्रवात के लिए अनुकूल माना जाता है। अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 1950 के दशक से भारी बारिश की घटनाएं और भंयकर चक्रवात पहले भी कहर ढा चुके हैं। सागर के तापमान में वृद्धि के साथ इसके और बढ़ने का अनुमान है। इससे बहुत सारे विपरीत प्रभाव दिखाई पड़ सकते हैं।

हिंद महासागर में गर्मी बढ़ने से इसका जलस्तर भी बढ़ सकता है। पानी में गर्मी का विस्तार हिंद महासागर में समुद्र के जल स्तर में आधे से अधिक वृद्धि में योगदान देता है, जो ग्लेशियर और समुद्री बर्फ के पिघलने से होने वाली बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा है। अध्ययन के मुताबिक सदी के अंत तक समुद्र का अम्लीकरण तेज हो सकता है। इससे सतह का पीएच 8.1 से ऊपर से घटकर 7.7 से नीचे आ सकता है। पीएच में अनुमानित बदलाव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस वजह से मूंगे और ऐसे जीव, जो अपनी खोल के निर्माण और रखरखाव के लिए कैल्सिफिकेशन पर निर्भर रहते हैं, प्रभावित होंगे। इस बदलाव को पीएच में बदलाव के आधार पर हम समझ सकते हैं। जैसे इंसान के रक्त के पीएच में मामूली 0.1 की गिरावट से सेहत पर गंभीर असर पड़ जाता है और कई अंग काम करना बंद कर देते हैं, उसी तरह सागर के पानी के पीएच मान में बदलाव के असर का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्लोरोफिल और उत्पादकता में भी गिरावट आने का अनुमान है। इससे पश्चिमी अरब सागर की पारिस्थितिकी ज्यादा प्रभावित होगी।

मानसून और चक्रवात निर्माण को प्रभावित करने वाली एक घटना, हिंद महासागर द्विध्रुव, में भी बदलाव आने का अनुमान वैज्ञानिक लगा रहे हैं। इसमें इक्कीसवीं सदी के अंत तक बहुत तेज बदलाव वाली घटनाओं की आवृत्ति में 66 फीसद तक की वृद्धि हो सकती है, वहीं मध्यम घटनाओं की आवृत्ति में 52 फीसद की कमी आने का अनुमान है। हिंद महासागर चालीस देशों की सीमा को छूता है। दुनिया की आबादी के एक तिहाई हिस्से के घर, हिंद महासागर क्षेत्र में आते हैं। जलवायु परिवर्तन का सामाजिक और आर्थिक असर कितना गहरा पड़ेगा इससे अनुमान लगाया जा सकता है।

आज हिंद महासागर और इसके आसपास के इलाकों में वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के सबसे ज्यादा खतरे वाले क्षेत्र के रूप में देखे जा रहे हैं। इसलिए हिंद महासागर और दूसरे महासागरों से बढ़ते खतरों पर चौकन्ना रहने की बेहद जरूरत है।

दुनिया मेरे आगे

कुदरत से सहमेल

राजेंद्र प्रसाद

प्रकृति ईश्वर की सर्वोत्तम भेंट है। ईश्वर प्रकृति के माध्यम से भोजन, हवा, पानी, सांस और आनंद देता है, वहीं मन हमें आनंद-क्लेश और सुख-दुख दोनों दे सकता है। विशेषकर मनुष्य छेड़छाड़ करके अपने और प्रकृति के नुकसान का कारण और चुनौती बनता जा रहा है, जबकि अधिकतर अन्य जीव प्रकृति अनुकूल जीवन जीते हैं। विकास की भूख, जरूरतों के अंबार और आधुनिकता की ओट में वनों की कटाई, पर्वतों की तोड़फोड़ करके मकान, उद्योग, वाणिज्यिक गतिविधियां, सड़क आदि के निर्माण में कंक्रीट की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं खड़ी हो रही हैं। आधुनिकता के ढेरों पक्षकार मानते हैं कि जो कुछ भी है, सब सुख वृद्धि व विकास की रफ्तार के लिए है। सुख की अबूझ पिपासा प्रकृति के साथ अबाध और परिणामविमुख छेड़खानी चल रही है। हालांकि प्रकृति बारंबार चेताती है। कभी भूकम्प आहट देता है तो कभी बाढ़ का तांडव। मनुष्य कुछ पल झिझकता है, लेकिन आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ में फिर से जुट जाता है।

मन जीव का विषय है, जिसका बहुत बड़ा संबंध प्रकृति से है। उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान सब कुछ संगठित-असंगठित तरीके से कर रहा है। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही आध्यात्मिक और प्रकृति के अर्थ को समझ सकता है। अस्वस्थ मन से उत्पन्न कार्य भी अस्वस्थ होंगे। इंसान मन को मनाकर खुश रह सकता है, न कि उसके मुताबिक चलकर। देह एक रथ है, इंद्रिया उसमें घोड़े, बुद्धि सारथी और मन लगाम है। मन को कर्तव्य की डोरी से बांधना पड़ता है, नहीं तो उसकी चंचलता आदमी को न जाने कहां लिए फिरे। मन में दुख होने पर देह भी ठीक वैसे ही संतप्त होने लगती है, जैसे घड़े में तपाए हुए लोहे के गोले को डाल देने में उसमें रखा हुआ ठंडा पानी गर्म हो जाता है। खुश रहने का एक सीधा-सा मंत्र है- कौन क्या, कैसे और क्यों कर रहा है, इससे मन को जितना दूर और संतुलित रखेंगे, मन की शांति के उतने ही करीब रहेंगे। परिस्थिति बदलना मुश्किल न हो तो मन की स्थिति बदल ली जाए। सब कुछ अपने-आप बदल जाएगा। अच्छी मानसिकता से ही अच्छा जीवन जीया जाता है। मानसिक बीमारियों से बचने का एक ही उपाय है कि हृदय को घृणा से और मन को भय और चिंता से मुक्त रखा जाए।

प्रकृति को भूलना आधुनिकता नहीं है। इसके भाव को सहज रूप से महसूस न करने वाला मन बीमार होता है। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन और प्रकृति का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। कोई रचनात्मक काम करने से मन बुरे विचारों में नहीं उलझेगा। आदमी जितना सृष्टि से दूर हो रहा है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से उतना ही अस्वस्थ्य हो रहा है। मन की सोच सुंदर हो तो संसार सुंदर लगता है। मन ही संसार है। प्रकृति का सनातन रहस्य है कि जैसा मन होता है, वैसा मनुष्य बन जाता है। मन तृप्त हो तो बूंद भी बरसात है, अन्यथा अतृप्त मन के आगे समंदर की भी क्या औकात!

बदलते दौर में मन की कमियों से जीतने के लिए इंसान अप्राकृतिक सुखों का भ्रमवश सहारा तलाशता है। प्रकृति की गोद में बैठकर आत्मा टटोलने में लगेंगे तो सही राह तक पहुंच सकते हैं, पर भौतिक संसाधनों की ओर और ज्यादा झुकने से वास्तविक जीवन पटरी से उतरता प्रतीत होता है। यही पतन का सबसे मुख्य आधार है। इससे मनुष्य प्रकृति से दूर जा रहा है। नकली सुख अलगाव लाता है। किसी भी युग में भौतिकता से आनंद का कोई लेना-देना नहीं है। कृत्रिम आनंद के वजन से हम चाहे-अनचाहे दबते चले जाते हैं। यक्ष प्रश्न यह भी है कि अंतर्मन की सुनें या वास्तविक आनंद की? आनंद के लिए लोग जंगलों-पहाड़ों की तरफ दौड़ते हैं, पर वहां वे घर से भी अधिक बेतरतीब हो जाते हैं। कूड़ा-कचरा कूड़ेदान में डालना होता है, पर आनंद के नशे में वहीं जहां-तहां अपना कचरा छोड़ चलते बनते हैं। घर आने पर अल्पकाल में मन पहले की तरह ऊबड़-खाबड़ हो जाता है। गए थे तो प्रकृति की गोद में आनंद का बोध करने, पर वह अधूरा रहा। मन और मकान को समय-समय पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती हैं। मन को निर्मल रखना भी एक धर्म है। यह याद रखना चाहिए कि दुनिया तभी तक खूबसूरत है, जब तक प्रकृति सुरक्षित है।

> **बदलते दौर में मन की कमियों से जीतने के लिए इंसान अप्राकृतिक सुखों का भ्रमवश सहारा तलाशता है। प्रकृति की गोद में बैठकर आत्मा टटोलने में लगेंगे तो सही राह तक पहुंच सकते हैं, पर भौतिक संसाधनों की ओर और ज्यादा झुकने से वास्तविक जीवन पटरी से उतरता प्रतीत होता है।**

जुगनू तभी तक चमकता है, जब तक उड़ता है। यही हाल मन का है, जब हम रुक जाते हैं और खुद को खंगालते नहीं हैं तो अंधकार में पड़ जाते हैं। खुद की खुशी के लिए प्रकृति को नाखुश न रखें। चिकित्सक उपचार करते हैं और प्रकृति अच्छा करती है। प्रकृति मां से भी बड़ी होती है। प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाती है और जो कार्य प्रकृति के करने का है, उसे मनुष्य हरगिज नहीं कर सकता। मनुष्य की जरूरतें पूरा करने के लिए प्रकृति के पास सब उपलब्ध है, पर उसके लालच के लिए कुछ नहीं। ईश्वर अपनी सृष्टि को किसी अवस्था में जंजीर से बांधकर नहीं रखते, उसे नए-नए परिवर्तनों के बीच निरंतर नवीन करते हुए सजग रखते हैं। लोग आजमाते हैं, 'परमात्मा' है कि नहीं, पर उसने एक बार भी हमसे सबूत नहीं मांगा कि हम 'इंसान' हैं कि नहीं!

असुरक्षित खाते

एक ओर डिजिटल लेनदेन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर साइबर अपराध का बढ़ता दायरा चिंताजनक है। सरकारी रपट के अनुसार जनवरी से मार्च 2023 की अवधि में देश के इक्कीस लाख बैंक खातों से डेटा चोरी हुआ। बैंकिग विनिमय में यूपीआइ को सुरक्षित बताकर अधिक लोकप्रिय बनाया जा रहा है, लेकिन इस सेवा में ग्राहक हित सुरक्षा को शून्य रखा गया है। आरबीआइ, बैंकों और लघु कंपनियों में ग्राहक डेटा सुरक्षा की नियमित निगरानी करने में विफल रहा है। ग्राहकों का सबसे अधिक डेटा चोरी बैंकों और बीमा कंपनियों के असुरक्षित भंडारण और कर्मचारियों की मिलीभगत से संभव हो रहा है। केवाईसी करने के नाम पर बैंक, बीमा कंपनियां, मोबाइल कंपनियां, शिक्षा और कोचिंग संस्थान समय-समय पर अपने ग्राहकों से केवाईसी दस्तावेज लेने के बाद उनके सुरक्षित भंडारण और निष्पादन नहीं करते हैं। ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रखना बैंक और बीमा कंपनियों का कर्तव्य है। सरकार को इसे कानूनी अमलीजामा पहनाना चाहिए, अन्यथा देश में डिजिटल क्रांति के दौर में ठहराव आ सकता है।

– हिमांशु शेखर, केसपा, गया

गर्मी का प्रकोप

देश के एक बड़े हिस्से में गर्मी और लू का प्रकोप है। इस बार गर्मी का दौर लंबा और असामान्य है। इसके लिए जिम्मेदार बढ़ती मानवीय गतिविधियां हैं। शहरीकरण और हरियाली वाले क्षेत्र घटने से शहर ज्यादा गर्म हो रहे हैं। यह गरीबों के लिए अधिक घातक है, क्योंकि उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जिससे उनको गर्मी से होने वाली थकान से राहत मिल सके। लगातार और तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा चक्र अनियमित होता जा रहा है। कार्बन उत्सर्जन चरम पर है। जीवाश्म ईंधन जलाने और वनों की कटाई से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। ये गैसें वातावरण में तापमान बढ़ा रही हैं, जिससे लू और गर्मी की तीव्रता बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पैटर्न में अनियमितता आ रही है, जिससे गर्मी और बढ़ रही है। पर्यावरण दिवस के आयोजनों में पौधरोपण की बहुतायत रहती है, किंतु असलियत में इससे कहीं अधिक करने की आवश्यकता है।

– गोपाल सोनी, मनावर, मप्र

डिगता भरोसा

परीक्षा प्रश्नपत्रों के लीक होने से छात्रों में तनाव और चिंता बढ़ जाती है। जिन छात्रों ने कड़ी मेहनत की है, उन्हें लगता है कि उनकी उपलब्धियों को कम आंका गया है, जिससे उनका आत्मविश्वास डिगने लगता है। पर्चाफोड़ की बार-बार होने वाली घटनाएं योग्य छात्रों का हक छीन लेती हैं। इससे उन्हें अपने भविष्य को लेकर आशंका घेरने लगती है। बिहार में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं के पर्चे कई बार लीक हो चुके हैं, इससे कई छात्र निराश महसूस करने लगे और शिक्षा प्रणाली में विश्वास खो दिया। इससे छात्रों की शैक्षणिक योजनाएं बाधित होती हैं। छात्रों पर इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम करने के लिए परामर्श और सहायता सेवाएं समय की मांग है। पर्चा लीक से प्रभावित छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श प्रदान करना अत्यंत जरूरी है। प्रश्नपत्र लीक होने की निरंतर घटनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं।

– प्रियंका सौरभ, हिसार (हरियाणा)

विकास की कुल्हाड़ी

आज, जो पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, हम उसी पर विकास की कुल्हाड़ी चला रहे हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर- ये पंचतत्त्व, जो हमारे जीवन का आधार हैं, हम उन सभी को समान रूप से दूषित कर रहे हैं। आम लोग आज पर्यावरण को बचाने की जिम्मेवारी भी सरकार के सिर पर डालना चाहते हैं, यह आत्मघाती है। एकादशी के दिन देखा कि लोग प्याऊ लगाकर जगह-जगह शरबत पिलाकर भरी गर्मी में पुण्य कमा रहे थे, लेकिन प्याऊ के पास का दृश्य अखरने वाला था। चारों ओर बिखरे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के गिलास बिखरे पड़े थे। निश्चित ही पुण्य के साथ ये लोग पाप भी कर रहे थे, धरा के विरुद्ध, जिसकी उन्हें शायद ही कोई ग्लानि हो। ऐसे तो बात नही बनेगी, जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा।

– सचिन पंवार, सहारनपुर

https://t.me/AllNewsPaperPdf

www.readwhere.com

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शुक्रवार, 14 जून 2024

यदि बोलने की आजादी छीन ली, तो हम गूंगे और खामोश हो जाएंगे।
-जॉर्ज वॉशिंगटन

कुवैत की एक इमारत में लगी आग से चालीस से अधिक भारतीय श्रमिकों की मौत दिल दहलाने वाली है। एक तरफ यह एक अत्याधुनिक देश में व्यवस्थाओं की कलई खोलती है, तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों में जा रहे श्रमिकों की दुर्दशा भी बयां करती है।

आग और सवाल

खाड़ी देश कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत के मंगाफ में बुधवार सुबह श्रमिकों के आवास वाली एक छह मंजिला इमारत में भयानक आग से 40 से अधिक भारतीय श्रमिकों की मौत एवं 50 के घायल होने की खबर दिल दहलाने वाली तो है ही, यह इसका भी सबूत है कि दुनिया के छठे सबसे बड़े तेल भंडार वाले इस देश में श्रमिकों की सुरक्षा के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता है। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद अल-यूसुफ अल-सबाह ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद खुद भी स्वीकार किया कि नियोक्ता कंपनी और इमारत के मालिक की तरफ से हुई लापरवाही ही इस दुर्घटना की वजह बनी। दरअसल, भारत के सभी खाड़ी देशों के साथ समझौते और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के नियमों के तहत वहां काम करने वाले भारतीय श्रमिकों को अच्छा वेतन मिलता है, जिसके चलते भारतीय श्रमिक इन देशों में जाना पसंद करते हैं, ताकि अपने घर पर ज्यादा पैसे भेज सकें। लेकिन कुवैत समेत इन देशों में प्रचलित अमानवीय कफाला व्यवस्था में इन श्रमिकों की हालत गुलामों जैसी हो जाती है, जिसमें कंपनियां इनके पासपोर्ट तक जमा करवा लेती हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़े अपनी कहानी आप कहते हैं, जिनके अनुसार, 2014 से 2018 के बीच कुवैत में 2,932 भारतीयों की मौतें हुईं। इसी तरह, 2022 और 2023 में भी कुवैत में क्रमशः 731 और 708 भारतीयों की मृत्यु हुई, जिनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर थे। ऐसे हादसों की एक वजह यह भी है कि तेल की बदौलत ये देश समृद्ध तो होते गए, लेकिन यहां की गगनचुंबी अट्टालिकाओं में अक्सर भवन संहिता का पालन नहीं होता। ताजा हादसे में भी देखा गया कि रात में सोते श्रमिकों में से ज्यादातर की मौतें दम घुटने से हुईं, क्योंकि इमारत में धुएं के बाहर निकलने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। राहत की बात है कि रात की पाली में काम करने वाले श्रमिक घरों में नहीं थे, अन्यथा मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी। कुवैत की आबादी में

करीब 21 फीसदी लोग भारतीय हैं, जो यहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, यहां काम करने वाले कुल लोगों में भी तीस फीसदी भारतीय हैं। ऐसे में, मामले की गंभीरता को समझते हुए कई स्थानीय अधिकारियों को लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। भारत सरकार भी इन हालात में मृतकों के परिजनों को हरसंभव मदद देने की कोशिश कर रही है। लेकिन मंगाफ के इस हादसे से सवाल उस व्यवस्था पर तो उठते ही हैं, जिसमें सैकड़ों मजदूर हर साल रोजी-रोटी की तलाश में बेहद अमानवीय परिस्थितियां होने के बावजूद परदेस जाने को मजबूर होते हैं।

पाकिस्तान और आजाद ख्याल

इसे पाकिस्तान की विडंबना ही कहें कि जहां आम लोगों को एक्स का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं प्रधानमंत्री खुद और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सुबह-शाम एक्स का उपयोग कर अपने ही नियम को तोड़ रहे हैं। असैन्य तानाशाही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है।

बोलने की आजादी, जुझारू व हर तरह के सेंसरशिप से आजाद मीडिया, असहमति को सहन करने की ताकत, असंतोष को दबाना-ये सभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे हैं, जिनके बारे में हम दुनिया भर में पढ़-सुन रहे हैं। हर जगह शासक और ताकतवर लोग मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं खबरों को प्रकाशित एवं प्रसारित करने की अनुमति देते हैं, जो उन्हें पसंद हों। दक्षिण एशिया के देश दुनिया के अन्य देशों से अलग नहीं हैं और इस हफ्ते मैं *अमर उजाला* के पाठकों का ध्यान इस खबर की ओर दिलाना चाहूंगी कि पाकिस्तान की मुख्य पार्टियां यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हो गई हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, ताकि मीडिया की आवाज को और दबाया जा सके।

मरिआना बाबर
वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार

हालांकि पाकिस्तानी मीडिया को चुप कराने संबंधी खबरों में सबसे निराशाजनक खबर दिवंगत बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से आई है, जिसने पंजाब प्रांत की पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की मरियम नवाज सरकार के नए विवादास्पद पंजाब मानहानि विधेयक, 2024 को पारित कराने में साथ दिया है, ताकि उन आक्रोशित नागरिकों को शांत किया जा सके, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। अतीत में जनरल जिया उल हक जैसे सैन्य तानाशाहों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी और विरोध करने वालों को सार्वजनिक रूप से कोड़े तक मारे थे। आज भी मेरे एक बुजुर्ग सहकर्मी नासिर जैदी जीवित हैं, जो बताते हैं कि कैसे तानाशाह ने उन्हें स्वतंत्र रूप से लिखने की हिम्मत करने के लिए कोड़ों से पीटा था। आज असैन्य तानाशाही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। यही नहीं, अब पत्रकारों के गायब होने और उनकी हत्या का खतरनाक चलन भी दिख रहा है। इससे पहले दुनिया भर के तानाशाहों की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ महीने पहले पूरे पाकिस्तान में एक्स पर प्रतिबंध

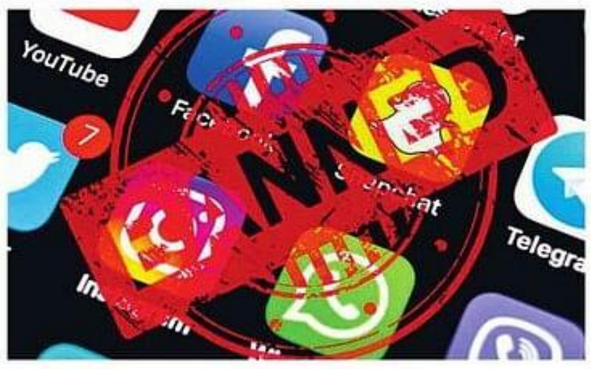

लगा दिया था। तब लोगों को वीपीएन इंस्टाल करना पड़ता था, जो सिस्टम को अनब्लॉक करने में मदद करता है, ताकि उपयोगकर्ता ट्वीट कर सकें। इनमें से कुछ वीपीएन मुफ्त हैं, जबकि कुछ अन्य के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, तभी एक्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जहां आम लोगों को एक्स का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं प्रधानमंत्री खुद और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सुबह-शाम एक्स का उपयोग कर अपने ही नियम को तोड़ रहे हैं। इस हफ्ते हम सबको इस बात पर हंसी आई कि एक्स को ब्लॉक किए जाने के बावजूद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री को आम चुनाव में जीत की बधाई ट्वीट करके दी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके जवाब दिया।

इस पाखंड को सबने समझ लिया कि पाकिस्तान के राजनेता कैसे अपने ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब पंजाब प्रांत की सरकार ने पंजाब मानहानि विधेयक, 2024 के लिए आधिकारिक रूप से गजट अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे विवादास्पद कहा जाता है। नए कानून का उद्देश्य यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं से निपटना है, जिससे 'फर्जी खबर' फैलाने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सके।

इस बात से हर कोई सहमत है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ पोस्ट किया जाता है, उनमें से कुछ नफरत से भरा और अस्वीकार्य होता है। लेकिन उन अकाउंट को बंद करने के बजाय, जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप पूरे नेटवर्क को बंद नहीं कर सकते। पत्रकार समुदाय ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया है। गैर-लोकतांत्रिक बताते हुए इसकी निंदा की है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से भी प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के कारण कड़ी आपत्ति जताई गई है। अंग्रेजी दैनिक द डॉन ने संपादकीय में लिखा है- 'ये घटनाक्रम इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसे आम नागरिक अभी तक पूरी तरह समझ नहीं सके हैं। यहां चिंता यह नहीं है कि नागरिकों को जो कुछ भी वे कहना या उपभोग करना चाहते हैं, उन्हें उसकी अनुमति दी जानी चाहिए, आखिरकार नागरिक होने के नाते वे भी देश के कानून से बंधे हैं। बल्कि डर यह है कि इन हथकंडों का इस्तेमाल पुलिस और सत्ता से असहमत केवल चुनिंदा लोगों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा।'

इस हफ्ते की दूसरी चौंकाने वाली खबर यह है कि शहबाज शरीफ सरकार अब इंटरनेट फायरवॉल बना रही है, जिसे कथित तौर पर अधिकारियों ने गुप्त रूप से लागू करना शुरू कर दिया है, जो उन्हें पाकिस्तानी उपयोगकर्ताओं द्वारा इंटरनेट पर पोस्ट की जाने वाली या देखी जाने वाली हर चीज पर जासूसी करने की अनुमति देगा। यह इंटरनेट फायरवॉल ग्रेट फायरवॉल की तरह है, जिसका उपयोग चीनी अधिकारी अपने नागरिकों पर नजर रखने के लिए करते हैं। यह इंटरनेट फायरवॉल इंटरनेट पुलिस की तरह काम करेगा। खबरें बताती हैं कि सरकार ने विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग शुरू कर दिया है, जिससे यह निगरानी की जा सकेगी कि कोई उपयोगकर्ता इंटरनेट पर क्या कह, सुन या पढ़ रहा है। एक दृष्टिकोण है कि इसके दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इस परियोजना के पूरा होने से पहले उचित मंचों पर इसे जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान तानाशाहों को अपने लोगों पर नियंत्रण बढ़ाने का जोखिम नहीं ले सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के निरंतर प्रयासों पर पूर्व संपादक अब्बास नासिर ने कहा, 'यह उल्लेखनीय है कि इन दिनों मीडिया पर होने वाली किसी भी चर्चा में लगभग हमेशा पारंपरिक मीडिया को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन समाचार साइटों के अलावा, चौबीसों घंटे चलने वाले दर्जनों टीवी चैनल और समाचार पत्र। इसका केवल एक कारण हो सकता है : पारंपरिक मीडिया अब अधिकारियों के इतने अधीन है कि इसे बड़े पैमाने पर उनका मुखपत्र माना जाता है। बहुत कम सम्मानजनक अपवादों के बावजूद। अगर आप मुझसे पूछें, तो यह दुखद है।' बहरहाल, कई दशकों के अपने अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर पलटवार करेगा। यहां तक कि अतीत में भी इसने सैन्य एवं असैन्य तानाशाही का विरोध किया है। हम अपनी जगह वापस पाने, अपनी आवाज बुलंद करने और सच बोलने के लिए लड़ेंगे।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

आचार्य श्रीराम शर्मा

शरीर मनुष्य का एक परिधान है, परंतु भ्रम के कारण वह खुद को शरीर ही मान बैठता है। शरीर के स्वार्थ व अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है।

मैं 'कौन हूं' का सही उत्तर है मैं 'आत्मा' हूं

'मेरे मित्र कौन हैं, शत्रु कौन हैं, कौन-सा देश है, मेरी आय-व्यय क्या है, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति कितनी है? इत्यादि बातों का बराबर विचार करते रहो।' सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है-'आत्मबोध'। अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जीव असल में ईश्वर ही है। विकारों में बंधकर वह बुरे रूप में दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर अमूल्य निधि भरी हुई है। शक्ति का वह केंद्र है और इतनी शक्ति है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी कठिनाइयां, सारे दुख इसी बात के हैं कि हम अपने को नहीं जानते। जब आत्मस्वरूप को समझ जाते हैं, तब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूं, फिर मेरा जन्म-मृत्यु कैसे? मैं प्राण नहीं हूं, फिर भूख-प्यास मुझे कैसी? मैं चित्त नहीं हूं, फिर मुझे शोक-मोह कैसे? मैं कर्ता नहीं हूं, फिर मेरा अंध मोक्ष कैसे? जब वह समझ जाता है कि मैं क्या हूं? तब उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है और सब पदार्थों का रूप ठीक से देखकर उसका उचित उपयोग कर सकता है। चाहे किसी दृष्टि से देखा जाए, आत्मज्ञान ही सर्वसुलभ और सर्वोच्च ज्ञान ठहरता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं? तो वह अपने वर्ण, कुल, व्यवसाय, पद या संप्रदाय का परिचय देगा। ब्राह्मण हूं, अग्रवाल हूं, बजाज हूं, तहसीलदार हूं, वैष्णव हूं आदि उत्तर होंगे। अधिक पूछने पर अपने निवास स्थान, वंश, व्यवसाय आदि का अधिकाधिक विस्तृत परिचय देगा। प्रश्न के उत्तर के लिए ही यह सब वर्णन हो, सो नहीं, उत्तर देने वाला यथार्थ में अपने को वैसा ही मानता है। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि अपने-आप को वह शरीर ही समझने लगा है। वंश, वर्ण, व्यवसाय या पद शरीर का होता है। शरीर मनुष्य का एक परिधान है, औजार है, परंतु भ्रम और अज्ञान के कारण मनुष्य अपने-आप को शरीर ही मान बैठता है और शरीर के स्वार्थ तथा अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है।

मनुष्य शरीर में रहता है, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है कि वह शरीर मात्र नहीं है। प्राण निकल जाने पर शरीर ज्यों-का-त्यों बना रहता है, उसमें से कोई वस्तु घटती नहीं, तो भी वह मृत शरीर बेकाम हो जाता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए, तो लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न होती है और कीड़े पड़ जाते हैं। देह वही है, ज्यों की त्यों, पर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य है। मैं कौन हूं? इसका सही उत्तर यह है कि 'मैं आत्मा हूं।'

आत्मा का मंदिर

सूत्र

शरीर आत्मा का मंदिर है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुविधा के लिए कार्य करना उचित एवं आवश्यक है, परंतु यह अहितकर है कि केवल शरीर के ही बारे में सोचा जाए, उसे अपना स्वरूप मान लिया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया जाए। अपने-आप को शरीर मान लेने के कारण मनुष्य शरीर के हानि-लाभों को भी अपने हानि-लाभ मान लेता है और अपने वास्तविक हितों को भूल जाता है।

8 सवाल

ऐसी सूचनाएं जिनका आपके जीवन से सीधा संबंध होता है, उनके बारे में आपके मन में उठने वाले सभी सवालों का जवाब मिलेगा '8 सवाल' में...

केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में बनी नई सरकार में शामिल दो प्रमुख पार्टियां जदयू बिहार और तेदेपा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्षों से करती आ रही हैं। आइए जानें, क्या है 'विशेष राज्य का दर्जा' और उसके प्रावधान...

विशेष राज्य का दर्जा

1 क्या है विशेष दर्जा?

संविधान में विशेष दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में वर्ष 1969 में पांचवें वित्त आयोग में गाडगिल कमेटी की सिफारिशों के तहत विशेष राज्य के दर्जे की संकल्पना अस्तित्व में आई। विशेष श्रेणी का दर्जा वाले राज्य को संघीय सरकार की सहायता और टैक्स छूट में प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

2 क्या सुविधा मिलती है?

विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को केंद्र सरकार की योजनाएं लागू करने के लिए 90 प्रतिशत धनराशि मिलती है, जबकि अन्य राज्यों में यह 60 से 75 प्रतिशत तक। यदि आवंटित राशि खर्च नहीं की जाती है, तो वह आगे बढ़ जाती है, समाप्त नहीं होती। सीमा शुल्क, आयकर, कॉरपोरेट समेत कई करों में छूट मिलती है। केंद्र के सकल बजट का 30 फीसदी हिस्सा मिलता है।

3 पहले किसे मिला लाभ?

1969 में विशेष राज्य दर्जे का प्रावधान होने पर सबसे पहले जम्मू-कश्मीर, असम और नगालैंड को यह लाभ मिला। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से उसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया।

4 कितने राज्य शामिल?

वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त कुल 11 राज्य हैं। इनमें असम, नगालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल हैं।

5 विशेष राज्य की पात्रता?

पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगने वाला एक रणनीतिक स्थान, आर्थिक एवं ढांचागत दृष्टिकोण से पिछड़ा या वित्तीय रूप से अत्यंत कमजोर।

6 इतनी मदद बढ़ी?

14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और योजना आयोग के विघटन के बाद विशेष श्रेणी के राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को अलग तरीके से शामिल किया गया। वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, राज्यों को दी जाने वाली यह राशि 32 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दी गई है।

7 आंध्र प्रदेश व बिहार को क्यों नहीं मिल रहा विशेष दर्जा?

विशेष राज्य का दर्जा पाने की जो पात्रताएं हैं, वे दोनों ही राज्य पूरी नहीं करते हैं। वित्त आयोग भी इन राज्यों की मांगों को ठुकरा चुका है।

8 आगे क्या?

15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह की किताब पोट्रेट्स ऑफ पॉवर के अनुसार, यदि केंद्र सरकार चाहे, तो किसी राज्य को विशेष श्रेणी दर्जा दे सकती है और 16वें वित्त आयोग को सिफारिश की जा सकती है। हालांकि आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज के तहत मदद दी जा रही है।

आंकड़े

शादी की उम्र

देश में बाल विवाह बड़ी समस्या है। हालांकि जम्मू-कश्मीर में लड़कियों की शादी की औसत उम्र देश में सबसे ज्यादा है।

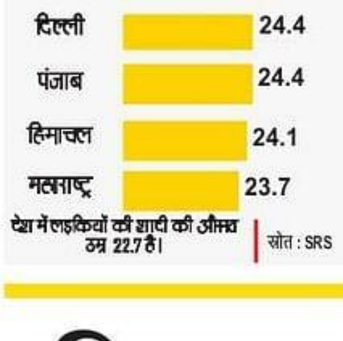

देश में लड़कियों की शादी की औसत उम्र 22.7 है। | स्रोत : SRS

आज मां धूमावती का प्राकट्य दिवस है। कथा है कि एक बार सती को बहुत भूख लगी, जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया।

शिव को निगल गईं धूमावती

अंतर्यात्रा

संकलित

पौराणिक कथाओं के अनुसार मां धूमावती के प्राकट्य को लेकर दो कथाएं हैं। धूमावती पार्वती का एक रूप हैं। पहली कथा यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप हैं। सती का जो कुछ बच गया था, वह उदास धुआं था।

पुराणों में उनके प्राकट्य दिवस को लेकर एक और कथा आती है। उसके अनुसार, एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थीं। इसी दौरान उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मुझे भूख लगी है। मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। शिव ने कहा, देवी! अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। इसके बाद सती ने कहा कि ठीक है, मैं आपको ही खा जाती हूं।

वह भूख से इतनी व्याकुल थीं कि भगवान शिव को ही निगल गईं। सती की जब भूख शांत हो गई, भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो। उन्होंने भगवान को उगलकर बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। बताया जाता है कि इसी वजह से सुहागिन स्त्रियां माता धूमावती के दर्शन नहीं करती हैं। मां धूमावती का वाहन कौवा है।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 जुलाई, 1953

चर्चिल व आइजनहावर में गहरे हुए मतभेद

बीमारी' राजनैतिक है
अमरीका रूस से वार्ता नहीं करना चाहता
तीन बड़े विदेशमंत्री मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे
पंचायतों अदालतों पर पूर्ण सन्तोष

लंदन में यह चर्चा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर के बीच गंभीर मतभेद हैं। इसी कारण बरमूदा सम्मेलन स्थगित किया गया है और चर्चिल रहस्यमय ढंग से बीमार पड़ गए हैं।

सियासत से नहीं बुझेगी दिल्ली की प्यास

सियासत अपनी जगह है, पर टैंकर माफिया पर अंकुश लगाने में असमर्थ दिल्ली सरकार पानी के ट्रीटमेंट व स्टोरेज पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रही।

ज्ञानेन्द्र रावत

जल संकट

वैसे तो मौसम की मार झेल रहे दिल्लीवासियों को हर साल भीषण गर्मी के दौरान पानी की भारी कमी से जूझना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दिल्लीवासी पानी की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी दिल्ली के जल संकट के लिए कभी दिल्ली के उपराज्यपाल को, तो कभी हरियाणा सरकार को दोषी ठहराती रहीं, तो वहीं उपराज्यपाल जल संकट के लिए पानी की चोरी और बर्बादी को मुख्य कारण बता रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने टैंकर माफिया पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और यह भी माना है कि इसी वजह से यह समस्या इतना विकराल रूप ले पाई है।

अब जब हिमाचल साफ कह चुका है कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए 136 क्यूसेक पानी नहीं है, शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए दिल्ली को पानी देने का फैसला अपर रिवर यमुना बोर्ड पर छोड़ा है कि उसके पास जल बंटवारे के जटिल मुद्दे के समाधान की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है।

सवाल यह भी है कि जब हरियाणा द्वारा दिल्ली को पूरा पानी दिया जा रहा है, तो दिल्ली पानी की किल्लत क्यों झेल रही है। दिल्ली वाले पानी के लिए क्यों तरस रहे हैं, मारामारी करने पर क्यों उतारू हैं? असलियत में यह सिलसिला दिल्ली में आप की सरकार के अस्तित्व में आने के साथ से ही लगातार जारी है। दिल्ली को हरियाणा से कुल 1,050 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए। एक से 22 मई तक हरियाणा मुनक नहर के कैरियर लाइन नहर यानी सीएलसी में 719 क्यूसेक और दिल्ली सब ब्रांच यानी डीएसबी नहर में 350 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। मतदान के दो से तीन दिन पहले इसे 91 क्यूसेक तक कम कर दिया गया। जहां तक मुनक नहर की मरम्मत और रख-रखाव का सवाल है, इसका ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ना नितांत गलत है, क्योंकि नहर की मरम्मत और उसके रख-रखाव का जिम्मा हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग का है। हकीकत में मुनक नहर से पानी बवाना लाया जाता है। बवाना से पहले यदि पानी की चोरी होती है, तो इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है।

यह तो रही दूसरे राज्यों से पानी आने, न आने की बात। कम पानी आने से वजीराबाद जलाशय का स्तर सामान्य से पांच फीट नीचे आ जाना खतरे का संकेत है। दिल्ली में जगह-जगह लोगों के लिए लगाए गए वाटर एटीएम की बात करें, जिसके बारे में भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के बढ़-चढ़कर दावे किए जा रहे थे, तो हकीकत यह है कि वे खराब पड़े हैं। जहां तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात है, तो हाल फिलहाल नौ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। दिसंबर तक द्वारका में एक नया प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन, असली समस्या तो पानी की मांग और उपलब्धता की है। दिल्ली में पानी की मांग 1,296 एमजीडी से 1,300 एमजीडी तक है, जबकि सप्लाई केवल 998.8 से 1,000 एमजीडी ही है। स्वाभाविक है 300 एमजीडी पानी की कमी तो बरकरार रहती ही है।

जल संकट के मद्देनजर कुल 587 ट्यूबवेल लगाने की योजना थी। पहले चरण में इनमें से कुछ लगे भी, जिनसे 19 एमजीडी पानी मिल रहा है, जबकि दूसरे चरण में 2,590 ट्यूबवेल के लिए 1,800 करोड़ की राशि की दरकार थी, जिसकी अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। फिर दिल्ली सरकार के जल बोर्ड की क्षमता केवल 90 करोड़ गैलन पानी के ट्रीटमेंट की ही है।

हकीकत यह है कि दिल्ली सरकार खुद ही पानी के ट्रीटमेंट और स्टोरेज पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार दिल्लीवासियों की पानी की जरूरत कैसे पूरी कर पाएगी, यह समझ से परे है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए योजना पेश करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जब तकरीबन 40-50 साल पुरानी पाइप लाइन लीकेज और जगह-जगह फटने से हजारों गैलन पानी की बर्बादी रोजमर्रा की बात है, तो इनमें सुधार किए बिना आने वाले दिनों में दिल्ली वाले पानी के संकट से कैसे निजात पाएंगे, यह समझ से परे है। हिमाचल की मनाही और शीर्ष अदालत के अपर रिवर यमुना बोर्ड के पास जाने के लिए कहने के बाद देखने वाली बात है कि अब दिल्ली सरकार पानी के लिए क्या कदम उठाएगी।

संपादकीय जागरण

(12) शुक्रवार, 14 जून, 2024: ज्येष्ठ शुक्ल - 8 वि. 2081

कृत्रिमता का आवरण बहुत समय तक नहीं टिकता

परीक्षा की विश्वसनीयता

मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा यानी नीट में अनियमितता को लेकर जो सवाल उठे, उनमें से ग्रेस मार्क्स के मामले का समाधान होना संतोष की बात है। 1563 छात्रों को परीक्षा में देरी के आधार पर जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वे रद कर दिए गए हैं। इसके चलते इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी या फिर ग्रेस मार्क्स के बगैर ही काउंसलिंग में शामिल होना होगा। ऐसे लगभग सभी छात्र दोबारा परीक्षा देना पसंद करेंगे, ताकि अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकें। चूंकि ऐसे छात्रों की संख्या अधिक नहीं, इसलिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को उनकी दोबारा परीक्षा लेने में कोई समस्या नहीं होगी और वे छात्र भी संतुष्ट होंगे, जो ग्रेस मार्क्स देने के नियम का विरोध कर रहे थे। यह विरोध उचित ही था, क्योंकि यह समझना कठिन था कि परीक्षा में देरी के आधार पर इस तरह ग्रेस मार्क्स कैसे दे दिए गए कि कुछ छात्र शत-प्रतिशत नंबर पा गए? ग्रेस मार्क्स देने को लेकर इसलिए भी संदेह उभर आया था, क्योंकि एक ही परीक्षा केंद्र के कई छात्र-छात्राओं को शत-प्रतिशत अंक हासिल हो गए थे। अच्छा होगा कि भविष्य में ग्रेस मार्क्स देना बंद किया जाए और यदि छात्रों को किसी कारण परीक्षा में देरी का सामना करना पड़े तो उन्हें दोबारा परीक्षा देने की सुविधा दी जाए। ग्रेस मार्क्स का मसला हल होने के बावजूद मामला अभी पूरी तौर पर शांत नहीं हुआ है, क्योंकि अनेक छात्र, अभिभावक और विपक्षी नेता नीट में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट अभी किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है और उसने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग पर विचार करने से भी मना कर दिया है। संभवत इसका कारण यह है कि जो भी नीट में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, वे इस परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का कोई प्रमाण नहीं दे सके हैं। यह सही है कि बिहार में कुछ साल्वर गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन अभी ऐसे प्रमाण सामने नहीं आए हैं कि प्रश्नपत्र लीक हो गए थे। शायद इसी कारण कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यह दावा कर रहे हैं कि नीट में कहीं कोई धांधली नहीं हुई। इस सबके बावजूद यह अच्छी बात नहीं कि नीट की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हुए। इस परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए को भी सवालों से दो-चार होना पड़ रहा है। उसकी परीक्षाओं को लेकर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। जहां सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, वहीं संकीर्ण स्वार्थों के चलते परीक्षाओं की विश्वसनीयता को संदिग्ध बताने वालों को बेनकाब भी करना होगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल और कोचिंग संस्थाएं अपना उल्लू सीधा करती दिख रही हैं।

सुविधापूर्ण हों अस्पताल

राज्य सरकार ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। भीषण गर्मी और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) समेत अन्य मौसमी बीमारी को देखते हुए यह जरूरी ही है। मुख्यमंत्री ने भी सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, अनुमंडल व सदर अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश देते हुए मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाएं और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता पर ध्यान देने को कहा है। राहत की बात है कि राज्य में इस साल एईएस के मामलों में खासी कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार भीषण गर्मी के बावजूद अब तक कुल 43 मामले ही सामने आए हैं। विभागीय स्तर पर सघन मानीटरिंग और स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयास से ही ऐसा संभव हो सका है। सभी अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और एईएस प्रभावित जिलों में चिकित्सक व अन्य स्वास्थ्यकर्मी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जाहिर है, राज्य के अस्पतालों में अगर तीन सौ तरह की दवाएं मिलने लगेंगी तो मरीजों और उनके स्वजन की परेशानी काफी कम हो जाएगी। अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं कि दावों के उलट मरीजों को दवा नहीं मिल रही है। इसके लिए अस्पताल के प्रभारी को विशेष रूप से सजग होना होगा। ऐसी व्यवस्था विकसित करना श्रेयस्कर होगा, जिससे यह पता चल जाए कि अस्पताल के स्टाक में कौन दवा कितनी मात्रा में उपलब्ध है, ताकि समय रहते उसे मंगवा लिया जाए। आलाधिकारियों को यह भी देखना होगा कि अस्पताल की क्षमता के अनुरुप वहां मरीज तथा उनके तीमारदार के लिए आधारभूत बुनियादी सुविधाएं एवं पर्याप्त मानव बल उपलब्ध हैं अथवा नहीं। इसके साथ ही किसी भी सरकारी अस्पताल में दलालों की मौजूदगी पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि वे परेशान हाल स्वजन को बरगला नहीं सकें।

स्वास्थ्यकर्मियों तथा मरीजों के स्वजन के सामूहिक प्रयास से ही सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाना संभव हो सकेगा।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों को उनके पुराने विभाग देने का फैसला सही है?

आज का सवाल
क्या विराट कोहली को विश्व कप में ओपनिंग के बजाय तीसरे नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए?

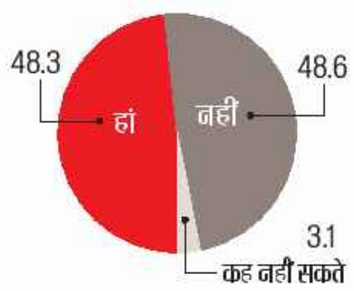

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आकड़े प्रतिशत में।

मोदी सरकार के लिए सबक

विकास सारस्वत

खराब टिकट वितरण, बाहरी नेताओं का आयात, पुराने कैडर की उपेक्षा जैसी समस्याएं भाजपा में बढ़ती हाईकमान संस्कृति की देन हैं

लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता के बावजूद बहुमत के आंकड़े से कुछ पीछे रह जाने की भाजपा को कुछ न कुछ टीस जरूर होगी। हालांकि पार्टी कुछ उपलब्धियों पर संतोष का अनुभव कर सकती है। कई इलाकों में जहां वह पहले हाशिए पर रहती आई, वहां भी उसे कुछ समर्थन मिलता दिखाई दिया। जैसे उसे तमिलनाडु में 11.1 प्रतिशत वोट मिले। इसी के साथ इस राज्य में 1971 के बाद दस प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करने वाली वह पहली राष्ट्रीय पार्टी बनी। पिछले आम चुनाव में भाजपा को यहां मात्र 3.6 प्रतिशत वोट मिला था। त्रिशूर सीट जीतकर भाजपा ने केरल में पहली बार अपना खाता खोला। पूर्वी तट वाले राज्यों में भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा है। ओडिशा में पार्टी ने न केवल 21 में से 19 लोकसभा सीटें जीतीं, बल्कि राज्य में पहली बार सत्ता प्राप्त भी की। दोनों तेलुगु भाषी राज्यों आंध्र और तेलंगाना में भी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। इस विस्तार के बावजूद भाजपा को महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बंगाल में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। आशा अनुरूप सफलता न मिलने के अलग-अलग राज्यों में कारण भी अलग रहे। राजस्थान में बिगड़े जातीय समीकरण और हरियाणा में अग्निवीर योजना ने असर डाला। महाराष्ट्र में लगभग आधे विपक्ष को अपने साथ मिला लेने के कारण पक्ष-विपक्ष जैसी रेखा ही खत्म हो गई और मतदाता में इस विचारविहीन आवागमन के प्रति नाराजगी थी। हालांकि इन तीनों राज्यों में भाजपा को भी थोड़े बहुत नुकसान की आशंका थी। सबसे अधिक चौंकाने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश से आए, जहां पार्टी सपा से भी पीछे रह गई।

उप्र के नतीजों की पड़ताल करें तो यहां 2022 विधानसभा चुनावों में बसपा को 13 प्रतिशत से कुछ कम वोट मिला था, जो इस बार 9.44 प्रतिशत रह गया। इसका लाभ आइएनडीआइए खेमे को मिला। दलित वोट में इस छितराव के अलावा कुछ पिछड़ी जातियों का झुकाव भी आइएनडीआइए की ओर दिखा। रुहेलखंड में सैनी, दोआब में निषाद और अवध में कुर्मी वोट भाजपा से छिटका। भाजपा और उसके समर्थक दलों के बयानों के खिलाफ राजपूतों की नाराजगी ने भी कहीं-कहीं पर प्रभाव डाला। किसी बड़े राष्ट्रीय या राष्ट्रवादी मुद्दे के अभाव में यह चुनाव भारतीय राजनीति की मूल वृत्ति जातिवाद की ओर गया और अखिलेश का सामाजिक समीकरण निर्माण भाजपा की खराब उम्मीदवारी पर भारी पड़ा। सांसदों के खिलाफ प्रबल असंतोष को भाजपा और संघ कैडर की उदासीनता ने पार्टी के लिए और नुकसानदेह बनाया। हालांकि इनसे इतर ऐसे बड़े कारण भी रहे, जिन्होंने चुनाव को व्यापक रूप से प्रभावित किया। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा अनुसूचित जाति

अवधेश राजपूत

और पिछड़ा बाहुल्य सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। इस रुझान को महज प्रत्याशी चयन या अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग की सफलता मानकर देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश में राजग का वोट घटा और विपक्षी मोर्चे का वोट बढ़ा। खराब उम्मीदवारी का आरोप कम से कम प्रधानमंत्री पर नहीं लग सकता, पर वाराणसी में उन्हें पिछली बार से 60,000 वोट कम मिले, जबकि अजय राय को पिछली बार सपा-बसपा गठबंधन और स्वयं को मिले वोट के योग से भी एक लाख सत्तर हजार वोट अधिक मिले।

प्रभावित सीटों की पड़ताल बताती है कि कांग्रेस का एक लाख रुपये देने का वादा और आरक्षण खत्म कर देने संबंधी नैरेटिव सफल हुआ। ईवीएम पर दुष्प्रचार भी सुर्खियों में रहा। एआइ द्वारा तैयार किया गया अमित शाह का आरक्षण समाप्त करने संबंधी फर्जी वीडियो जब तक पकड़ में आया, तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। भाजपा कांग्रेसी दुष्प्रचार का समय से कारगर जवाब नहीं दे पाई। बिहार की तरह अति पिछड़ा एवं अनुसूचित जातियों के गठबंधन की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में आरक्षण संबंधी दुष्प्रचार को हवा मिलती रही। जहां बिहार में जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेताओं ने इस झूठ का छोटी-छोटी सभाओं में खंडन किया, वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। एक विदेशी कंपनी द्वारा एआइ द्वारा हालिया चुनावों को प्रभावित करने की जो बात सामने आई, वह आने वाले चुनावों में तकनीकी हेराफेरी को एक खतरनाक चुनौती के रूप में दर्शाती है।

देश के आधारभूत ढांचे, मूलभूत सुविधाओं और सकल घरेलू उत्पाद में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इस बीच 'विकसित भारत' और 'विश्वगुरु' जैसे शब्दों ने एक वर्ग को अपनी खराब आर्थिक स्थिति का ध्यान दिलाया। निम्न आय वर्ग का मत परिवर्तन इसकी पुष्टि करता है कि ऐसे प्रचार के प्रति मतदाता में खीझ बनी रहेगी और उसे चुनावी मुद्दा बनाना तब तक जोखिम भरा है, जब तक बहुत बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बन जाता। इस तरह देखें तो 2024 में 2004 जैसी 'इंडिया शाइनिंग' जैसी चूक की भी पुनरावृत्ति हुई।

प्रधानमंत्री मोदी का प्रशासनिक रिकार्ड अभूतपूर्व रहा है। यह उनकी लोकप्रियता का ही कमाल है कि भाजपा पिछले दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर तीसरी बार भी सत्ता विरोधी रुझान को धता बताते हुए सत्ता में लौटी। किसी दूसरे नेता के नेतृत्व में ऐसी उपलब्धि असंभव थी। यह भी सही है कि केंद्रीय नियंत्रण और दिल्ली द्वारा थोपे गए निर्णयों ने राज्य सरकारों की गतिशीलता को प्रभावित किया है। खराब टिकट वितरण, बाहरी नेताओं का आयात, पुराने कैडर की उपेक्षा जैसी तमाम समस्याएं भी भाजपा में बढ़ती हाईकमान संस्कृति की देन हैं। ध्यान रहे कि कांग्रेस के पराभव का पहला महत्वपूर्ण कारण भी हाईकमान संस्कृति ही थी। उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत खराब परिणाम के लिए राज्य सरकार की उस कार्यप्रणाली के विश्लेषण की भी आवश्यकता है, जिसमें बाबुओं पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी ने संगठित अपराध की कमर तोड़कर प्रदेश को भय मुक्त बनाया है, किंतु जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा संगठन की उदासीनता का कारण बनी है। कुछ समस्याओं के बावजूद, जैसे केंद्र में मोदी जरूरी हैं, वैसे ही यूपी में योगी अपरिहार्य हैं। विपक्ष द्वारा योगी के भविष्य पर अनिश्चितता का जो माहौल बनाया गया, उसका शीर्ष स्तर से ससमय खंडन न होने से भी पार्टी समर्थकों में गलत संदेश गया। भाजपा के लिए अच्छी बात यह है कि उसे छोटा झटका सत्ता गंवाए बिना मिला। पिछला रिकार्ड इसका गवाह है कि पार्टी और उसका नेतृत्व अपने आपको आवश्यकता अनुरूप ढालता रहा है।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

अप्रासंगिक होते वामपंथी दल

हरेंद्र प्रताप

चुनाव नतीजे बताते हैं कि यदि वाम दल भारत विरोधी विचार नहीं छोड़ते तो इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे

तेजी से सिमट रहे हैं वाम दल ● फाइल

अठारहवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे विचारधारा वाले दो दलों-भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों के उत्कर्ष और पराभव की भी कहानी कहते हैं। राष्ट्रवादी विचार को लेकर चलने के कारण भाजपा जहां आज सत्ता के शीर्ष पर है, वहीं राष्ट्र विरोधी विचार के कारण देश में वामपंथ को नकारा जा रहा है। आज भारत में कम्युनिस्ट नामधारी कई पार्टिया हैं, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआइ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम, सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन, सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन रेड स्टार, सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन रेड फ्लैग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (यूनाइटेड) और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर आफ इंडिया (कम्युनिस्ट)। इसके अलावा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) और फारवर्ड ब्लाक के नाम में भले कम्युनिस्ट या मार्क्स या लेनिन न जुड़ा हो, पर उनकी विचारधारा भी वामपंथी है और वे वाम गठबंधन में शामिल रहे हैं। सीपीआइ से टूट कर सीपीएम, सीपीएम से टूटकर सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन और लिबरेशन से टूट कर लिबरेशन रेड स्टार और लिबरेशन रेड फ्लैग जैसे दल बने। अलोकतांत्रिक, असहिष्णु एवं हिंसा के पक्षधर वामपंथ में संवाद-सहयोग और समन्वय का अभाव तथा विदेशपरस्त नीतियां उनके विभाजन के प्रमुख कारण बनते रहे।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम तीन तो सीपीआइ दो सीटों पर जीती थी। इस बार लोकसभा चुनाव में सीपीएम केरल से एक, तमिलनाडु से एक तथा राजस्थान से एक यानी कुल तीन सीटें और सीपीआइ तमिलनाडु से दो सीटें जीती हैं। साथ ही सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन बिहार से दो तथा आरएसपी केरल से एक सीटें जीतने में सफल रही। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटे हैं। कभी इस राज्य में 28 सीटें जीतने वाली सीपीएम विगत लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस बार भी नहीं खोल पाई। इस बार के चुनाव में मात्र एक सीट पर ही वह दूसरे स्थान पर रही है। स्पष्ट है कि अब बंगाल उसके हाथ से पूरी तरह फिसल चुका है।

सीपीआइ का वर्ष 1964 में विभाजन हुआ। दूसरे धड़े ने अपना नाम सीपीएम रखा। 1967 के लोकसभा चुनाव में बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां कम्युनिस्ट पार्टी का खासा जनाधार था, वहां ये दोनों दल एक-दूसरे के खिलाफ लड़े। बंगाल में दोनों पांच-पांच सीटें जीते। धीरे-धीरे ये दोनों राज्य विशेष में अपना जनाधार बनाने लगे। त्रिपुरा, बंगाल और केरल में वामपंथी जनाधार पर सीपीएम का कब्जा तो बंगाल से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश में सीपीआइ का असर हो गया। 1991 में सीपीआइ पूरे देश में 14 सीटें जीती थी, जिसमें बिहार की हिस्सेदारी आठ थी। हालांकि 1996 के बाद से उत्तर प्रदेश तो 1998 के बाद से बिहार में सीपीआइ अपना खाता भी नहीं खोल पाई। अब बिहार के वामपंथी जनाधार पर सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन का कब्जा हो गया है। 2020 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीतने में सफल रही। सीपीआइ तथा सीपीएम दोनों दो-दो सीटें ही जीत पाईं। इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन भाजपा के आरके सिंह तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को हराने में सफल हुई। तीन सीटों पर लड़कर दो सीटों पर विजय प्राप्त होने से सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन के समर्थक उत्साहित हैं।

कुछ वामपंथी विचारक इसे वामपंथ के पुनरुद्धार से जोड़कर नई-नई भविष्यवाणी कर रहे हैं। ध्यान रहे कि बिहार में वामपंथी दलों का गठबंधन जातिवादी राजनीति के वाहक राजद के साथ है। वर्ग की बात करने वाले जाति की राजनीति करने वाले से हाथ मिलाकर इतरा रहे हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस भी है, जबकि 2008 में सीपीएम के तत्कालीन महासचिव प्रकाश करात ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि भविष्य में वह कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। केरल में तो नहीं, पर बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में वह कांग्रेस से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़े। बंगाल में कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन में आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक भी शामिल थे, लेकिन कूचबिहार और पुरुलिया में कांग्रेस ने आरएसपी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अतः चुनाव परिणाम के अगले दिन ही आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक ने यह घोषणा कर दी कि भविष्य में वे कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे।

बंगाल में जिस कांग्रेस का विरोध कर सीपीएम दशकों राज्य की सत्ता पर काबिज रही, उसी कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करती है और उसकी करारी हार होती है तो यह मतदाता नहीं कम्युनिस्ट नेतृत्व का दोष है। बंगाल आज राजनीतिक हिंसा और वोटों के अपहरण का पर्याय बन गया है। यहां इस संस्कृति का बीजारोपण सीपीएम नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने ही किया था। अब वामपंथी दल ममता बनर्जी पर लोकतंत्र के अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में लगातार हो रही हार पर सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि अब हमें भी 'आइपैक' जैसी पेशेवर संस्था का सहारा लेना चाहिए, ताकि पार्टी को फिर पटरी पर लाया जा सके। वैसे भी वर्तमान में चुनाव इंटरनेट मीडिया पर कुछ ज्यादा निर्भर होता जा रहा है।

वाम दलों की पराजय और बिखराव पर वामपंथी विचारक भले सार्वजनिक रूप से अपनी कमी को स्वीकार न करें, पर उनके अवसान का कारण वे खुद हैं। चीन के विस्तारवाद पर चुप्पी, बांग्लादेश के निर्माण का विरोध तथा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध की घोषणा से सीपीएम बेनकाब हो गई है। अगर वामपंथी भारत विरोधी विचार नहीं छोड़ेंगे तो उनका इतिहास के पन्नों में सिमटना तय है।

(लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

समन्वय की शक्ति

वास्तव में जीवन समन्वय का ही प्रतीक है। जब विभिन्न तत्वों में समन्वय है, तभी गति है। गति है तभी चेतना है। चेतना है तभी जीवन की संज्ञा है। यदि जगत के तत्वों का समन्वय भंग होता है तो वे जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। जड़ वस्तु में चेतना नहीं होती और वह निर्जीव हो जाती है। स्पष्टतः जीवन के लिए समन्वय आवश्यक है।

तत्वों के समन्वय में एक लय होती है। इस लय से राग बनता है। राग सौंदर्य को उत्पन्न करता है। सौंदर्य मन और भावना में लगाव का भाव बोध जगाता है। यही लगाव इस संसार का मूल गुण है। इसी से किसी वस्तु का अस्तित्व है। यदि हम गहनता से विचार करें तो पाएंगे कि समन्वय एक सुव्यवस्था है। यह व्यवस्था ही किसी तत्व, वस्तु या व्यक्ति के स्वरूप को निर्धारित करती है। विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि कहें तो जब हाइड्रोजन और आक्सीजन के परमाणु आपस में मिलते हैं, तब पानी बनता है। यदि ये परमाणु आपस में मिलने से मना कर दें तो पानी का अस्तित्व संभव नहीं है। उनका यह मिलना एक निश्चित व्यवस्था के तहत होता है। जब हाइड्रोजन के दो परमाणु और आक्सीजन का एक परमाणु आपस में मिलते हैं, तो पानी बनता है। यह समन्वय की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के भंग होने या किसी नए अनुपातिक संयोजन से पानी नहीं बन सकता।

समन्वय में सभी तत्व अपने अस्तित्व को एक में मिला देते हैं। जैसे हल्दी और चूने के मिलने पर हल्दी अपना पीला और चूना अपना सफेद रंग छोड़कर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। यही समन्वय का दर्शन है। वस्तुतः समन्वय से ही सामर्थ्य, शक्ति, साहस और सहकार है। जैसे हमारे शरीर के सारे अंग समन्वय के साथ मिलकर जीवन का संचालन करते हैं, ठीक वैसे ही समाज के संचालन के लिए इसके सभी अंगों का समन्वय आवश्यक है। व्यष्टि से लेकर समष्टि तक यह समन्वय हमें सभी जगह दृष्टिगोचर होता है। इसी समन्वय की शक्ति से यह पूरा ब्रह्मांड संचालित है।

डा. प्रशांत अग्निहोत्री

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

रोजगार के अवसर बढ़ाने से बनेगी बात

'सुधारों पर सहमति बनाने का समय' शीर्षक से लिखे आलेख में जीएन वाजपेयी ने केंद्र सरकार को चेताया कि वह मतदाताओं की भावनाओं पर खरा उतरने के प्रयास करे। इसके लिए सरकार को देश की जीडीपी, आर्थिक असमानता और आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गंभीरता से काम करने की भी बात कही है। सबसे पहली चीज तो यह है कि अबकी बार केंद्र में गठबंधन की सरकार है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी फैसला लेने से पहले गैर भाजपाई राजनीतिक दलों की सहमति भी प्राप्त करनी होगी। देश की जीडीपी और आर्थिक व्यवस्था के अच्छे दिन लाने के लिए सरकार को मुफ्त की योजनाएं कम, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और उद्योग-धंधों को मजबूत करने के लिए ज्यादा काम करना होगा। देश की तरक्की तब तक अधूरी है, जब तक देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब, भूखा और विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। महात्मा गांधी ने भी आर्थिक समानता लाने की बात की थी। गांधी जी के कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना धन तो हो जिससे वह अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी कर सके। उनके अनुसार जिनके पास जरूरत से ज्यादा धन है, उन्हें उसको लोक-भलाई के लिए लगाना चाहिए। किसी देश की संपन्नता का पता इससे चलता है कि वहां के नागरिकों को सही शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन मिल रहे हैं कि नहीं। इसके लिए कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने, गांवों में खपत बढ़ाने और कृषि में और सुधार लाने, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने की दरकार है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

भारत विरोधी तत्वों का बढ़ता दुस्साहस

संपादकीय आलेख 'आंतरिक सुरक्षा को खतरा' (13 जून) पढ़ा। जम्मू क्षेत्र में चार दिनों में चार आतंकी हमला गंभीर चिंता का विषय है। सुरक्षा बलों द्वारा जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आतंकी बेलगाम होते जा रहे हैं। आतंकी निर्दोष लोगों के साथ सुरक्षा बलों को भी निशाना बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आम जनता का उत्साहपूर्वक भाग लेना आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। आतंकियों ने वारदात के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों को चुना है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर जम्मू-कश्मीर में अशांति बनाए रखना चाहता है। आतंकियों को सीमा पार से मदद मिल रही है एवं देश के अंदर भी उनके मददगार छिपे हुए हैं। आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा पाकिस्तान से बातचीत की सलाह देना निराशाजनक है। सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति में बदलाव लाना चाहिए, एवं आतंकियों के सभी मददगारों के साथ कठोरतम व्यवहार करना चाहिए। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित इटली दौरे से पूर्व वहां अलगाववादियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करना चिंताजनक है। देश-विदेश में भारत विरोधी तत्वों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। एक ओर खालिस्तान समर्थक पंजाब में नए सिरे से सिर उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और इटली जैसे देशों में भी उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। भारत सरकार को जम्मू-कश्मीर और पंजाब को लेकर अधिक सतर्कता की आवश्यकता है।

ई हिमांशु शेखर, कैसपा, गया

हाल में 56 संघर्ष होना चिंताजनक

11 जून 2024 को प्रकाशित हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट चिंताजनक है। इसके अनुसार हाल में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 56 संघर्ष हुए हैं। दुनिया को तरक्की के रास्ते पर ले जाना हो तो सर्वप्रथम वैश्विक शांति जरूरी है। इसके लिए सभी देशों को संयम बरतने की जरूरत है। जो देश हथियारों के सौदागर हैं, पहले वे ही युद्ध की स्थिति पैदा करते हैं, फिर शांति की बात करते हैं और अंततः युद्ध कराकर अपने हथियार बेचते हैं। अच्छी-खासी तबाही करा कर वे युद्ध रुकवा देते हैं। इसके बाद उन देशों में निर्माण कार्यों के ठेके आदि लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के लगभग आठ दशकों में इतनी अधिक अशांति कभी नहीं रही। यह रिपोर्ट आंकड़ों में प्रकाशित हुई है लेकिन ऐसी अशांति दुनिया को किस ओर ले जा रही है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। संघर्षों में एक ओर देशों को अपने बजट का बड़ा हिस्सा सेना, गोला-बारूद आदि पर खर्च करना पड़ता है, इस कारण नागरिकों की सुविधाओं में कटौती होती हैं। यह स्थिति सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 11 करोड़ लोग लड़ाइयों के चलते विस्थापित हुए हैं या शरणार्थी शिविरों में जीवन जी रहे हैं। इन स्थितियों में संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका पर भी प्रश्न चिह्न लगा हुआ है। देशों के बीच परस्पर सौहार्द व भाईचारा आवश्यक है। इसके लिए संपूर्ण निशस्त्रीकरण और असैन्यीकरण अंतिम उपाय हैं।

रुपेश राय, दरभंगा

पोस्ट

कश्मीर में मंदिर जा रही औरतें और बच्चे बेदर्दी से मारे जा रहे हैं और जेएनयू छात्र संघ के नए अध्यक्ष नारा लगवा रहे हैं- 'जियो, जियो, जियो मेरे फलस्तीन।'

अनुपम मिश्रा@scribe9104

जब आमिर खान की फिल्म पीके आई थी तब कोर्ट ने कहा था कि फिल्म पसंद नहीं है तो मत देखो। हालांकि 'हमारे बारह' फिल्म को हिंदू देखें या न देखें, यह भारत का सुप्रीम कोर्ट और मुसलमान तय करेंगे।

चंद्र प्रकाश@CPism

कांग्रेस के खटाखट पैसा देने के चुनावी वादे ने महिलाओं को आंदोलित कर दिया है। महिलाएं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के दफ्तरों या नेताओं के घरों के चक्कर लगा रही हैं। कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। बेहतर होगा कि कांग्रेस अपने झूठे वादे के लिए महिलाओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।

संजय निरुपम@sanjaynirupam

अमेरिका के खिलाफ मैच में बुमराह की झोली में एक भी विकेट नहीं आया और विराट कोहली भी पहली गेंद पर बिना खाता खोले पैवेलियन लौट गए। अमेरिका की टीम मैच भले ही हार गई, लेकिन अपने नाम कई उपलब्धियां दर्ज कर गई।

अयाज मेमन@cricketwallah

जनपथ

बीजेपी का ना रहा ज्यादा बढ़िया हाल,
बेहतर हो अब कीजिए दल को ओवरहाल।
दल को ओवरहाल आयलिंग, ग्रीसिंग, पंपिंग,
जिससे अगली बार हो सके ऊंची जंपिंग।
देखि चुनाव रिजल्ट दिख रही झेंपी-झेंपी,
लगे काम पर झेंप झटककर अब बीजेपी।

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 63

****

दैनिक जागरण

कृत्रिमता का आवरण बहुत समय तक नहीं टिकता

परीक्षा की विश्वसनीयता

मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा यानी नीट में अनियमितता को लेकर जो सवाल उठे, उनमें से ग्रेस मार्क्स के मामले का समाधान होना संतोष की बात है। 1563 छात्रों को परीक्षा में देरी के आधार पर जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वे रद कर दिए गए हैं। इसके चलते इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी या फिर ग्रेस मार्क्स के बगैर ही काउंसलिंग में शामिल होना होगा। ऐसे लगभग सभी छात्र दोबारा परीक्षा देना पसंद करेंगे, ताकि अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकें। चूंकि ऐसे छात्रों की संख्या अधिक नहीं, इसलिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को उनकी दोबारा परीक्षा लेने में कोई समस्या नहीं होगी और वे छात्र भी संतुष्ट होंगे, जो ग्रेस मार्क्स देने के नियम का विरोध कर रहे थे। यह विरोध उचित ही था, क्योंकि यह समझना कठिन था कि परीक्षा में देरी के आधार पर इस तरह ग्रेस मार्क्स कैसे दे दिए गए कि कुछ छात्र शत-प्रतिशत नंबर पा गए? ग्रेस मार्क्स देने को लेकर इसलिए भी संदेह उभर आया था, क्योंकि एक ही परीक्षा केंद्र के कई छात्र-छात्राओं को शत-प्रतिशत अंक हासिल हो गए थे। अच्छा होगा कि भविष्य में ग्रेस मार्क्स देना बंद किया जाए और यदि छात्रों को किसी कारण परीक्षा में देरी का सामना करना पड़े तो उन्हें दोबारा परीक्षा देने की सुविधा दी जाए।

ग्रेस मार्क्स का मसला हल होने के बावजूद मामला अभी पूरी तौर पर शांत नहीं हुआ है, क्योंकि अनेक छात्र, अभिभावक और विपक्षी नेता नीट में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट अभी किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है और उसने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग पर विचार करने से भी मना कर दिया है। संभवत इसका कारण यह है कि जो भी नीट में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, वे इस परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का कोई प्रमाण नहीं दे सके हैं। यह सही है कि बिहार में कुछ साल्वर गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन अभी ऐसे प्रमाण सामने नहीं आए हैं कि प्रश्नपत्र लीक हो गए थे। शायद इसी कारण कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यह दावा कर रहे हैं कि नीट में कहीं कोई धांधली नहीं हुई। इस सबके बावजूद यह अच्छी बात नहीं कि नीट की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हुए। इस परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए को भी सवालों से दो-चार होना पड़ रहा है। उसकी परीक्षाओं को लेकर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। जहां सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, वहीं संकीर्ण स्वार्थों के चलते परीक्षाओं की विश्वसनीयता को संदिग्ध बताने वालों को बेनकाब भी करना होगा, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल और कोचिंग संस्थाएं अपना उल्लू सीधा करती दिख रही हैं।

माफिया पर अंकुश

पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कई तरह के माफिया सक्रिय हैं। नशा माफिया युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा जबकि खनन एवं वन माफिया पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है। नशा माफिया के खिलाफ पुलिस की मुहिम का असर दिख रहा है। राज्य में हर दिन नशा तस्कर और नशीले पदार्थ पकड़े जा रहे हैं। उधर, खनन माफिया और वन माफिया भी अपने कृत्यों से बाज नहीं आ रहे। इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही। नदियों एवं खड्डों से भारी मात्रा में रेत, बजरी और पत्थर निकाले जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों से ये सामग्री अन्य राज्यों में भेजी जा रही है। अवैध खनन करने पर कार्रवाई मात्र चालान तक ही सीमित रहती है। यही कारण है कि इस पर रोक नहीं लग पा रही है। हैरानी की बात है कि कई टिप्पर, ट्रक, ट्रैक्टर खनन सामग्री के साथ पकड़े जाते हैं। कुछ दिन तक इन वाहनों को सीज भी किया जाता है, लेकिन छुड़वाने के बाद फिर इन्हें अवैध खनन में झोंक दिया जाता है। अवैध खनन के प्रभाव भी नजर आने लगे हैं। राज्य की अधिकतर पेयजल योजनाएं नदियों एवं खड्डों के किनारे स्थित हैं। अवैध खनन के कारण इनमें जलस्तर भी निरंतर कम हो रहा है। अवैध खनन के कारण ही बरसात में नदी-नाले रुख बदल रहे हैं। इससे भारी नुकसान हो रहा है। भूजल स्तर में गिरावट के अलावा पेयजल परियोजनाओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। राज्य के कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। लोग पेयजल के लिए भटक रहे हैं। सरकार एवं प्रशासन को हर तरह के माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को भी सतर्क होना होगा एवं आम लोगों का सहयोग भी इसमें आवश्यक है।

प्रदेश में हर तरह के माफिया को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई अपेक्षित है

मोदी सरकार के लिए सबक

विकास सारस्वत

खराब टिकट वितरण, बाहरी नेताओं का आयात, पुराने कैडर की उपेक्षा जैसी समस्याएं भाजपा में बढ़ती हाईकमान संस्कृति की देन हैं

अवधेश राजपूत

लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता के बावजूद बहुमत के आंकड़े से कुछ पीछे रह जाने की भाजपा को कुछ न कुछ टीस जरूर होगी। हालांकि पार्टी कुछ उपलब्धियों पर संतोष का अनुभव कर सकती है। कई इलाकों में जहां वह पहले हाशिए पर रहती आई, वहां भी उसे कुछ समर्थन मिलता दिखाई दिया। जैसे उसे तमिलनाडु में 11.1 प्रतिशत वोट मिले। इसी के साथ इस राज्य में 1971 के बाद दस प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करने वाली वह पहली राष्ट्रीय पार्टी बनी। पिछले आम चुनाव में भाजपा को यहां मात्र 3.6 प्रतिशत वोट मिला था। त्रिशूर सीट जीतकर भाजपा ने केरल में पहली बार अपना खाता खोला। पूर्वी तट वाले राज्यों में भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा है। ओडिशा में पार्टी ने न केवल 21 में से 19 लोकसभा सीटें जीतीं, बल्कि राज्य में पहली बार सत्ता प्राप्त भी की। दोनों तेलुगु भाषी राज्यों आंध्र और तेलंगाना में भी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। इस विस्तार के बावजूद भाजपा को महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बंगाल में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। आशा अनुरूप सफलता न मिलने के अलग-अलग राज्यों में कारण भी अलग रहे। राजस्थान में बिगड़े जातीय समीकरण और हरियाणा में अग्निवीर योजना ने असर डाला। महाराष्ट्र में लगभग आधे विपक्ष को अपने साथ मिला लेने के कारण पक्ष-विपक्ष जैसी रेखा ही खत्म हो गई और मतदाता में इस विचारविहीन आवागमन के प्रति नाराजगी थी। सबसे अधिक चौंकाने वाले नतीजे उत्तर प्रदेश से आए, जहां पार्टी सपा से भी पीछे रह गई।

उप्र के नतीजों की पड़ताल करें तो यहां 2022 विधानसभा चुनावों में बसपा को 13 प्रतिशत से कुछ कम वोट मिला था, जो इस बार 9.44 प्रतिशत रह गया। इसका लाभ आइएनडीआइए खेमे को मिला। दलित वोट में इस छितराव के अलावा कुछ पिछड़ी जातियों का झुकाव भी आइएनडीआइए की ओर दिखा। रुहेलखंड में सैनी, दोआब में निषाद और अवध में कुर्मी वोट भाजपा से छिटका। भाजपा और उसके समर्थक दलों के बयानों के खिलाफ राजपूतों की नाराजगी ने भी कहीं-कहीं पर प्रभाव डाला। किसी बड़े राष्ट्रीय या राष्ट्रवादी मुद्दे के अभाव में यह चुनाव भारतीय राजनीति की मूल वृत्ति जातिवाद की ओर गया और अखिलेश का सामाजिक समीकरण निर्माण भाजपा की खराब उम्मीदवारी पर भारी पड़ा। सांसदों के खिलाफ प्रबल असंतोष को भाजपा और संघ कैडर की उदासीनता ने पार्टी के लिए और नुकसानदेह बनाया। हालांकि इनसे इतर ऐसे बड़े कारण भी रहे, जिन्होंने चुनाव को व्यापक रूप से प्रभावित किया। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा अनुसूचित जाति और पिछड़ा बाहुल्य सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। इस रुझान को महज प्रत्याशी चयन या अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग की सफलता मानकर देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश में राजग का वोट घटा और विपक्षी मोर्चे का वोट बढ़ा। खराब उम्मीदवारी का आरोप कम से कम प्रधानमंत्री पर नहीं लग सकता, पर वाराणसी में उन्हें पिछली बार से 60,000 वोट कम मिले, जबकि अजय राय को पिछली बार सपा-बसपा गठबंधन और स्वयं को मिले वोट के योग से भी एक लाख सत्तर हजार वोट अधिक मिले।

प्रभावित सीटों की पड़ताल बताती है कि कांग्रेस का एक लाख रुपये देने का वादा और आरक्षण खत्म कर देने संबंधी नैरेटिव सफल हुआ। ईवीएम पर दुष्प्रचार भी सुर्खियों में रहा। एआइ द्वारा तैयार किया गया अमित शाह का आरक्षण समाप्त करने संबंधी फर्जी वीडियो जब तक पकड़ में आया, तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। भाजपा कांग्रेसी दुष्प्रचार का समय से कारगर जवाब नहीं दे पाई। बिहार की तरह अति पिछड़ा एवं अनुसूचित जातियों के गठबंधन की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में आरक्षण संबंधी दुष्प्रचार को हवा मिलती रही। जहां बिहार में जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेताओं ने इस झूठ का छोटी-छोटी सभाओं में खंडन किया, वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। एक विदेशी कंपनी द्वारा एआइ द्वारा हालिया चुनावों को प्रभावित करने की जो बात सामने आई, वह आने वाले चुनावों में तकनीकी हेराफेरी को एक खतरनाक चुनौती के रूप में दर्शाती है।

देश के आधारभूत ढांचे, मूलभूत सुविधाओं और सकल घरेलू उत्पाद में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इस बीच ''विकसित भारत'' और ''विश्वगुरु'' जैसे शब्दों ने एक वर्ग को अपनी खराब आर्थिक स्थिति का ध्यान दिलाया। निम्न आय वर्ग का मत परिवर्तन इसकी पुष्टि करता है कि ऐसे प्रचार के प्रति मतदाता में खीझ बनी रहेगी और उसे चुनावी मुद्दा बनाना तब तक जोखिम भरा है, जब तक बहुत बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बन जाता। इस तरह देखें तो 2024 में 2004 जैसी 'इंडिया शाइनिंग' जैसी चूक की भी पुनरावृत्ति हुई।

प्रधानमंत्री मोदी का प्रशासनिक रिकार्ड अभूतपूर्व रहा है। यह उनकी लोकप्रियता का ही कमाल है कि भाजपा पिछले दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर तीसरी बार भी सत्ता विरोधी रुझान को धता बताते हुए सत्ता में लौटी। किसी दूसरे नेता के नेतृत्व में ऐसी उपलब्धि असंभव थी। यह भी सही है कि खराब टिकट वितरण, बाहरी नेताओं का आयात, पुराने कैडर की उपेक्षा जैसी तमाम समस्याएं भी भाजपा में बढ़ती हाईकमान संस्कृति की देन हैं। उत्तर प्रदेश में खराब परिणाम के लिए राज्य सरकार की उस कार्यप्रणाली के विश्लेषण की भी आवश्यकता है, जिसमें बाबुओं पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी ने संगठित अपराध की कमर तोड़कर प्रदेश को भय मुक्त बनाया है, किंतु जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा संगठन की उदासीनता का कारण बनी है। कुछ समस्याओं के बावजूद, जैसे केंद्र में मोदी जरूरी हैं, वैसे ही यूपी में योगी अपरिहार्य हैं। विपक्ष द्वारा योगी के भविष्य पर अनिश्चितता का जो माहौल बनाया गया, उसका शीर्ष स्तर से समय खंडन न होने से भी पार्टी समर्थकों में गलत संदेश गया। भाजपा के लिए अच्छी बात यह है कि उसे छोटा झटका सत्ता गंवाए बिना मिला। पिछला रिकार्ड इसका गवाह है कि पार्टी और उसका नेतृत्व खुद को आवश्यकता अनुरूप ढालता रहा है।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

अप्रासंगिक होते वामपंथी दल

हरेंद्र प्रताप

चुनाव नतीजे बताते हैं कि यदि वाम दल भारत विरोधी विचार नहीं छोड़ते तो इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे

तेजी से सिमट रहे हैं वाम दल। फाइल

अठारहवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे विचारधारा वाले दो दलों-भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियों के उत्कर्ष और पराभव की भी कहानी कहते हैं। राष्ट्रवादी विचार को लेकर चलने के कारण भाजपा जहां आज सत्ता के शीर्ष पर है, वहीं राष्ट्र विरोधी विचार के कारण देश में वामपंथ को नकारा जा रहा है। आज भारत में कम्युनिस्ट नामधारी कई पार्टिया हैं, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआइ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम, सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन, सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन रेड स्टार, सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन रेड फ्लैग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (यूनाइटेड) और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर आफ इंडिया (कम्युनिस्ट)। इसके अलावा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) और फारवर्ड ब्लाक के नाम में भले कम्युनिस्ट या मार्क्स या लेनिन न जुड़ा हो, पर उनकी विचारधारा भी वामपंथी है और वे वाम गठबंधन में शामिल रहे हैं। सीपीआइ से टूट कर सीपीएम, सीपीएम से टूटकर सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन और लिबरेशन से टूट कर लिबरेशन रेड स्टार और लिबरेशन रेड फ्लैग जैसे दल बने। अलोकतांत्रिक, असहिष्णु एवं हिंसा के पक्षधर वामपंथ में संवाद-सहयोग और समन्वय का अभाव तथा विदेशपरस्त नीतियां उनके विभाजन के प्रमुख कारण बनते रहे।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम तीन तो सीपीआइ दो सीटों पर जीती थी। इस बार लोकसभा चुनाव में सीपीएम केरल से एक, तमिलनाडु से एक तथा राजस्थान से एक यानी कुल तीन सीटें और सीपीआइ तमिलनाडु से दो सीटें जीती हैं। साथ ही सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन बिहार से दो तथा आरएसपी केरल से एक सीटें जीतने में सफल रही। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटे हैं। कभी इस राज्य में 28 सीटें जीतने वाली सीपीएम विगत लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस बार भी नहीं खोल पाई। इस बार के चुनाव में मात्र एक सीट पर ही वह दूसरे स्थान पर रही है। स्पष्ट है कि अब बंगाल उसके हाथ से पूरी तरह फिसल चुका है।

सीपीआइ का वर्ष 1964 में विभाजन हुआ। दूसरे धड़े ने अपना नाम सीपीएम रखा। 1967 के लोकसभा चुनाव में बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां कम्युनिस्ट पार्टी का खासा जनाधार था, वहां ये दोनों दल एक-दूसरे के खिलाफ लड़े। बंगाल में दोनों पांच-पांच सीटें जीते। धीरे-धीरे ये दोनों राज्य विशेष में अपना जनाधार बनाने लगे। त्रिपुरा, बंगाल और केरल में वामपंथी जनाधार पर सीपीएम का कब्जा तो बंगाल से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश में सीपीआइ का असर हो गया। 1991 में सीपीआइ पूरे देश में 14 सीटें जीती थी, जिसमें बिहार की हिस्सेदारी आठ थी। हालांकि 1996 के बाद से उत्तर प्रदेश तो 1998 के बाद से बिहार में सीपीआइ अपना खाता भी नहीं खोल पाई। अब बिहार के वामपंथी जनाधार पर सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन का कब्जा हो गया है। 2020 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीतने में सफल रही। सीपीआइ तथा सीपीएम दोनों दो-दो सीटें ही जीत पाईं। इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन भाजपा के आरके सिंह तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को हराने में सफल हुई। तीन सीटों पर लड़कर दो सीटों पर विजय प्राप्त होने से सीपीआइ (एमएल) लिबरेशन के समर्थक उत्साहित हैं।

कुछ वामपंथी विचारक इसे वामपंथ के पुनरुद्धार से जोड़कर नई-नई भविष्यवाणी कर रहे हैं। ध्यान रहे कि बिहार में वामपंथी दलों का गठबंधन जातिवादी राजनीति के वाहक राजद के साथ है। वर्ग की बात करने वाले जाति की राजनीति करने वाले से हाथ मिलाकर इतरा रहे हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस भी है, जबकि 2008 में सीपीएम के तत्कालीन महासचिव प्रकाश करात ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि भविष्य में वह कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। केरल में तो नहीं, पर बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में वह कांग्रेस से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़े। बंगाल में कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन में आरएसपी और फारवर्ड ब्लाक भी शामिल थे, लेकिन कूचबिहार और पुरुलिया में कांग्रेस ने आरएसपी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया।

बंगाल में जिस कांग्रेस का विरोध कर सीपीएम दशकों राज्य की सत्ता पर काबिज रही, उसी कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करती है और उसकी करारी हार होती है तो यह मतदाता नहीं कम्युनिस्ट नेतृत्व का दोष है। बंगाल आज राजनीतिक हिंसा और वोटों के अपहरण का पर्याय बन गया है। यहां इस संस्कृति का बीजारोपण सीपीएम नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने ही किया था। अब वामपंथी दल ममता बनर्जी पर लोकतंत्र के अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में लगातार हो रही हार पर सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि अब हमें भी 'आइपैक' जैसी पेशेवर संस्था का सहारा लेना चाहिए, ताकि पार्टी को फिर पटरी पर लाया जा सके। वैसे भी वर्तमान में चुनाव इंटरनेट मीडिया पर कुछ ज्यादा निर्भर होता जा रहा है।

वाम दलों की पराजय और बिखराव पर वामपंथी विचारक भले सार्वजनिक रूप से अपनी कमी को स्वीकार न करें, पर उनके अवसान का कारण वे खुद हैं। चीन के विस्तारवाद पर चुप्पी, बांग्लादेश के निर्माण का विरोध तथा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध की घोषणा से सीपीएम बेनकाब हो गई है। अगर वामपंथी भारत विरोधी विचार नहीं छोड़ेंगे तो उनका इतिहास के पन्नों में सिमटना तय है।

(लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

समन्वय की शक्ति

वास्तव में जीवन समन्वय का ही प्रतीक है। जब विभिन्न तत्वों में समन्वय है, तभी गति है। गति है तभी चेतना है। चेतना है तभी जीवन की संज्ञा है। यदि जगत के तत्वों का समन्वय भंग होता है तो वे जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। जड़ वस्तु में चेतना नहीं होती और वह निर्जीव हो जाती है। स्पष्टतः जीवन के लिए समन्वय आवश्यक है।

तत्वों के समन्वय में एक लय होती है। इस लय से राग बनता है। राग सौंदर्य को उत्पन्न करता है। सौंदर्य मन और भावना में लगाव का भाव बोध जगाता है। यही लगाव इस संसार का मूल गुण है। इसी से किसी वस्तु का अस्तित्व है। यदि हम गहनता से विचार करें तो पाएंगे कि समन्वय एक सुव्यवस्था है। यह व्यवस्था ही किसी तत्व, वस्तु या व्यक्ति के स्वरूप को निर्धारित करती है। विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि कहें तो जब हाइड्रोजन और आक्सीजन के परमाणु आपस में मिलते हैं, तब पानी बनता है। यदि ये परमाणु आपस में मिलने से मना कर दें तो पानी का अस्तित्व संभव नहीं है। उनका यह मिलना एक निश्चित व्यवस्था के तहत होता है। यह समन्वय की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के भंग होने या किसी नए अनुपातिक संयोजन से पानी नहीं बन सकता।

समन्वय में सभी तत्व अपने अस्तित्व को एक में मिला देते हैं। जैसे हल्दी और चूने के मिलने पर हल्दी अपना पीला और चूना अपना सफेद रंग छोड़कर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। यही समन्वय का दर्शन है। वस्तुतः समन्वय से ही सामर्थ्य, शक्ति, साहस और सहकार है। जैसे हमारे शरीर के सारे अंग समन्वय के साथ मिलकर जीवन का संचालन करते हैं, ठीक वैसे ही समाज के संचालन के लिए इसके सभी अंगों का समन्वय आवश्यक है। व्यष्टि से समष्टि तक यह समन्वय हमें सभी जगह दृष्टिगोचर होता है। इसी समन्वय की शक्ति से यह पूरा ब्रह्मांड संचालित है।

डा. प्रशांत अग्निहोत्री

कैंसर ने बढ़ाई युवाओं की चिंता

देवेंद्रराज सुथार

भारत में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा कैंसर के बढ़ते मामलों के साथ तालमेल बैठाने के लिए संघर्ष कर रहा है

हाल में एक गैर-लाभकारी संस्था कैंसर मुक्त फाउंडेशन (सीएमएफ) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि युवा पीढ़ी में कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है। इसकी हेल्पलाइन के माध्यम से दूसरी सलाह लेने वाले 20 प्रतिशत कैंसर रोगी 40 वर्ष से कम आयु के थे। देश में पांच में से एक कैंसर का मामला 40 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और महिलाओं में पाया जाता है और लगभग 60 प्रतिशत रोगी पुरुष होते हैं। सीएमएफ को हैदराबाद से सबसे अधिक काल प्राप्त हुए, उसके बाद मेरठ और मुंबई का स्थान रहा है।

भारत को अब दुनिया की 'कैंसर राजधानी' माना जाता है। वैसे तो कैंसर के सौ से अधिक प्रकार हैं, लेकिन इनमें प्रमुख हैं-स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, हड्डी का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, अग्न्याशय का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गुर्दे का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर, पेट का कैंसर, थायराइड कैंसर, मुंह एवं गले का कैंसर। आमतौर पर शरीर का वजन बढ़ने एवं शारीरिक गतिविधियों में कमी, दोषपूर्ण तथा असंतुलित आहार, व्यायाम न करने, नशे के रूप में अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से इस रोग का शिकार होने की आशंका अधिक होती है। चाय-काफी जैसे पेय पदार्थों के आदी व्यक्ति को भी कैंसर होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि इसमें कई हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। कैंसर एक आनुवंशिक रोग है। कई बार यह रोग कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चों में भी उनके जीन के जरिये पहुंच जाता है। दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी कैंसर के मामले हो रहे हैं।

हालांकि भारत में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा कैंसर के बढ़ते मामलों के साथ तालमेल बैठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कैंसर उपचार केंद्रों, विशेषज्ञ डाक्टरों और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कमी प्रभावी कैंसर प्रबंधन में बाधा बन रही है। भारत में बढ़ते कैंसर संकट से निपटने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। कैंसर से पीड़ित लोगों की घटती उम्र का देश के स्वास्थ्य, व्यक्तिगत और पारिवारिक बजट, अर्थव्यवस्था और समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। 40 वर्ष से कम आयु के लोग उत्पादक व्यक्ति होते हैं और कामकाजी आयु वर्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उनमें से अधिकांश के परिवार होते हैं। कैंसर से लड़ने की रणनीति पर नए सिरे से ध्यान दिया जाना चाहिए। लोगों को जीवनशैली में जरूरी बदलाव के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। कैंसर की जांच, शुरुआती पहचान और उपचार के लिए समुचित सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कैंसर पर अधिक अध्ययन और शोध भी होने चाहिए, जो बीमारी से लड़ने में उपयोगी होंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

रोजगार के अवसर बढ़ाने से बनेगी बात

'सुधारों पर सहमति बनाने का समय' शीर्षक से लिखे आलेख में जीएन बाजपेयी ने केंद्र सरकार को चेताया कि वह मतदाताओं की भावनाओं पर खरा उतरने के प्रयास करे। इसके लिए सरकार को देश की जीडीपी, आर्थिक असमानता और आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गंभीरता से काम करने की भी बात कही है। सबसे पहली चीज तो यह है कि अबकी बार केंद्र में गठबंधन की सरकार है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी फैसला लेने से पहले गैर भाजपाई राजनीतिक दलों की सहमति भी प्राप्त करनी होगी। देश की जीडीपी और आर्थिक व्यवस्था के अच्छे दिन लाने के लिए सरकार को मुफ्त की योजनाएं कम, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और उद्योग-धंधों को मजबूत करने के लिए ज्यादा काम करना होगा। देश की तरक्की तब तक अधूरी है, जब तक देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब, भूखा और विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांधी जी के कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना धन तो हो जिससे वह अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी कर सके। उनके अनुसार जिनके पास जरूरत से ज्यादा धन है, उन्हें उसको लोक-भलाई के लिए लगाना चाहिए। किसी देश की संपन्नता का पता इससे चलता है कि वहां के नागरिकों को सही शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन मिल रहे हैं कि नहीं। इसके लिए कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने, गांवों में खपत बढ़ाने और कृषि में और सुधार लाने, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने की दरकार है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

मजबूत है लोकतंत्र का आधार

'निराधार थे लोकतंत्र पर उठे सवाल' शीर्षक आलेख में गिरीश्वर मिश्र ने इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा उछाले गए सभी आरोपों को जनता द्वारा सिरे से खारिज किए जाने का चित्रण किया है। देखा जाए तो पूरे चुनावी परिदृश्य में विपक्ष शुरू से रिजल्ट आने तक सिलसिलेवार आरोपों का पुलिंदा खोलते गया और हर बार मात खाता गया। चुनाव से पूर्व कांग्रेस लोकतंत्र एवं संविधान को खतरे में बताकर लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश करने लगी। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की देखा-देखी इसके अन्य सहयोगी दल भी लोकतंत्र एवं संविधान खतरे में है, की रट लगाते रहे। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल उठा कि संविधान बचाने से उनका वास्तविक मतलब क्या है? वह संविधान के लिए ऐसा क्या नहीं करेंगे कि संविधान बचा रहेगा? कांग्रेस को याद दिलाया गया कि मनमोहन सिंह सरकार ने न केवल संविधान के अनुच्छेद-338 का उल्लघंन किया, बल्कि संविधान निर्माताओं की उस बात को भी नहीं माना, जिसके तहत उन्होंने अनुसूचित जातियों से जुड़े मामलों को देखने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रविधान किया। अपनी हार की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़ा करने लगी कि ईवीएम मोदी के पक्ष में रिजल्ट उगलेगा। विपक्ष के सभी आरोपों को नकारते हुए लोकतंत्र का स्तंभ और मजबूत हुआ है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

निरंतरता का संदेश

लोकसभा चुनाव में भाजपा को आशा से कम सीटें मिलीं, लेकिन कई आशावादी उपलब्धियां भी हासिल हुईं। जैसे 1989 के बाद से 240 सीटें भी भाजपा के अतिरिक्त किसी दल को नहीं मिली हैं। 60 साल के बाद मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ओडिशा में पहली बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है। 10 साल के बाद थोड़ी बहुत सत्ता विरोधी लहर तो स्वाभाविक है, लेकिन आज भी मोदी देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। यह लोकप्रियता उन्हें जमीन से जुड़े कार्य और कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के कारण मिली है। यह गौर करने लायक है कि इतना विकास कोविड महामारी के कारण दो वर्ष बर्बाद होने के उपरांत हुआ है। मोदी सरकार निरंतरता का संदेश दे रही है, लेकिन उसे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कुछ क्षेत्रों में मिशन मोड पर काम करना होगा। ये क्षेत्र हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, मंहगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण। न्याय के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है।

सीपी बंसल, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

भारतीयों की चिंता

यह मर्माहत कर देने वाली खबर है कि कुवैती शहर मंगफ में एक आवासीय इमारत में आग लगने से कम से कम 40 भारतीयों की जान चली गई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आग उसी इमारत में लगी, जहां दर्जनों कर्मचारी रहा करते थे, उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। निचली मंजिल पर लगी आग ऊपर फैलती चली गई। अधिकांश हताहत दक्षिण भारतीय राज्य केरल और तमिलनाडु से हैं। करीब 50 भारतीय घायल भी हुए हैं। घायलों में नेपाली कामगार भी शामिल हैं। इसमें तो कोई दोराय नहीं कि ये कर्मचारी या मजदूर बहुत अमानवीय माहौल में रह रहे थे। इमारत में करीब 196 कर्मचारी रह रहे थे। जाहिर है, इमारत में काफी भीड़भाड़ थी और इसी वजह से कर्मचारी आग से घिर गए। कुवैती उप-प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ अल-सबा ने इमारत के मालिकों पर लालच का आरोप लगाया और कहा कि भवन मानकों के उल्लंघन के चलते यह त्रासदी हुई। वैसे, सिर्फ वजह बताने से काम नहीं चलेगा, हमें यह देखना होगा कि क्या कुवैती सरकार दोषियों के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी?

ध्यान रहे, तमाम अरब देशों में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं। छोटे से मुल्क कुवैत की अगर बात करें, तो वहां आबादी का दो-तिहाई हिस्सा विदेशी श्रमिकों से बना है। वहां पर भारतीय श्रमिकों की संख्या अच्छी-खासी है। इतने बड़े हादसे के बाद प्रशासन जागता लग रहा है। प्रशासन सफाई दे रहा है कि ऐसे आवासों में भीड़भाड़ को लेकर अक्सर चेतावनियां जारी की जाती थीं, पर भवन मालिकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस त्रासदी पर मानवाधिकार समूहों ने भी चिंता जताई है। अब चिंता से आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। तमाम अरब देशों में मजदूरों की स्थिति बहुत अमानवीय है। इन सभी देशों में मजदूरों की सुरक्षा चाक-चौबंद करने पर ध्यान देना होगा। भारत सरकार को अपनी ओर से भरपूर दबाव डालना होगा, ताकि अरब देशों में हमारे कामगारों के प्रति संजीदगी बढ़े। देश के लाखों मजदूरों को रोजगार के लिए विदेश जाना पड़ता है, तो विदेश गए मजदूरों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है। सबकी नजरें भारत सरकार पर है कि वह आगामी दिनों में अपने लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाती है?

भारत सरकार को अपनी ओर से भरपूर दबाव डालना होगा, ताकि अरब देशों और अन्य जगहों पर भारतीय कामगारों के प्रति पर्याप्त संवेदनशीलता बढ़े।

अरब देशों ही नहीं, यूक्रेन, रूस जैसे अनेक देशों में भारतीयों की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। मिसाल के लिए, युवा काम की तलाश में रूस जाते हैं और उन्हें रूस में सैनिक बना दिया जाता है। रूसी सेना की ओर से लड़ते हुए भारतीय हमें बहुत चिंता में डाल रहे हैं। सरकार को आपत्ति जताने से आगे जाकर अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यहां यह जान लेना चाहिए कि विदेश में भारतीयों की मौत चिंता की एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगे गए एक जवाब के मुताबिक, अकेले साल 2020 में विदेश में कुल 11,439 भारतीयों की मौत हुई। अगर छात्रों की बात करें, तो साल 2018 के बाद से विदेश में 403 भारतीय छात्रों की विभिन्न वजहों से मौत हुई है। इनमें से सर्वाधिक 91 छात्र कनाडा में मारे गए हैं। सोचने वाली बात है, भारतीय छात्रों की मौत के मामले में कनाडा, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों का दामन साफ नहीं है। अतः भारत सरकार को तगड़ी मोर्चाबंदी करनी पड़ेगी और विदेश जाने वालों को भी अपनी सुरक्षा के प्रति सजग होना पड़ेगा।

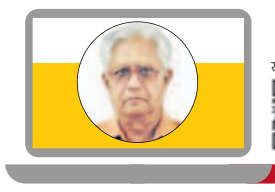

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 14 जून, 1949

रियासतों का एकीकरण

स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होने वाला काम रियासतों के एकीकरण का हुआ है। इसे सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन कोई यह न मानना चाहे तो भी यह तो निर्विवाद है कि सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कामों में प्रमुख यह अवश्य है। यही कारण है कि सरकारी और गैरसरकारी सभी लोग इसका खास तौर पर उल्लेख करते हैं और इस पर गर्वानुभव करते हैं। भारत सरकार के रियासती मंत्रालय के मंत्री श्री एम.के. वेलोडी ने रेडियो-भेंट में रविवार को इस संबंध में जो प्रकाश डाला, वह बोधप्रद है। ५ जुलाई, १९४७ को यह मंत्रालय बना था और आजकल १९४९ का जून है। इस प्रकार लगभग दो वर्ष का वह काम है जो इस विभाग ने इस दिशा में किया है। पहले जहां ६०० से ऊपर रियासतें थीं और उनका काम राष्ट्रीय जागृति को दबाये रखने में विदेशी सरकार को सहारा देना था, वहां अब इनी-गिनी रियासतें देश के नक्शे में रह गई हैं। अधिकांश या तो भारतीय प्रान्तों में मिल गई हैं, या अपनी-अपनी अलग सत्ता समाप्त कर अन्य रियासतों के साथ संघबद्ध हो गई हैं, अथवा केन्द्रीय शासन प्रबन्ध में हैं। यह कुछ कम काम नहीं है, खासकर तब इसका महत्व और बढ़ जाता है, जब श्री वेलोडी के कथनानुसार इसका उद्देश्य रियासतों का सफाया नहीं, बल्कि उन्हें एक समान इकाइयां बनाना तथा वहां के निवासियों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर ऊंचा करना है। यह लक्ष्य अपने आप में तो अच्छा है ही, भारत को संयुक्त व शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से भी इसका महत्व है। इसी दृष्टि से सभी प्रगतिशील व्यक्तियों ने इसका स्वागत किया है और सरदार पटेल की इसके लिए सराहना की है, जिनके निर्देशन में यह कार्य हुआ है।

श्री वेलोडी ने बताया है कि विभिन्न रियासतों को जीवन के सभी क्षेत्रों में- राजनीतिक, शासनिक और आर्थिक प्रांतों के समकक्ष बनाना ही मंत्रालय ने अपना लक्ष्य रखा है। शासन की सन्तोषजनक व्यवस्था के साथ-साथ लोकतंत्रीय संस्थाओं की वृद्धि भी उसका उद्देश्य रहा है और रियासतों के एकीकरण में दृष्टि यह रही है कि जो रियासत स्वावलम्बी इकाई के रूप में न रह सके, उसे अलग न रखकर प्रान्त में अन्य रियासत अथवा रियासतों के साथ संघबद्ध कर दिया जाये।

वर्षा जल की बाट जोहते जलाशय

यहां स्कैन करें

दिनेश मिश्र | जल विशेषज्ञ

दिल्ली और देश में जो मौजूदा जल संकट है, वह हमारे जल-तंत्र की नाकामी है। जरूरतमंदों तक पानी पहुंचाने की हमारी कवायद ध्वस्त हो चुकी है, इसलिए नए प्रयासों की जरूरत है।

बिहार में आजादी के बाद 1950-51-52 में भयंकर अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। अकाल घोषित तो नहीं हुआ था, पर परिस्थितियां कम भयावह नहीं थीं। तब म्यांमार जैसे छोटे-छोटे मुल्कों से भी हमें अनाज मंगवाना पड़ा था। उस अकाल की गाथा खोजते-खोजते हमारी भेंट रोहतास जिले के लहेरी गांव, प्रखंड सासाराम के एक 88 वर्षीय बुजुर्ग शिवपूजन सिंह से हुई। उन्होंने लंबी वार्ता के दौरान बताया कि तब तो हमलोग बच्चे ही थे, फिर भी बहुत सी बातें याद हैं। 'हमारे पीने के पानी की कमी उस सूखे के समय भी नहीं हुई थी। पीने का पानी कुएं से हमेशा मिल जाता था, क्योंकि तालाब भले ही सूख जाएं, पर कुआं कभी नहीं सूखता था। जानवरों को भी वही पानी दिया जाता था। अब तो कुएं बचे ही नहीं हैं और उनके नष्ट हो जाने की एक वजह यह है कि उन दिनों आज की तरह बोरिंग नहीं थी।'

इस घटना के 70-75 साल बाद अब जो नदियों, तालाबों, झरनों और अन्य जल-स्रोतों की दुर्दशा हुई है, वह सचमुच चिंताजनक है। केंद्रीय जल आयोग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 150 प्रमुख जलाशयों का जलस्तर 22 फीसदी ही रह गया है। यही नहीं, इनमें से चार जलाशय तो मार्च महीने में ही सूख गए थे। यह गंभीर होते जल संकट का स्पष्ट संकेत है। अब पानी के लिए इस कदर मारामारी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की खबरें रोजाना अखबारों में छप रही हैं।

बेशक, इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं। कुओं की जगह ले चुके बोरिंग, लिफ्ट आदि आधुनिक संयंत्रों ने पानी की उपलब्धता उन लोगों के लिए बढ़ाई है, जो इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। आज से लगभग बीस साल पहले गुजरात से यह पहली सूचना मिलने लगी थी कि अगर किसी गरीब किसान के खेत से लगे बड़े आदमी के खेत हों, तो छोटे किसान की बोरिंग सूख जाती है, क्योंकि वह समृद्ध किसान की बोरिंग के मुकाबले और गहराई तक जाने की कीमत नहीं चुका सकता था।

नदियों के उद्गम के आसपास बने जलाशयों ने पानी के वितरण और निचले क्षेत्रों में उसकी उपलब्धता पर प्रश्न-चिह्न लगा दिए हैं। 1960 के उत्तरार्द्ध से आधुनिक खेती के विस्तार के कारण सिंचाई के लिए पानी की मांग बेतहाशा बढ़ गई है। इस पानी के उपयोग से जहां एक ओर कृषि उत्पादन बढ़ा, तो दूसरी ओर बहुत सी खेती की जमीन में लवणीयता भी बढ़ी है, जिससे उन क्षेत्रों में उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है। पिछले कृषि वर्ष में हरियाणा और दिल्ली के बीच यमुना के पानी को लेकर बाढ़ और सूखे, दोनों मौसम में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले तंत्र की भूमिका आलोचना के दायरे में रही। अभी ही दिल्ली में जो जल संकट है, वह जल-तंत्र की विफलता की ओर इशारा करता है और बताता है कि जरूरतमंदों तक पानी पहुंचाने की हमारी कवायद किस कदर ध्वस्त हो चुकी है। जब नदियों से पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही, तो इस विफलता की जिम्मेदारी क्या तय नहीं होनी चाहिए?

सवाल विभाग की प्राथमिकताओं का भी है। इस शताब्दी के प्रारंभ में पटना में गंगा के किनारे एक मरीन ड्राइव बनाने की योजना किसी को भी आकर्षक लगती थी। मगर यह भी सच था कि राज्य की शिक्षित जनता का आंकड़ा कमोबेश वही था, जो देश के स्तर पर सन् 1961 में था। मरीन ड्राइव की योजना पर आह्लादित होने वाली जनता में से शायद ही किसी ने यह आवाज उठाई कि मरीन ड्राइव बनाने से पहले शिक्षा के सुधार का कार्यक्रम हाथ में लेना चाहिए था। यह नदी सैरगाह अब बन चुका है और सफल भी है, लेकिन प्राथमिकता की बात करें, तो पहले कुछ और होना चाहिए था।

बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं का अलग ही किस्सा है। विभाग आजादी के बाद से नदियों के किनारे तटबंध बनाने के अलावा कुछ कर नहीं पाया है, जबकि देश का बाढ़ प्रवण क्षेत्र, यानी किसी न किसी समय बाढ़ से प्रभावित होने वाला इलाका, आजादी के बाद से 12वीं योजना बीत जाने के बाद दोगुना हो गया है। बिहार का 68.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, जो आजादी के समय केवल 25 लाख हेक्टेयर था। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग पांच करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, जो आजादी के समय इसका आधा था। अब तो शहरों-महानगरों की बाढ़ नई समस्या का रूप ले चुकी है।

जल-संकट का प्रशासनिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई सिंचाई या बाढ़ नियंत्रण की योजना तैयार की जाती है, तो उसके कुछ उद्देश्य, पूरा होने का समय, लागत खर्च आदि की व्याख्या की जाती है और उसके बाद लाभ-लागत गुणक निर्धारित किया जाता है कि योजना पर जो खर्च किया जाएगा, उसके अनुरूप लाभ कितना होगा? इतनी सूचना राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल के बजट भाषण में जरूर बताई जाती है। इस पर बहस भी होती है और अगर उसमें किसी सुधार या परिवर्तन की आवाज उठती है, तो उसका संज्ञान भी लिया जाता है। बताते हैं कि विधानसभा में जब बजट और योजना पर बहस होती है, तब वहां से जो भी प्रश्न उठते हैं, उनको मुख्य अभियंताओं को भेज दिया जाता है, जिस पर वे अपना मंतव्य देकर वापस कर देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से बजट प्रस्ताव और उस पर हुई बहस को लेकर इन अधिकारियों की कोई अलग से बैठक नहीं होती और ज्यादातर काम विभागीय स्तर पर कर लिया जाता है।

स्पष्ट है, हमारी मूल समस्या जवाबदेही की है कि व्यवस्था जो कुछ भी हासिल करने का विचार रखती है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाती है या नहीं? इसके लिए अंग्रेजी में 'अकाउंट' और 'अकाउंटेबिलिटी' जैसे शब्दों का उपयोग होता है। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर हैं नहीं। अकाउंट लेखा-जोखा है, जबकि अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी है। ऑडिट के बाद अकाउंट का काम प्रायः समाप्त हो जाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तब तक पीछा नहीं छोड़ती, जब तक उद्देश्य पूरे न हो जाएं। जल संकट का यही निदान है। संबंधित विभागों को सोचना चाहिए कि क्या 1950 के दशक की परिस्थितियों से निपट लेने के हम सक्षम हो पाए हैं?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इंसानी फितरत को समझने में नाकामी और एग्जिट पोल

यहां स्कैन करें

बीजू डोमिनिक | सीईओ, फाइनल माइल कंसल्टिंग

दो दिन पहले आपने क्या नाश्ता किया? चूंकि नाश्ता रोजमर्रा का मामला है, अतः नाश्ते के फैसले पर ज्यादा विचार नहीं किया जाता है। हममें से अधिकांश लोग भूल जाते हैं कि हमने दो दिन पहले क्या भोजन ग्रहण किया था। मगर क्या हममें से बहुत लोग भूल गए होंगे कि हमने 2024 के आम चुनाव में किस प्रत्याशी को वोट दिया था? मतदान करना कोई रोजमर्रा का व्यवहार नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए, मतदान एक बहुत सोच-विचारकर लिया गया फैसला है। यह संभव नहीं है कि कोई यह भूल जाए कि उसने किस राजनीतिक दल को वोट दिया था। यदि ऐसा है, तो ज्यादातर एग्जिट पोल सही भविष्यवाणी में नाकाम क्यों रहे?

हर निर्वाचन क्षेत्र के बड़े मतदाताओं का सटीक प्रतिनिधित्व करने वाले सही नमूनों का चयन न कर पाना, आकलन में गलती का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। सर्वोत्तम सांख्यिकीय तरीकों का इस्तेमाल करने के बावजूद मतदाताओं के फैसले का सटीक मूल्यांकन आसान नहीं होता। भारत में बाजार अनुसंधान उद्योग कई दशक पुराना है और कई एजेंसियों ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे उपभोक्ता या मतदान अनुसंधान किए हैं। ऐसे में, यह यकीन करना मुश्किल है कि उन्होंने भारत जैसे जटिल देश को समझने के लिए जरूरी सांख्यिकीय तरीकों का अब तक पता नहीं लगाया है।

यह संभव नहीं कि कोई यह भूल जाए कि उसने किस दल को वोट दिया है। यदि ऐसा है, तो ज्यादातर एग्जिट पोल सही अनुमान लगाने में नाकाम क्यों रहे?

एग्जिट पोल के नतीजे गलत क्यों थे, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। अपनी किताब *प्राइवेट ट्रुथ्स, पब्लिक लाइज : द सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रिफरेंस फाल्सिफिकेशन* में अर्थशास्त्री तिमुर कुरन 'वरीयता मिथ्याकरण' की बात करते हैं। कुरन के अनुसार, यह वास्तविक या कथित सामाजिक दबावों के तहत किसी के वास्तविक विचारों को गलत ढंग से पेश करने का कार्य है। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा अक्सर होता है, जब हम किसी मेजबान को बताते हैं कि हम परोसे गए भोजन का खूब आनंद ले रहे हैं, जबकि हमें भोजन बेस्वाद लग रहा होता है।

समाज में ऐसे व्यवहार की व्यापकता को देखते हुए, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मतदाताओं ने अपना वोट किसी खास सियासी दल को दिया हो, पर जब एग्जिट पोल करने वालों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने दूसरे दल का नाम बता दिया? मतदाता आखिर ऐसा क्यों करते हैं? उनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों हो जाता है?

दरअसल, सामाजिक जीव होने के नाते, इंसान इस बात की बहुत चिंता करता है कि दूसरे लोग उसके विचारों व कार्यों के बारे में क्या सोचते हैं? कई बार लोग बहुमत के विचार के साथ दिखने मात्र के लिए गलत जवाब देते हैं। इसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सोलोमन एश के एक प्रसिद्ध प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें, तो लोगों से अगर अलग-अलग पूछा जाए, तो वे सही जवाब दे सकते हैं, मगर जब तीन की पसंद चौथा आदमी सुन लेता है, तो वह भी उसी पसंद के पक्ष में फैसला सुना देता है। यह एक तरह की नकल है। शायद ही कोई व्यक्ति अल्पमत में दिखना चाहता है। मतदान केंद्र के अंदर लोगों को भरोसा होता है कि उनका व्यवहार गोपनीय रहेगा, इसलिए वहां वे अपनी सोच के हिसाब से व्यवहार करते हैं, पर मतदान केंद्र के बाहर उन पर बहुमत के विचारों से सहमत होने का दबाव होता है। ऐसे में, यह मुमकिन है कि इस साल के एग्जिट पोल में कई उत्तरदाताओं ने बहुमत के हिसाब से अपना फैसला जाहिर किया है। इन एग्जिट पोल में हमने देखा है कि लोग जो कहते हैं और जो करते हैं, दोनों के बीच अंतर स्पष्ट है। अधिकांश अनुसंधान एजेंसियां मतदाताओं के इस रवैये को समझने में नाकाम हैं।

किसी भी सर्वेक्षण में व्यावहारिक पहलू को समझना जरूरी है। मिसाल के लिए, यदि हम ड्राइवरों को सुरक्षित गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं, तो नई सड़कों की इंजीनियरिंग दुरुस्त करने का क्या मतलब है? यदि हम बड़े पैमाने पर लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीका लगवाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, तो बीमारियों से बचाव के लिए कारगर टीकों के आविष्कार का क्या मतलब है? हमें मानव व्यवहार को समझना होगा। सर्वेक्षण एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें हमें नए सिरे से सोचने और नए सिरे से काम करने की जरूरत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

रामराज्य तभी आएगा

आज दुनिया में तमाम तरह के ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, लेकिन किसी की समकक्षता गोस्वामी जी के ग्रंथों से नहीं होती। गोस्वामी जी ने वही किया, जो राम जी ने किया। कहा जाता है कि इस दुनिया में *रामचरितमानस* फिर बनने वाला नहीं है। कई लोग *रामायण* लिखकर गोस्वामी तुलसीदास बनना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। लेकिन लोगों के पास राम जी हों, तब तो ऐसे ग्रंथ की रचना हो। यदि राम जी मिल भी गए, तो तुलसीदास जी का मन कहां से लाएंगे। पूरी दुनिया में इस स्तर के महाकाव्य की रचना नहीं हो पाई। तुलसीदास जी की कोई तुलना नहीं है। उन जैसी प्रतिभा कहां से आएगी?

इस दुनिया में जितने मांगलिक भाव हैं, उन सबका समुद्र ईश्वर माना जाता है। हमारा ईश्वर समुद्र है, उसके अवतार भी समुद्र हैं। यह केवल परोक्ष ज्ञान में नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान में भी है। रावण को भी अपरोक्ष ज्ञान होता, तो वह महापाप नहीं करता। ज्ञान उसके हृदय में कभी नहीं उतरा। उसे केवल ऊपरी ज्ञान था। राम जी मनुष्यावतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञान का संग्रह किया। अपने चरित्र में ज्ञान को उतारा और अपने संपूर्ण अवतार काल में लोगों को वह ज्ञान दिया, गुणों को प्रसारित किया, तभी रामराज्य की स्थापना हो पाई। सभी लोग उसी तरह से जीवन जीने लगे। याद रखिए, रामराज्य में लोग केवल राम जी से ही प्रेम नहीं कर रहे हैं, उनमें परस्पर भी प्रीति है- *सब नर करहीं परस्पर प्रीती।*

ईश्वर के लिए समर्पित होकर हम कर्म करें, तो इससे ऐसे समाज की रचना होती है, जो समाजवाद कभी नहीं कर सकता, लोकतांत्रिक पार्टियां ऐसा नहीं कर सकतीं। ईश्वर को नहीं मानने वाला भी कर्मयोगी कहलाता है, महर्षि अरविंद ने ऐसा उल्लेख किया है। वेदों, पुराणों को नहीं मानने वाला भी बोलता है कि मैं कर्मयोगी हूं। वेदों से जो धारा आई थी *वाल्मीकि रामायण* में, उसमें एक अद्भुत स्थापना हुई। गोस्वामी जी केवल कर्म की शिक्षा नहीं देते, केवल ज्ञान या भक्ति की शिक्षा नहीं देते, ईश्वर को समर्पित होकर, जो विधान शास्त्रों में वर्णित है, उनके अनुरूप स्वयं चलते भी हैं।

हम पहले स्वयं को चरित्रवान बनाते हैं, उसके बाद ही दूसरों को प्रेरित करते हैं। राम जी पहले स्वयं चरित्र शिरोमणि हैं, उसके बाद ही उनका व्यापक प्रभाव समाज पर दिखने लगता है।

कहा जाता है कि हमारे ऋषियों ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। भारत में अभी भी विश्व गुरुत्व है। मगर याद रखना, छोटे उद्देश्यों के लिए जीकर कोई विश्व गुरु नहीं होता। मनु ने कहा कि श्रेष्ठ ऋषियों ने संपूर्ण संसार को चरित्र की शिक्षा दी। हम पहले स्वयं को चरित्रवान बनाते हैं और उसके बाद ही दूसरों को चरित्रवान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। रामराज्य में भी ऐसा ही होता है। राम जी पहले स्वयं चरित्र शिरोमणि हैं, उसके बाद ही उनका व्यापक प्रभाव समाज पर दिखने लगता है। संसार को चरित्र की शिक्षा भारत ने ही दी है।

रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामनरेशाचार्य

पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड' | प्रधानमंत्री, नेपाल

गणतंत्रवाद, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय हमारे संविधान के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनमें से किसी एक के अभाव में दूसरा अधूरा है, इसलिए संघवाद को लागू करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

दक्षिण भारत में भी दबदबा बनाती भाजपा

इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण की 130 सीटों में से 29 पर सफलता हासिल की है और यह साबित कर दिया है कि भारत के दक्षिणी हिस्से में भी वह अपना दबदबा बढ़ा रही है। दक्षिण का राजनीतिक समीकरण भाजपा की राजनीति के साथ एक बड़े बदलाव के लिए तैयार दिख रहा है। मूलतः भाजपा को उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता रहा है और तमाम प्रयासों के बावजूद कर्नाटक को छोड़कर दक्षिणी राज्यों में यह अपनी पैठ नहीं बना सकी थी, मगर इस बार के चुनाव में चीजें बदल गई हैं। यह सही है कि पिछले आम चुनाव की तरह इस बार भी 29 सीटों पर भगवा झंडा लहरा पाया है, लेकिन इस बार उसे तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी दक्षिणी राज्यों में सीटें मिली हैं, इसलिए उम्मीद यही है कि यह सिलसिला आगे और बढ़ेगा। इस साल पहली बार भाजपा ने केरल में भी सफलता हासिल की है, इसलिए यह कह सकते हैं कि देवताओं की भूमि में भाजपा का खाता खोलना एक स्वर्णिम संकेत है। बेशक, कर्नाटक और तमिलनाडु में मन-मुताबिक प्रदर्शन नहीं हो पाया, लेकिन बाकी दक्षिणी राज्यों में भाजपा ने जो मेहनत की है, उसका असर दिख रहा है। दक्षिण में भाजपा का बढ़ता दबदबा पार्टी के लिए सुखद है। अब यह सही मायने में अखिल भारतीय पार्टी कहलाने की अधिकारी है। यह कह सकते हैं कि आने वाले समय में भाजपा के लिए दक्षिण में भी अपार संभावनाएं बनेंगी।

आरआर मनमोहन, टिप्पणीकार

जीत के सूत्रधार

तमिलनाडु में अन्नामलाई चुनाव हार गए। एक आईपीएस, जो नौकरी छोड़कर राजनीति में कूदा और भारत के दक्षिणी छोर पर हिंदुत्व की राजनीति का ध्वजवाहक बना, वह अपना चुनाव हार गया। मगर हारा कौन नहीं है? खुद दीनदयाल उपाध्याय अपना एकमात्र चुनाव हार गए थे। अपनी भाषण शैली के कारण जन-जन में लोकप्रिय अटल बिहारी वाजपेयी को भी पराजय झेलनी पड़ी थी। जो व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए जीता है, उसके लिए हार-जीत उसके मकसद का महज छोटा सा हिस्सा होता है। अन्नामलाई का मिशन है, तमिलनाडु में हिंदुत्व की राजनीति को स्थापित करना। हालांकि, पेरियारवाद के दलदल में कमल खिलाना थोड़ा कठिन कार्य लगता है, लेकिन इन चुनावों में राज्य के 11 प्रतिशत से अधिक वोट भाजपा को मिले हैं। जो लोग तमिलनाडु की राजनीति समझते हैं, वे जानते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है। यह स्पष्ट है कि दक्षिण का किला दरक चुका है। देर-सबेर यहां भी भगवा ध्वज लहराएगा और इस मुहिम के नायक के रूप में अन्नामलाई याद किए जाएंगे।

विकल्प सिंह ठाकुर, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
दक्षिण में भाजपा

उत्तर भारत जैसे नहीं हैं यहां के हालात

उत्तर और दक्षिण भारत में एक बुनियादी अंतर है। उत्तर भारत का समाज अब भी तरक्की के पायदान पर काफी पीछे है, इसी कारण वहां की राजनीतिक व्यवस्था भी गुणवत्तापूर्ण नहीं मानी जाती। इसके उलट, दक्षिण का समाज कहीं अधिक उन्नत है। यहां के लोग उत्तर भारतीयों की तुलना में कहीं अधिक जागरूक और संवेदनशील हैं। इसी कारण यहां की राजनीति भी उत्तर भारत से अलग है। यहां उस तरह जाति-धर्म की राजनीति नहीं होती, जिस तरह उत्तर भारत में होती है। यही मूल वजह है कि भगवा पार्टी को अपनी जगह बनाने में यहां इतना वक्त लगा। खैर, इससे इनकार नहीं है कि इस बार भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है और कुल 130 सीटों में से उसे 29 सीटें मिली हैं, जबकि पिछले आम चुनाव में उसे कर्नाटक से ही 25 सीटें मिली थीं और शेष चार सीटें तेलंगाना से मिली थीं। मगर इस बार तमिलनाडु छोड़ तमाम सूबों में मिली जीत के आधार पर यह नहीं कह सकते कि भाजपा दक्षिण भारत की भी पार्टी बन गई है, क्योंकि अब भी यहां क्षेत्रीय पार्टियों का खासा दबदबा है, जो जल्द खत्म होने वाला नहीं है।

आंकड़ों के मुताबिक, इस बार उसे आंध्र प्रदेश में तीन, तो तेलंगाना में आठ सीटें मिली हैं। केरल में उसका खाता खुला है। हालांकि, कर्नाटक में उसे 17 सीटें जरूर मिली हैं, पर यहां से पिछली बार उसके 25 सांसद चुने गए थे। इस पर क्या कहेंगे आप? अगर भाजपा का असर वास्तव में होता, तो यहां की सीट वह नहीं गंवाती। तमिलनाडु में ही अन्नामलाई जैसे उसके कद्दावर नेता जीतने में सफल नहीं हो सके, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं की नजर में वह मुख्यमंत्री के चेहरों में एक हैं। इसी तरह, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का साथ यदि नहीं मिला होता, तो भाजपा के लिए अपना ग्राफ सुधारना मुश्किल होता। इन सबके उलट, उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर टिकी हुई है। जहां-जहां भी उसका गठबंधन है, वहां पर वह आमतौर पर बड़े भाई की भूमिका में है।

कुल मिलाकर, हमें उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति का गहन विश्लेषण करते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। सिर्फ एक चुनावी जीत से किसी के भाग्य का निर्धारण नहीं हो सकता। यदि समर्थकों की नजर में दक्षिण में पूर्ववत 29 सीटों पर ही रह जाना भाजपा की बड़ी सफलता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर 303 सीटों से घटकर 240 पर आ जाना भाजपा की बड़ी हार मानी जानी चाहिए। कहने का अर्थ यही है कि भाजपा भले एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन दक्षिण का दुर्ग फिलहाल काफी मजबूत है।

कुणाल, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । मुंबई । शुक्रवार, 14 जून 2024

सरकार का साथ

कुवैत के मंगाफ शहर की छहमंजिला इमारत में लगी आग से मृतकों की बड़ी संख्या तो परेशान कर ही रही है, जिन हालात में यह घटना हुई, उससे भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं।

कंपनी मालिकों का लालच | शुरुआती खबरों के मुताबिक, उस इमारत में 195 लोग रह रहे थे जो एक ही कंपनी के वर्कर थे। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मौतें धुएं के कारण दम घुटने से हुई। इस मामले में आगे की जांच चल रही है, लेकिन कुवैत सरकार के मुताबिक पहली नजर में इस हादसे की वजह तय मानदंडों का उल्लंघन है। कुवैत के उप-प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ अल-सबह ने कहा कि कंपनी मालिकों के लालच के कारण यह घटना हुई।

कुवैत हादसे ने छोड़े कई सवाल

श्रमिकों की हालत | इस घटना ने एक बार फिर काम के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की जीवनदशा का सवाल सामने कर दिया है। कुवैत में भी मानवाधिकार समूह यह मसला उठाते रहे हैं। कुवैत के लिए यह ज्यादा जरूरी मुद्दा इसलिए भी है कि इसकी आबादी का करीब दो तिहाई हिस्सा विदेश से आने वाले मजदूरों का है। यहां की इकॉनमी इन प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है।

भारतीय सबसे ज्यादा | इस घटना के पीड़ितों में सबसे ज्यादा भारतीयों का होना कोई इत्तफाक नहीं है। यहां की कुल आबादी का 21% और कुल वर्कफोर्स का 30% हिस्सा भारतीय समुदाय ही है। भारतीयों के इतनी बड़ी संख्या में वहां जाने के पीछे एक बड़ा कारण है वहां होने वाली बचत। एक कुवैती दीनार की कीमत भारतीय मुद्रा में मौजूदा विनिमय दर के मुताबिक 272 रुपये से ज्यादा बैठती है। निम्न व मध्यम श्रेणी के कार्यों के लिए वहां औसत मासिक वेतन 1000 से 3000 कुवैती दीनार है, जो भारतीय मुद्रा में 75000 से 225000 रुपये हो जाता है।

भारत की तत्परता | अच्छी बात यह रही कि भारत सरकार ने इस मामले में तत्परता दिखाई। न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की बल्कि दोनों सरकारों के बीच भी पूरी तरह तालमेल दिखा। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी फौरन कुवैत रवाना हो गए ताकि घायलों के इलाज का जायजा ले सकें। सरकार के स्तर पर इस तरह की तत्परता विदेश में रह रहे भारतीयों के बीच यह भरोसा बनाए रखने में मदद करती है कि उनका देश संकट की घड़ी में हमेशा साथ खड़ा रहेगा।

दूरगामी उपाय हों | लेकिन घटना के बाद की यह प्रतिक्रिया काफी नहीं है। वहां रह रहे भारतीयों की जीवनदशा ठीक रहे इस पर भी कुवैत सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं की आशंका न रहे।

रोज़-ब-रोज़

जंग के बाद

शैलेंद्र पांडेय

वट्सऐप पर बहस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अंगुलियां बहुत घिसनी पड़ती हैं मेसेज टाइप करने में। ऐसे में मन में गुबार ज्यादा होता है, लेकिन शब्दों से पूरी तरह निकल नहीं पाता। मोबाइल के छोटे-से कीपैड पर लंबे-लंबे संदेश लिखने में कुछ न कुछ छूट ही जाता है। यह छूटना ही नियामत समझिए कि यह नहीं छूटा, तो फिर रिश्ता छूटने का डर हो जाता है। इस महीने की शुरुआत में डर की ऐसी ही छाया दिखी दोस्तों के इस ग्रुप में। पता नहीं किसने, किन हालात में इसे नाम दे दिया PKMR। पहली बार सुनने पर लगा कि कोई मल्टिनैशनल फर्म है, जो बनारस में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही।

इस ग्रुप में वही सब बातें होती हैं, जो दोस्तों के किसी ग्रुप में अमूमन होती हैं। लेकिन, पिछले दिनों मामला अलग था। जंग का मैदान बना हुआ था ग्रुप। धड़ाधड़ मेसेज गिर रहे थे। ग्रुप खोलने पर हमेशा कोई न कोई टाइपिंग करता ही नजर आता। एक-दूसरे की बातों को ऐसे काटा जा रहा था, जैसे वेस्टर्न सिनेमा में किसी योद्धा को चाकू से दुश्मनों को काटते दिखाया जाता है। खून गिरता दिख नहीं रहा था, लेकिन दोस्त लहूलुहान हो रहे थे और उन पर वार करने वाले भी दोस्त ही थे। एक और फायदा यह है वट्सऐप वाली बहस का कि अगर आप मैदान छोड़कर जाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि पीठ पीछे पड़ने वाली लानतों से बच जाएं, तो ग्रुप लेफ्ट कर सकते हैं। इस लड़ाई में भी कुछ योद्धाओं ने वही किया। कुछ इसके बाद भी ललकारते हुए पीछे भागे। यह स्थिति करीब हफ्ते भर चली और तब भी गनीमत रही क्योंकि कई बातें कहने से छूट गई थीं। उत्तेजना से कांपते हाथों ने कई शब्दों को अधूरा ही टाइप करके सेंड कर दिया था। तो बात बिगड़ी, लेकिन इतनी नहीं कि संभाली न जा सके। वापसी का रास्ता बचा था और यह तब खुला, जब देश बाहर आया चुनावी मोड से। हर ग्रुप में कोई सदस्य जरूर होता है ऐसा, जिसे बात को मोड़ना आता है। जिसमें इतना हुनर होता है कि बीच में से एक नई शुरुआत कर सके। आपके ग्रुप में भी पक्का ऐसे दोस्त होंगे। दरअसल, इन्हीं की वजह से जंग के बाद जीवन को फिर से पटरी पर लाने में मदद मिलती है। तो प्रयास शुरू हुए। जो लेफ्ट कर गए थे, उन्हें एड किया गया।

थोड़ी उलाहना, थोड़ा प्यार। मेसेजबाजी फिर शुरू हो चुकी है। नोकझोक चल रही है। अब कुछ लिखने में अंगुलियां दर्द नहीं कर रहीं और न ही दिमाग पर ज्यादा जोर देना पड़ रहा है। पिछली सुबह ही मोबाइल बजा। एक नया मेसेज था, एक साथी के जन्मदिन का। पार्टी मांगने वाले जाग चुके हैं। टाइपिंग अब भी जारी है।

एकदा

राही ने पहचाना

घटना महाराष्ट्र के सोलापुर जनपद स्थित इस्लामपुर गांव के प्राइमरी स्कूल की है। एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाने में तल्लीन थे। कक्षा के बाहर खिड़की के पास खड़ा होकर एक बच्चा शिक्षक पर ध्यान लगाए रहता था। स्कूल के बाहर रास्ते से आते-जाते लोग उस बच्चे को देखते और आगे बढ़ जाते। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। एक दिन वहां से गुजरते एक राही से रहा नहीं गया। वह बच्चे के पास गया और उससे कक्षा से बाहर खड़े रहने का कारण पूछा। बच्चे ने कहा कि वह पढ़ना चाहता है पर वह महार जाति से है, उसे कक्षा में बैठने की इजाजत नहीं है। राही ने शिक्षक से तीखी बहस की, पर व्यवस्था को दोषी ठहराते हुए शिक्षक ने बच्चे को कक्षा में बैठाने से मना कर दिया। वह राही उस बच्चे को लेकर अपने घर आया और अगले दिन उसे लेकर कोल्हापुर चला गया। रास्ते में उसने उस बच्चे से बताया कि कोल्हापुर में उसके पढ़ने और रहने का इंतजाम करवा देगा। उस समय कोल्हापुर में शाहू जी महाराज छूआछूत के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चला रहे थे। उन्होंने ऐसे बच्चों के रहने और उनके पढ़ने-ठहरने के लिए मिस क्लार्क नाम से एक छात्रावास खोल रखा था। यहां इस बच्चे के रहने का इंतजाम हो गया और यहीं से उसके पढ़ने-लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बच्चे का नाम ज्ञानदेव ध्रुवनाथ घोलप था। शिक्षा पूरी करने के बाद ज्ञानदेव 1920 में मुंबई से डॉ. आंबेडकर द्वारा शुरू किए गए मूक नायक नामक समाचार पत्र के प्रबंधक और संपादक बने। वह विधान परिषद के सदस्य भी बने। इस बच्चे को ज्ञान के तट पर पहुंचाने वाले उस राही को कर्मवीर भाऊराव पाटिल के नाम से जानते हैं। उन्होंने आगे चलकर सतारा में रेयात शिक्षण संस्थान की स्थापना की। उन्हें सन 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया।

संकलन : **हरिप्रसाद राय**

अमेरिका खेल का सबसे बड़ा बाज़ार, दुनिया की टॉप पांच स्पोर्ट्स लीग में से चार वहीं हैं

US में पूरा होगा क्रिकेट का रीयल ड्रीम

शैलेंद्र पांडेय

अमेरिकी जिस खेल को फुटबॉल कहते हैं, उसमें मैदान आयताकार होता है, गेंद अंडाकार और उसे पकड़ा जाता है हाथों से। शरीर से शरीर टकराते हैं और जो मजबूत पड़ता है, वही जीतता है। रग्बी और सॉकर से इवॉल्व हुए इस खेल को किसी भी सूरत में क्रिकेट के करीब नहीं कहा जा सकता। लेकिन, जब T-20 विश्वकप में मेजबान USA की टीम ने पाकिस्तान को सुपरओवर में हराया तो अमेरिका के सबसे बड़े स्पोर्ट्स चैनल ने इस जीत के मायने को समझाने के लिए अमेरिकी फुटबॉल का ही सहारा लिया। चैनल का कहना था कि इस जीत के महत्व को समझना हो तो कल्पना कीजिए कि अमेरिकी फुटबॉल में पाकिस्तान की टीम हमें हरा दे।

चमत्कार की उम्मीद | इंजीनियर, मैनेजर और दवा कंपनियों के कर्मचारियों से बनी अमेरिका की टीम के प्रदर्शन को चमत्कारी कहा जा रहा है। क्रिकेट के लिए एक नए बाजार की तलाश में जब इंटरनैशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2024 के T-20 विश्व कप की मेजबानी वेस्टइंडीज के साथ अमेरिका को सौंपी थी, तो उसे भी ऐसे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं रही होगी। ICC बस दुनिया के सबसे बड़े बाजार में घुसने का मौका देख रही थी। उसे वह मौका मिल चुका है। वाकई खेल का भला होना है, तो US को इसी तरह का चमत्कार कई बार करना होगा।

1983 जैसा असर | विश्व कप में अमेरिका की जीत या शानदार प्रदर्शन इस खेल से एक महाशक्ति को जोड़ देगी। इसका वैसा ही असर हो सकता है, जैसा कि 1983 में मिली वर्ल्ड कप जीत का भारत में हुआ। फाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत से सब बदल गया। क्रिकेट ने tectonic shift देखा वहां। उस दिन लॉर्ड्स में एक नई क्रिकेट सुपर पावर का जन्म हुआ।

क्रिकेट के लिए ज़रूरी
- अमेरिका की जीत से नए दर्शक मिलेंगे
- US स्पोर्ट्स मार्केट में घुसने का मौका
- नए खिलाड़ियों से मुकाबले रोचक होंगे

नया फ्लेवर | अमेरिका में क्रिकेट का दायरा बढ़ता है तो खेल को नया फ्लेवर मिलेगा। अभी पूरा मुकाबला चंद टीमों के बीच सिमटा होता है। दर्शक, बाजार, स्टार - सब कुछ एक दायरे में है। अमेरिका में दायरा बढ़ने से क्रिकेट को नए खिलाड़ी और दर्शक मिलेंगे। जब इस विश्व कप के लिए टीमें तय हुईं, तो कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि असोसिएट मेंबर्स के आने से रोमांच कम होगा क्योंकि उनमें और फुल मेंबर्स के बीच गैप बहुत ज्यादा है। मुकाबले एकतरफा होंगे, तो मजा नहीं आएगा। हां, कुछ मुकाबले एकतरफा हुए हैं, लेकिन कम से कम अमेरिका के नहीं। अमेरिकी टीम ने झलक दिखा दी है कि अगर उसे लगातार मौके मिलें तो वह बड़ी टीमों में शामिल हो सकती है और यह मौका तभी मिलेगा जब वह इस विश्वकप में बेहतर प्रदर्शन करती है।

AI Image

अमेरिका के चुनावी सीजन में क्रिकेट का बुखार भी चढ़ा है। सोचिए अगर ट्रंप और बाइडन भी मैदान में आ जाएं तो कैसा नजारा होगा (AI की कल्पना से)

बाजार में पैठ | अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा खेल बाजार है। दुनिया की टॉप 5 स्पोर्ट्स लीग में से चार उसके यहां होती हैं।
- नंबर वन पर काबिज National football league ने पिछले सीजन में 20 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जुटाया।
- National Basketball Association (NBA) का रेवेन्यू करीब 11 बिलियन डॉलर रहा।
- Major League Baseball (MLB) का रेवेन्यू भी 11 बिलियन डॉलर से थोड़ा ही कम रहा।

अमेरिका में प्रफेशनल स्पोर्ट्स का पूरा मार्केट 70 बिलियन डॉलर के आसपास है। अभी क्रिकेट खेलने वाले सारे देशों को मिला लीजिए, तो भी उससे ज्यादा। विश्व कप में अमेरिका की जीत क्रिकेट को इस मार्केट में हिस्सेदार बनाने में मदद करेगी। 28 ट्रिलियन डॉलर वाली दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में घुसने से क्रिकेट का भला ही होगा।

दूसरे देशों को सहारा | एक सवाल जहन में उठ सकता है कि क्रिकेट को अमेरिका का पैसा क्यों चाहिए? यह खेल बाकियों से इस लिहाज से जुदा है कि इसे खेलने के लिए तमाम इंतजाम करने पड़ते हैं। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है और उसके बाद भी कोई इवेंट कराना बहुत मुश्किल और खर्चीला होता है। यही वजह है कि इन खर्चों को पूरा करने के लिए ICC हर मेंबर को रेवेन्यू शेयर देती है, लेकिन वह काफी नहीं। आयरलैंड और जिम्बाब्वे जैसे टेस्ट खेलने वाले देश भी ज्यादा नहीं खेल पाते, क्योंकि बजट नहीं होता। अगर अमेरिकी मार्केट क्रिकेट के लिए उसी तरह खुल जाता है, जैसे फुटबॉल या बास्केटबॉल के लिए खुला, तो इससे खेल को मजबूती मिलेगी।

बेसिक इंफ्रा मौजूद | USA Cricket का अनुमान है कि अमेरिका में करीब चार करोड़ आबादी है, जिसकी पहले से जान-पहचान है क्रिकेट से। देश की अपनी क्रिकेट लीग है, Major League Cricket। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और IPL के फ्रैंचाइजी मालिकों ने निवेश किया है। पूरे अमेरिका में 400 से ज्यादा घरेलू लीग शुरू हो चुकी हैं और दो लाख से अधिक खिलाड़ी विभिन्न स्तरों पर खेल रहे हैं। 2028 में Los Angeles में ओलिंपिक्स होने हैं, जिसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है।

पुराना इतिहास | अमेरिका में क्रिकेट की जड़ें लगभग उतनी ही पुरानी हैं, जितनी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में। 1844 में अमेरिका और कनाडा के बीच पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया था। जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी इस खेल का आनंद लिया था और वैंकूवर डॉन ब्रैडमैन के पसंदीदा मैदानों में था। इतिहास अमेरिका के साथ है, उसे अब भविष्य लिखना है।

BJP ने कैसे छीना नवीन पटनायक का गढ़

पिंकी होता

4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मोदी ने NDA की जीत की स्पीच 'जय जगन्नाथ' बोलकर शुरू की। BJP ने ओडिशा की 21 संसदीय सीटों में से सिर्फ एक छोड़कर सभी जीत लीं और बीजू जनता दल (BJD) को संसद से लगभग बाहर कर दिया। पार्टी ने विधानसभा में भी बहुमत हासिल किया (147 में से 78 सीटें), और राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक को लगभग 25 साल बाद सत्ता से हटा दिया। पार्टी ने मंगलवार को चार बार के आदिवासी विधायक मोहन चरण माझी को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना।

ओडिया पहचान | हालांकि BJD की हार एंटी-इनकंबेंसी का नतीजा हो सकती है, लेकिन खुद उसी ने ओडिशा में BJP के लिए रास्ता खोला। उसके उड़िया गर्व के विजन के केंद्र में हिंदू पहचान थी, जिसके लिए उसने पुरी में जगन्नाथ मंदिर के तीर्थ यात्रा गलियारे पर 800 करोड़ खर्च किए। इसी हिंदू-ओडिया लॉजिक ने BJP के राजनीतिक हिंदुत्व को जीत के लिए तैयार किया। पार्टी ने BJD को इस आधार पर चुनौती दी कि राज्य की 'शुद्ध' हिंदू पहचान को कौन बेहतर संजो सकता है।

पटनायक के पांडियन | मोदी ने पटनायक को कमजोर दिखाया। उन्होंने पटनायक की सेहत की जांच के लिए एक कमिटी बनाने का वादा किया। पटनायक के सबसे करीबी और तमिलनाडु में पैदा हुए पूर्व IAS अधिकारी वी.के. पांडियन को कठपुतली और तमिल घुसपैठिया कहा गया।

हिंदू अस्मिता | 'उड़िया हिंदू गौरव' के नारे के साथ BJP ने पटनायक को उनके ही खेल में हरा दिया। BJP ने जनजातीय समुदायों में गहरी पैठ बनाई। BJD का उच्च जाति हिंदुओं पर निर्भर रहना उल्टा पड़ गया।

आमने-सामने | जनजातियों के हिंदूकरण ने आदिवासियों और दलितों को आमने-सामने ला खड़ा किया है। 2008 में VHP नेता की हत्या के बाद कंधमाल में ईसाई दलितों का नरसंहार हुआ था। आदिवासी-दलित विरोध BJP के लिए एक सफल रणनीति साबित हुई क्योंकि आदिवासी 23% हैं, जबकि दलित 17%।

कॉमन रूम

असंतुलित मॉडल | पटनायक की पिछली सफलता काफी हद तक इस तथ्य पर टिकी थी कि ओडिशा देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस छवि के पीछे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर आधारित विकास मॉडल था। BJD के गरीब समर्थक पार्टी होने के दावों के बावजूद इसकी आर्थिक सफलता ने आदिवासियों और दलितों को बड़ी संख्या में बेदखल कर दिया था। वेदांता के चलते डोंगरिया कोंड को उनके पवित्र पर्वत नियमगिरि के आसपास के इलाकों को छोड़ना पड़ा। जजपुर जिले के खनिज संपन्न सुकिंदा में आदिवासियों ने BJD के खिलाफ मतदान किया क्योंकि अवैध खनन के चलते वहां का पानी प्रदूषित हो गया।

बड़ा डर | यह देखना बाकी है कि ओडिशा में आदिवासियों की स्थिति BJP के शासन में बेहतर होगी या नहीं क्योंकि छत्तीसगढ़ में BJP ने आदिवासी स्वायत्तता और जंगलों तक पहुंच की रक्षा करने वाले प्रमुख कानूनों में बदलाव किए हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि BJP आदिवासी अधिकारों का सम्मान नहीं करती और उसने आदिवासी ईसाईयों को भी निशाना बनाया है।

साझा मंच | राष्ट्रपति मुर्मु ओडिशा की संथाल आदिवासी हैं, जो राष्ट्रपति हैं। BJP इसका रणनीतिक फायदा उठाना चाहती है। आदिवासियों की तस्वीर 'प्रोटो-हिंदू' जैसी पेश की गई है, जिन्हें ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ लामबंद किया जा सकता है। इससे BJP राज्य की 'आदिवासी पार्टी' बन गई है। ओडिशा के पहले BJP मुख्यमंत्री माझी भी संथाल नेता हैं। अब एक साझा दलित-बहुजन-आदिवासी मंच को ओडिशा के पर्यावरण के विनाश का मुकाबला करने के लिए काम करना होगा।

(लेखिका स्मिथ कॉलेज, अमेरिका में असोसिएट प्रफेसर हैं)

संसद में दिखेगी अग्निवीर मामले की तपिश

पूनम पाण्डे

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। यह 17वीं लोकसभा से इस मायने में भी अलग है कि इस बार संसद में विपक्ष की आवाज ज्यादा सुनाई देगी। पहले जहां विपक्षी सांसदों की संख्या बहुत कम थी, वहीं अब नंबर के लिहाज से मजबूत विपक्ष है। साथ ही सरकार भी गठबंधन वाली है। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष के साथ-साथ सरकार में शामिल BJP के सहयोगी दल JDU ने अग्निपथ में बदलाव को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। सेना में भर्ती की स्कीम अग्निपथ को लेकर चिंगारी तो दो साल से ही भड़की हुई है, लेकिन नए समीकरणों को देखते हुए लगता है कि इस बार संसद में इसकी तपिश ज्यादा होगी।

ऐसा नहीं है कि अचानक अग्निपथ स्कीम को लेकर सवाल उठने लगे। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अपनी आने वाली किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' में अग्निपथ को लेकर लिखा है कि यह योजना आर्मी को हैरान करने वाली थी, और एयरफोर्स और नेवी के लिए तो यह झटके की तरह आई थी। जनरल नरवणे ने लिखा है कि उन्होंने 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। उसमें कुछ सीमित संख्या में सैनिकों को कम अवधि के लिए भर्ती करने की बात थी। यह प्रस्ताव अधिकारियों के शॉर्ट सर्विस कमिशन की तरह था।

PMO ले आया नई स्कीम

प्रधानमंत्री कार्यालय बाद में एक अलग स्कीम लेकर आया- अग्निपथ, जिसमें सारी भर्तियां चार साल के लिए ही होनी हैं। जनरल नरवणे की किताब कब आएगी, इस पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। उनकी किताब को अभी रक्षा मंत्रालय का अप्रूवल नहीं मिला है। पिछली लोकसभा के आखिरी सत्र में संसद की रक्षा मामलों की

विशुद्ध राजनीति
कसौटी

स्टैंडिंग कमिटी ने भी अग्निवीर को लेकर कुछ अहम सिफारिशें कीं। सिफारिश की गई कि अगर कोई अग्निवीर वीरगति को प्राप्त होता है तो उनके परिजनों को वही मदद देनी चाहिए जो किसी सैनिक की वीरगति होने पर उनके परिवार वालों की दी जाती है। भारतीय सेना में अग्निवीर की सेवा शर्तों के मुताबिक बैटल कैजुअल्टी होने पर परिवार वालों को इंश्योरेंस, एक्स ग्रेशिया सहित करीब 1 करोड़ रुपये की सहायता मिलती है। लेकिन अगर कोई रेग्युलर सैनिक शहीद होता है तो उसके परिवार को भी इन सब आर्थिक मदद के साथ उसकी आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन भी मिलती है। साथ ही पूर्व सैनिक को आर्मी कैंटीन, मिलिट्री हॉस्पिटल के जो फायदे होते हैं वह भी शहीद के परिवार को दिए जाते हैं।

बिना पायलट प्रॉजेक्ट के सीधे ही पूरी तरह अग्निपथ स्कीम लागू करने की तपिश फौज के अंदर भी दिख रही है। जहां रेग्युलर सैनिकों को साल में 90 दिन की छुट्टी मिलती है, वहीं अग्निवीरों के लिए महज 30 छुट्टियां हैं। फैमिली कमिटमेंट के साथ ही बाकी सभी जरूरतें रेग्युलर सैनिक की तरह ही अग्निवीर की भी है। ऐसे में उनकी छुट्टी एक बड़ा इश्यू बन रही है। अग्निवीर की सेवा शर्तें रेग्युलर सैनिकों से अलग हैं जिसकी वजह से फौज के अंदर ही दो कैटेगिरी होती दिख रही है। इसका असर रोजमर्रा के कामकाज पर भी दिख रहा है। अग्निवीर से अकेले संतरी के तौर पर नाइट ड्यूटी नहीं कराई जा रही है और इस तरह की बहुत सी संवेदनशील ड्यूटीज हैं जिनमें अग्निवीर को तैनात नहीं किया जा रहा। इससे अग्निवीर और रेग्युलर सैनिकों में एक-दूसरे से अलग होने की भावना आएगी।

एकतरफा कमिटमेंट का सवाल

अग्निवीरों को चार साल के लिए भर्ती किया जा रहा है और इनमें से अधिकतम 25 फीसदी को परमानेंट होने का विकल्प दिया जाएगा। यह सेना के 'नाम-नमक-निशान' के लिए जान देने वाले खाके पर फिट नहीं बैठता। मनोविज्ञान को जरा भी समझने वाले बता सकते हैं कि जब युवाओं को लगेगा कि ज्यादा संभावना इस बात की है कि चार साल बाद उन्हें घर जाना है तो वे रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, वह भी तब जब शहीद होने के बाद भी उनके परिजनों के लिए कोई पेंशन व्यवस्था नहीं है। सेना सामान्य नौकरी नहीं है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सैनिक और देश के बीच एक कमिटमेंट होता है कि सैनिक देश की रक्षा करेगा, चाहे जान तक देनी पड़े और देश सैनिक के परिजनों की जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन अग्निवीर के साथ देश यह कमिटमेंट नहीं कर रहा है। तो क्या कमिटमेंट एकतरफा ही निभाया जाएगा? इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा रहा, खासकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं। इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। मसला गरम है और जल्द ही इसकी गरमाहट का असर भी दिख सकता है।

मत-सम्मत

www.edit.nbt.in

विषयः मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में लगी आग की भयावह घटनाओं को लेकर आपका क्या कहना है?

■ बचाव के नाकाफी उपाय

मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में पिछले महीने हुई अग्निकांड की दर्दनाक और भयावह घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस भयावह त्रासदी में भारी जनहानि हुई है। कई मासूम बच्चों की जान गई है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। अक्सर खराब कंस्ट्रक्शन, वर्क स्पेस सेफ्टी मानकों के खराब रेकॉर्ड और सुरक्षा नियमों के पालन में कमी से ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं। प्रशासन को इस लापरवाही के जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। लेकिन, विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार, लापरवाही और नियमों की अनदेखी का ऐसा आलम है कि आगजनी की ऐसी भयावह घटनाओं को चाह कर भी नहीं रोका जा सकता।

-दीपा सिन्हा (मुंबई), ईमेल से

■ सुरक्षा पर दें ध्यान

आग लगने की बढ़ती घटनाएं यह साबित कर रही हैं कि प्रशासन ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। वैसे ही हादसे हो रहे हैं, जान-माल का भारी नुकसान हो रहा है। यह बेहद चिंता की बात है। हाउसिंग सोसायटी और संस्थानों में आग बुझाने के साधन अच्छे होना चाहिए, बहुमंजिला और व्यावसायिक भवनों में आग लगने पर सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए।

-साजिद अली, ईमेल से

■ हर कदम पर लापरवाही

भारत के शहरों में गिनती की ही कुछ इमारतें होंगी, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आसानी से पहुंचती हो। कई रिहायशी इलाकों में इतनी भी जगह नहीं होती कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सके। अधिकतर गगनचुंबी इमारतों में बिल्डरों द्वारा लगाए गए फायर सिस्टम की गुणवत्ता भी खराब होती है, तो कभी उस सिस्टम को समय पर चालू ही नहीं कर पाते हैं लोग, जिसकी वजह से जान-माल का भारी नुकसान हो जाता है। प्रशासन, बिल्डर्स और कुछ नागरिकों की लापरवाही भी एक बड़ा कारण है।

-जय गोविंद मिश्रा (मुंबई), ईमेल से

सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी

आग की भयावह घटनाएं दुःखद हैं। अग्नि सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन और रखरखाव ठीक से हो। प्रशासन की ओर से रिहायशी इलाकों में औचक जांच भी जरूरी है। पूर्व सूचना पर अग्नि सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण व परीक्षण आग से होने वाली हानि को कम कर सकती है।

-गिरधारीलाल पोद्दार, ईमेल से

अगली बार का विषयः लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर आपका क्या कहना है?

mat.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

बीती बातों पर फुलस्टॉप लगाओ चिंता नहीं घेरेगी

ब्रह्माकुमारी शिवानी

समय हमारा बहुत बड़ा खजाना है। हमें इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। अगर हम समय को नष्ट करेंगे, तो समय हमें नष्ट कर देगा। यह नहीं सोचना है कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। समय का इंतजार नहीं करना है और इसे सकारात्मक बातों, निस्वार्थ सेवा में अवश्य लगाना है। दुनिया वाले मानते हैं कि ईश्वर की याद में रहने से हम सफल होते हैं। यह व्यर्थ नहीं जाता है। इसका कारण है कि ईश्वरीय स्मृति वाली हर सांस में सफलता समाई हुई है। लेकिन अपने संकल्प, समय और सांस रूपी खजाने को हम कितना जमा करते हैं या गंवाते हैं, यह हमारे ऊपर है। हमें देखना है कि दिन भर में हमने इन खजानों को कितना जमा किया या गंवाया है? जीवन की सफलता या सार्थकता इसी पर निर्भर करती है।

इन खजानों को जमा करने का तरीका आसान है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। स्थूल खजाने, जैसे धन-संपत्ति, बैंक-बैलंस में भी एक के आगे एक जीरो लगाते हैं। ऐसे ही हमारी अंतरात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसके चिंतन में रहने से आत्मशक्ति जागृत होती है। दूसरा, सर्व आत्माओं के रूहानी पिता परमात्मा भी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उनकी स्नेह भरी स्मृति में रहकर कर्म करना है। तीसरा, जो बीत चुका है उस पर फुलस्टॉप लगाओ तो व्यर्थ की चिंता या overthinking से बच जाएंगे और समर्थ चिंतन का खजाना बढ़ेगा या जमा होगा।

व्यर्थ के संकल्पों पर फुलस्टॉप लगाना एक कला और क्षमता भी है। कई बार ऐसा करने की हम कोशिश करते हैं, पर बिंदी लंबी लाइन बन जाती है। कई बार बिंदी की जगह लाइन हो जाती है, या उसकी जगह क्वेश्चन-मार्क लग जाता है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी लगाना, यानी हमारा वर्तमान जो है, जैसा है उसे एक्सेप्ट करना। रोज सुबह हमें तीन बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाना है, तो एक भी खजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय, हर खजाना जमा होता जाएगा। अक्सर हमारे समय, संकल्प और बोल व्यर्थ जाते हैं, जमा नहीं होते हैं। चलते-चलते हम समय, संकल्प और बोल का महत्व भूल जाते हैं। अगर इन आंतरिक खजानों का जमा कम होगा, तो विपरीत परिस्थिति व परीक्षाओं का हम सही से सामना नहीं कर पाएंगे। इन खजानों को जमा करने की सहज विधि है- सुबह उठने से लेकर दिन भर कर्म करते हुए स्व (आत्म) चिंतन, प्रभु चिंतन, परमात्म ध्यान, सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और कल्याणकारी संकल्पों का अभ्यास करना। इन आध्यात्मिक मूल्यों या स्वधर्म के नियमित अभ्यास के जरिए मनुष्यों का मनोबल और आत्मबल बढ़ेगा। हमें परचिंतन, परचर्चा, परपंच, पूर्वाग्रह, निंदा, चुगली, कटाक्ष, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा, आक्रोश जैसी अहितकारी भावनाओं को हितकारी विचारों में बदलने की जरूरत है।

इस परिवर्तन की दिशा में नेगेटिव में पॉजिटिव देखने, अवगुणों में सद्गुण खोजने, बेकार में से विशेषता ढूंढने, समस्याओं में समाधान निकालने, निराशा में आशा का संचार करने और अंधकार में प्रकाश का अनुभव करने का दृढ़ संकल्प विकसित करना है। इसी पॉजिटिव नजरिए को मन, वचन और कर्म में उतारना ही सच्ची दृढ़ता है।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

https://t.me/AIINewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 102

विकास का विकेंद्रीकरण

स्थानीय सरकारें बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं की आपूर्ति करके देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए सिंचाई, सड़कें, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। वे स्थानीय जरूरतों को विकास परियोजनाओं से जोड़ पाने की दृष्टि से बेहतर स्थिति में होती हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि कई विकसित और विकासशील देश नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए स्थानीय सरकारों पर निर्भर रहते हैं। भारत जहां प्राचीन काल से ही स्थानीय सरकारों से परिचित है, वहीं ब्रिटिश काल में यह व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। आजादी के बाद इसमें फिर से नई जान फूंकी गई और 1990 के दशक के आरंभ में संविधान संशोधन करके तीसरे स्तर की सरकार को सशक्त बनाया गया। बहरहाल, अभी भी यह वांछित ढंग से काम नहीं कर रही है। खुशकिस्मती से स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने की बात सबको स्वीकार्य है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी अपने चुनाव घोषणापत्र में यह वादा किया है कि वह पंचायती राज संस्थानों को राजकोषीय स्वायत्तता प्रदान करेगी।

इस संदर्भ में विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक कार्य पत्र 'दो सौ पचास हजार लोकतंत्रः भारत में ग्राम सरकार एक समीक्षा' में इस बात पर जोर दिया है कि स्थानीय सरकारों को अधिक फंड, काम और पदाधिकारी दिए जाने चाहिए। भारत में तीसरे स्तर की सरकारों की राजनीतिक स्वायत्तता के बारे में मौजूद तमाम सामग्री की व्यापक समीक्षा के बाद इसने ऐसे उपायों को अपनाने का प्रस्ताव रखा जिनकी मदद से राजकोषीय और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाई जा सके और भुगतान के डिजिटलीकरण के कारण वापस आ रहे पुनर्केंद्रीकरण के रुझान का मुकाबला किया जा सके। दुनिया भर में स्थानीय सरकारें औसत कुल कर राजस्व का लगभग 10 फीसदी पाती हैं। जैसा कि रिजर्व बैंक के एक हालिया अध्ययन में रेखांकित किया गया, कुछ यूरोपीय देशों मसलन फिनलैंड, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड में यह राशि 20 फीसदी से अधिक है। बहरहाल भारत में स्थानीय सरकारें राजस्व के मामले में बहुत तंग हालात में हैं। वे सरकार के ऊपरी स्तरों से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर हैं। वर्ष 2022-23 में पंचायतों का अपना राजस्व उनकी कुल राजस्व प्राप्तियों में करीब एक फीसदी का ही हिस्सेदार था। इसके परिणामस्वरूप सरकार के ऊपर के स्तरों से मिलने वाला अनुदान प्राप्तियों का मुख्य स्रोत बन गया और कुल प्राप्तियों में इनका योगदान करीब 95 फीसदी है। राजस्व जुटाने की सीमित क्षमता होने के कारण व्यय संबंधी निर्णयों में उनकी स्वायत्तता को सीमित करता है। जैसा कि 15वें वित्त आयोग ने कहा, 'उनके कुल व्यय में निर्बंध व्यय की हिस्सेदारी केवल 40 फीसदी है। इससे संकेत मिलता है कि वे निर्णय लेने और नीतियां बनाने वाली एक स्वायत्त संस्था के बजाय केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली संस्था के रूप में अधिक काम करती हैं।'

स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी विधायी परिवर्तन आवश्यक हैं। संविधान को पंचायतों और नगर निकायों की शक्तियों और उनके काम को स्पष्ट करना चाहिए। स्थानीय निकायों के चुनाव भी नियमित और निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। बहरहाल इन कामों का प्रभावी क्रियान्वयन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया होते हैं या नहीं। इस संदर्भ में संविधान हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की बात कहता है ताकि राज्य सरकारों से स्थानीय सरकारों को ज्यादा संसाधनों का हस्तांतरण हो सके। बहरहाल अधिकांश राज्यों में इन वित्त आयोगों के गठन में काफी देर हुई। जब वे घटित हो भी गए तो हस्तांतरण अपर्याप्त बना रहा। ऐसे में मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक है ताकि राज्य जरूरी हस्तांतरण कर सकें। केंद्रीय वित्त आयोग से सीधे फंड आवंटन का तरीका भी तलाश किया जा सकता है। पर्याप्त फंडिंग के अलावा यह भी अहम है कि स्थानीय सरकारों की क्षमता और पारदर्शिता बढ़ाई जाए। उदाहरण के लिए स्थानीय सरकारों की प्राप्तियों और व्यय के आंकड़े न होना भी एक दिक्कत है। समुचित अंकेक्षण से न केवल जवाबदेही बढ़ेगी बल्कि निर्णय लेने और किफायती संसाधन आवंटन में भी मदद मिलेगी। विश्व बैंक की अनुशंसा के मुताबिक एक स्वतंत्र और विश्वसनीय व्यवस्था बनाकर स्थानीय सरकारों के प्रदर्शन का आकलन किया जा सकता है। भारत के लिए समय आ गया है कि वह स्थानीय सरकारों को मजबूत करे ताकि विकास के क्षेत्र में बेहतर नतीजे हासिल हो सकें।

विनय सिन्हा

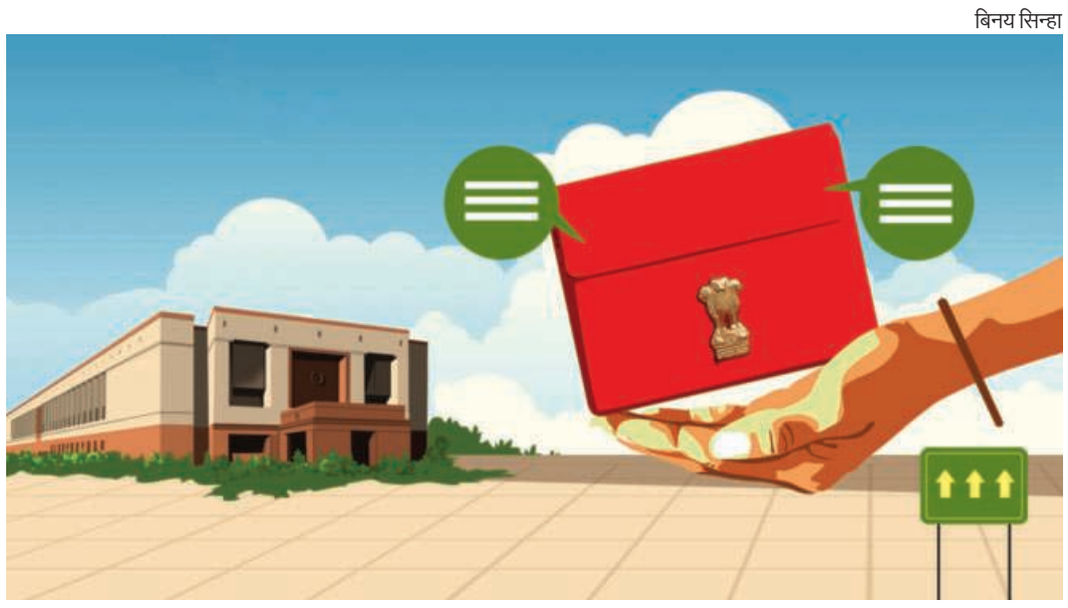

बजट निर्माण प्रक्रिया में बढ़े पारदर्शिता

बजट में वर्ष 2023-24 के प्रारंभिक आंकड़ों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अधिशेष का इस्तेमाल बेहतर प्रभाव के लिए किया जाना चाहिए। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

अब जबकि निर्मला सीतारमण पिछले कार्यकाल की तरह वित्त मंत्री के पद पर लौट आई हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय भी अपने सबसे अहम काम में जुट गया है यानी 2024-25 का बजट तैयार करना। उन्होंने गत 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था परंतु वह केवल लेखानुदान था। यानी उन्होंने नई सरकार का पूर्ण बजट पेश होने तक व्यय के लिए एक खास राशि खर्च करने के वास्ते संसद की अनुमति मांगी थी। इससे पहले के कुछ अंतरिम बजट के उलट उन्होंने बजट में कोई नई नीतिगत घोषणा नहीं की थी। अब जबकि वह चालू वर्ष का पूर्ण बजट तैयार कर रही हैं तो उनकी प्रमुख चिंता क्या होनी चाहिए?

निस्संदेह वृहद आर्थिक हालात जिनके तहत आगामी बजट तैयार किया जाएगा, वे अंतरिम बजट के समय की तुलना में फिलहाल बेहतर नजर आ रहे हैं। खुदरा मुद्रास्फीति नियंत्रण में नजर आ रही है, हालांकि अभी भी यह सरकार द्वारा तय चार फीसदी के लक्ष्य से ऊपर है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2023-23 में 8.2 फीसदी की दर से बढ़ी और इस वर्ष उसके 7.2 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 640 अरब डॉलर के साथ सहज स्तर पर है। चालू खाते का घाटा भी 2023-24 की पहली तीन तिमाहियों में जीडीपी के 1.2 फीसदी के साथ नियंत्रण में रहा है। कुछ अनुमानों के अनुसार पूरे वर्ष के दौरान यह एक फीसदी से कम रह सकता है। निर्यात के मोर्चे पर भी कुछ चिंताएं हैं। वस्तु निर्यात में गिरावट आ रही है और सेवा निर्यात भी पहले जैसा गतिशील नहीं है। भूराजनीतिक तनावों में कोई कमी आती नहीं दिख रही है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जिंस कीमतें खासकर कच्चे तेल की कीमतें भी चिंता का विषय हो सकती हैं। परंतु कुल मिलाकर 2024-25 का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती से लाभान्वित हो सकता है।

वर्ष 2024-25 के बजट के लिए एक और सकारात्मक बात हाल के घटनाक्रम से निकली है। भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष हस्तांतरण इस वर्ष अनुमान से 133 फीसदी अधिक रह सकता है। कुल 2.1 लाख करोड़ रुपये का यह हस्तांतरण जीडीपी के करीब 0.37 फीसदी के करीब गुंजाइश बनाएगा। क्या सरकार को इस अतिरिक्त प्राप्ति का इस्तेमाल घाटा कम करने में करना चाहिए या अधोसंरचना में निवेश बढ़ाना चाहिए अथवा खपत बढ़ाने के लिए कर प्रोत्साहन देना चाहिए। एक प्रश्न यह भी है कि क्या सरकार को निचले स्तर पर इससे अधिक रोजगार तैयार करने चाहिए? सरकार द्वारा गत वर्ष संसाधनों के उपयुक्त इस्तेमाल की बदौलत वर्ष 2023-24 का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.6 फीसदी तक सीमित रखने में मदद मिली जबकि बजट अनुमान 5.9 फीसदी का था। अब घाटे को कम करके अंतरिम बजट के 5.1 फीसदी के लक्ष्य तक लाने का काम अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। यकीनन वित्त मंत्रालय और तेज कमी लाकर 4.5 फीसदी के लक्ष्य को 2025-26 से पहले हासिल करने का लक्ष्य रख सकता है और अगले कुछ वर्ष में इसे तीन फीसदी के स्तर पर लाने की बात भी कह सकता है। अगले बजट में इन बड़े नीतिगत विकल्पों को चुनना होगा कि क्या इस वर्ष केवल घाटा कम करने पर ध्यान देकर उपलब्ध संसाधनों से अर्थव्यवस्था की अन्य जरूरतों को पूरा किया जाए मसलन निवेश, रोजगार और खपत मांग को बढ़ाना।

इस वर्ष के बजट का दूसरा सकारात्मक पहलू अप्रत्याशित क्षेत्र से आ सकता है। जुलाई 2022 से जून 2024 के बीच सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति उपकर राजस्व में करीब 2.7 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह वह राशि है जो केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक से उधार ली थी ताकि कोविड के महीनों में उन्हें हुई राजस्व हानि की भरपाई की जा सके। जुलाई 2022 से राज्यों को किसी तरह की क्षतिपूर्ति मिलनी बंद हो गई लेकिन केंद्र अपने ऋण की भरपाई के लिए यह राशि संग्रहित करता रहा।

वास्तविक भुगतान देनदारी के ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं लेकिन संभव है कि मार्च 2025 के पहले पूरा भुगतान हो जाएगा। इससे सरकार को दो तरह से अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्रालय जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त कर सकता है या उसके एक हिस्से को संशोधित दरों में शामिल कर सकता है। आदर्श स्थिति में उपकर समाप्त होना चाहिए और यह कवायद जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के साथ होनी चाहिए। दूसरा लाभ समग्र क्षतिपूर्ति उपकर को समाप्त करके जीएसटी दर को कम करना हो सकता है ताकि मांग बढ़ सके।

बजट विकल्पों से इतर नजर डालें तो वित्त मंत्रालय बजट प्रस्तुति में पारदर्शिता लाकर बड़ा सुधार कर सकता है। आम चुनाव के बाद पेश किए गए सभी बजट पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों पर आधारित रहे हैं जो अंतरिम बजट में पेश किए जाते। बहरहाल जब तक पूरा बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्रालय के पास पिछले वर्ष के प्रारंभिक आंकड़े होते हैं हालांकि वे अंकेक्षित नहीं होते। ध्यान रहे कि पिछले कुछ बजटों में संशोधित अनुमान और आरंभिक अनुमानों में काफी अंतर था।

उदाहरण के लिए 2008-09 में कुल राजस्व प्राप्तियों के लिए प्रारंभिक अनुमान संशोधित अनुमान से तीन फीसदी कम निकला। प्रारंभिक अनुमान में सरकार का पूंजीगत व्यय संशोधित अनुमान से 8 फीसदी कम था। 2013-14 में सरकार का कुल कर राजस्व प्रारंभिक अनुमानों में संशोधित अनुमान से 214 फीसदी कम था। वर्ष 2018-19 में यह अंतर बहुत बढ़ गया और राजस्व प्राप्ति के प्रारंभिक अनुमान संशोधित अनुमान से 9.6 फीसदी कम रहे। शुद्ध कर प्राप्तियां 11 फीसदी और कुल व्यय छह फीसदी कम रहा। अधिकांश अवसरों पर यह अंतर अंतिम आंकड़ों पर बड़ा असर नहीं डाल सका। परंतु राजस्व और व्यय के आंकड़ों में इस अंतर का अर्थ यह था कि इन आंकड़ों पर आधारित अर्थव्यवस्था के सभी पाठों में दिक्कत होगी।

बजट दस्तावेजों का अध्ययन करने पर राजस्व और व्यय के आंकड़े बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के रूप में दो श्रेणियों में नजर आएंगे, हालांकि सरकार के पास प्रारंभिक बिना अंकेक्षण के भिन्न-भिन्न आंकड़े उपलब्ध होंगे। 2023-24 के प्रारंभिक और संशोधित आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन वित्त मंत्री को अधिक पारदर्शिता बरतनी चाहिए ताकि सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के रुझान को लेकर अधिक पारदर्शी तस्वीर सामने आ सके। यह निर्णय बजट निर्माण की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से भी अहम होगा।

कारगर नहीं 'एक देश, एक चुनाव' का विचार

लंबे समय तक चला बहुत ही उबाऊ और थकाऊ लोक सभा चुनाव संपन्न हो चुका है। पूरे चुनाव के दौरान कुछ नए मुद्दे सुनने को मिले तो कई असाधारण उम्मीदवार भी राजनीतिक पटल पर उभर कर सामने आए। पूरे चुनाव के दौरान आचार संहिता लगी होने के कारण नीतियां और कानून बनाने का काम भले ठप रहा, लेकिन यह नेताओं को बड़ी-बड़ी बातें करने से नहीं रोक पाई, जबकि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही गलतबयानी पर सख्ती से अंकुश लगाया जाना चाहिए था।

इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में चुनाव बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरते हैं और मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बड़ा देश होने का तर्क देकर चुनाव प्रक्रिया को लंबा खींचा जाए। ज्यादा दिनों तक चुनाव में उलझे रहने से उभरने वाली चिंताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलीभांति अवगत हैं। इसलिए वह इससे छुटकारा पाने के लिए प्रायः 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की वकालत करते हैं। गृहमंत्री तो 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यवस्था को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि वह नई सरकार बनने पर इसे लागू करने की बात डंके की चोट पर कहते आए हैं।

लंबी चुनावी प्रक्रिया से छुटकारा दिलाने के लिए 'एक देश, एक चुनाव' का फॉर्मूला अपनाना 'बीमारी से ज्यादा भयावह इलाज' साबित हो सकता है। इसके कई कारण हैं। भारत में शासन के कई स्तर हैं। प्रशासनिक मोर्चे पर भी बहुत सी चुनौतियां हैं। इसलिए हमें कम से कम समय में संपन्न हो जाने वाली चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही, ये भी महत्त्वपूर्ण है कि वे सार्थक हों।

चुनाव प्रचार के दौरान एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। मतदाता विधान सभा और लोक सभा के लिए अलग-अलग तरीके से होने वाले मतदान से बहुत खुश नजर आते हैं। वे इस बात को भलीभांति समझते हैं कि दोनों तरह के चुनावों में अलग-अलग प्रकृति के कौशल और नीतिगत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इससे मतदाता नीतियों को लेकर अपनी असहमति या नाराजगी का संदेश राजनीतिक वर्ग तक आसानी से पहुंचा पाते हैं। लोक सभा और विधान सभा के चुनावों को एक साथ संपन्न कराने से मतदाताओं को मिलने वाली यह सुविधा समाप्त हो जाएगी। राज्य सरकारों का आकलन उनके अपने कामों के आधार पर होना चाहिए न कि इस बात पर कि दिल्ली की सत्ता संभालने वाली पार्टी ने पूरे कार्यकाल के दौरान कितना अच्छा या बुरा कार्य किया है।

नीति नियम
मिहिर शर्मा

वास्तव में, हमें एक नहीं, कई चुनावों की आवश्यकता है। भारत में स्थानीय चुनाव उसी स्तर पर संपन्न कराए जाने चाहिए, जैसे वे अन्य जगह होते हैं। इसके लिए स्थानीय निकायों को कर वसूली करने और नीतियां बनाने के लिए अधिक शक्तियों की जरूरत होगी। पंचायती राज व्यवस्था देने वाला संविधान का 73वां संशोधन जल्दबाजी में लाया गया अधूरा कानून है। दरअसल, इसमें आधे-अधूरे नियम कायदे हैं और आधी-अधूरी व्यवस्था हमेशा असफल रहती है।

इसमें उन नीतिगत क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें राज्य शासन के तीसरे स्तर पर हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी हस्तांतरण को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। नतीजतन, सभी राज्यों ने स्थानीय निकाय तो बनाए हैं, लेकिन उन्हें बहुत अधिक शक्तियां या करने के लिए कार्य नहीं दिए हैं। इसके बजाय वे कार्य राज्य की राजधानी में गैर-जिम्मेदार एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में रख दिए गए हैं।

मतदाताओं के सामने स्पष्ट मुद्दे होने चाहिए, जिनके आधार पर वे वोट दे सकें। इसी प्रकार जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव होना बहुत जरूरी है, ताकि जीतने के बाद वे आम जन के उन मुद्दों को हल करने की दिशा में काम कर सकें, जिनके लिए उन्हें चुना गया है। संसद सदस्य के लिए मतदान करने से संस्थागत रूप से अपने समुदाय में सार्वजनिक सेवाओं के लिए जवाबदेही का स्तर बदलने में बहुत कम मदद मिल पाती है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि इसमें इस प्रकार के दोष एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवस्था लागू होने पर जारी रहेंगे।

एक पूर्ण और स्वस्थ लोकतंत्र में प्रशासन की तीसरे स्तर की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अर्थपूर्ण नियमित चुनाव कराना बहुत ही आवश्यक है। व्यवस्था ऐसी हो कि यदि हमारी सड़कें और नालियां अच्छी नहीं बनी हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को हम चुनाव के जरिये बदल दें। आज यदि संस्थाएं ठीक तरीके से काम नहीं करती हैं तो हम किस पर गुस्सा निकालें। यह अस्थायी रूप से संतुष्टिप्रद हो सकता है, लेकिन कार्यगत स्तर पर इसका कोई तर्क नहीं है।

लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया केवल सार्वजनिक सेवाओं और शासन की गुणवत्ता के लिए ही जवाबदेही प्रदान नहीं करती है बल्कि यह लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका देती है और एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां लोग खुलकर अपनी पहचान के लिए लड़ सकें।

लेकिन भारतीय समाज स्थानीयता, जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्रीयता जैसी अनेक विविधताओं से भरा है। ऐसे देश में जब अलग-अलग समय और सरकार के अलग-अलग स्तर पर कई चुनाव होते हैं तो लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने मुद्दों के लिए आवाज बुलंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि समाज में न केवल शांति स्थापित होती है बल्कि, लोग एकजुट भी होते हैं।

इन तमाम अवसरों को जब एक चुनाव के जरिये एकल व्यवस्था में केंद्रित कर दिया जाएगा तो इससे हालात बेहतर होने के बजाय बदतर होंगे। पहचान का संघर्ष खत्म होने के बजाय और तीव्र होगा। यह संभव है कि एक या दूसरी पार्टी अस्थायी तौर पर फायदे में रहे, लेकिन चुनाव ही न हो, यह तो किसी के भी हक में ठीक नहीं होगा।

खासकर इस साल की लंबी और थकाऊ चुनावी प्रक्रिया को देखकर एक देश, एक चुनाव का नारा देने के तर्क को समझा जा सकता है। लेकिन, काफी कुछ केंद्र में नई सरकार पर निर्भर करेगा। संसद को चुनावी व्यवस्था में अनावश्यक और अनुत्पादक बदलावों में उलझकर असली मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए। यदि संसद वास्तव में मतदान प्रक्रिया में सुधार करना चाहती है, तो उसे पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न दलों में आम सहमति बनानी होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आम चुनाव की प्रक्रिया कई सप्ताह तक न चले। अवश्य ही इसकी अवधि छोटी होनी चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपका पक्ष

नीट परीक्षा में गड़बड़ी की कड़ाई से हो जांच

नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा संचालित नीट यूजी परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही गड़बड़ी के आरोप सामने आ गए। उच्च स्तरीय अध्ययन और नौकरी के लिए दी जाने वाली परीक्षाओं में पहले भी पेपर लीक होने और कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। इन परीक्षाओं के लिए प्रतिभाशाली छात्र कठोर परिश्रम करते हैं। छात्र तैयारी के लिए महंगी कोचिंग क्लास जाते हैं और दूसरे शहर में जाकर हॉस्टल और खाने का भारी खर्च उठाते हैं जो लाखों रुपये प्रतिवर्ष होता है। इस बार मामला उच्चतम न्यायालय में है। भविष्य में ऐसी अनियमितताएं न हों, इसके लिए परीक्षा के कुछ घंटे पहले ही पेपर सेट कर ऑनलाइन वितरित किए जाएं। इनका मूल्यांकन भी रात्रि तक करके परिणाम बता दिए जाएं तो अनियमितता की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर गुरुवार को अनियमितता के कारण नीट यूजी की परीक्षा फिर से कराने की मांग करते छात्र

छात्रों का डगमगाता विश्वास

देश में बड़ी परीक्षाएं अनियमितताओं की शिकार हो रही हैं। देश में बड़े पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में संस्थाएं ऐसे 100 प्रश्न नहीं सेट कर पा रही हैं जिनके उत्तरों को लेकर विवाद न हो। सरकार मामले को जांच कमेटी को सौंप कर ठंडा करने की कोशिश करती है तो विवादित प्रश्नों को डिलीट कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी। दिन-रात मेहनत करते बच्चों की विश्वसनीयता परीक्षाओं से उठने लगी है। द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के लिए पीएससी द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। पिछली दो-तीन परीक्षाओं को लेकर छात्रों के मन में असंतोष उभरा है। इसकी वजह प्रश्न पत्रों का स्तर ठीक नहीं होना है। एक प्रश्न के दो-दो उत्तरों के कारण छात्र असमंजस में पड़ जाते हैं। साल भर जी तोड़ मेहनत के बाद परीक्षा में विवादित प्रश्नों का आना और विरोध के चलते उन्हें परीक्षा से हटा देने का चलन हो गया है। इससे लाखों विद्यार्थी प्रभावित होते हैं।

अमृतलाल मारू, इंदौर

भारत के आर्थिक विकास में मजबूती उत्साहजनक

वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.8 फीसदी की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। इंटरनैशनल मॉनिटरी फंड ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक की वृद्धि दर का अनुमान जारी किया है। आईएमएफ ने भारत के लिए अपने वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाते हुए 2024 में इसके 6.8 फीसदी रहने का अनुमान जताया है जो जनवरी 2024 में जारी 6.5 फीसदी के अनुमान से ज्यादा है। 2025 के लिए आईएमएफ ने अपने वृद्धि दर अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया है और 6.5 फीसदी का अनुमान जताया गया है। उसने कहा कि भारत में वृद्धि दर मजबूत बनी रहेगी और 2024 में 6.8 फीसदी और 2025 में 6.5 फीसदी जीडीपी रहने का अनुमान है। आईएमएफ के मुताबिक घरेलू मांग में मजबूती और काम करने वाली आबादी के बढ़ने के चलते भारत के आर्थिक विकास में मजबूती देखने को मिल रही है। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.8 फीसदी कर दिया है जो सरकार के अनुमान 7.6 फीसदी से ज्यादा है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

पापुआ न्यू गिनी में पिछले दिनों हुए भीषण भूस्खलन के बाद गुरुवार को भारत से लगभग 10 लाख डॉलर मूल्य की राहत सामग्री भेजी गई।

मणिपुर हिंसा

चिन्ता का विषय

मणिपुर हिंसा फिर तेज हुई है जो चिन्ता का विषय है। मणिपुर लगातार हिंसा और अस्थिरता का शिकार रहा है जिसका कारण लोगों की पुरानी पीड़ा, राजनीतिक आयाम तथा नस्ली टकराव हैं। समय बीतने के साथ स्थिति फिर बिगड़ी है जिसके कारण व्यापक स्तर पर प्रदर्शन और रक्तपात जारी है। मणिपुर में मैतेई, नगा और कुकी जैसे कई नस्ली समुदाय रहते हैं जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान, संस्कृति व क्षेत्र संबंधी दावे हैं। इन समूहों के बीच संसाधनों, जमीन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर लंबे समय से जारी समस्याओं से पैदा टकराव के कारण गहरी दुश्मनी है। ऐतिहासिक रूप से इम्फाल घाटी में रहने वाले प्रमुखत: हिंदू मैतेई समुदाय का राजनीतिक सत्ता पर कब्जा था। इससे पहाड़ी आदिवासियों तथा पड़ोसी पहाड़ी ढलानों पर रहने वाले कबीलों जैसे नगा और कुकी में 'हाशियाकरण' की भावना पैदा हुई। ये समुदाय मुख्यत: ईसाई हैं। टकराव का एक मुख्य कारण इन पहाड़ी आदिवासियों में स्वायत्तता की बढ़ती मांग है। नगा समूहों ने सभी नगा-बहुल क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत एकीकृत करने की मांग की है। इससे एक विभाजनकारी अध्याय तैयार हुआ है जिसका टकराव बार-बार मणिपुर के सरोकारों तथा क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने से होता है। अनेक विद्रोही संगठनों की उपस्थिति के कारण स्थिति और जटिल होती है। विभिन्न नस्ली समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये संगठन अपनी मांगों से जनता को जोड़ने के लिए हिंसा करते हैं। इन समूहों के अवैध गतिविधियों व नशे के व्यापार में शामिल होने के साथ इनको हथियारों की कोई कमी नहीं है।

हालांकि, राज्य और केन्द्र सरकारों ने मणिपुर में सुधार के प्रयास किए,

लेकिन संभवत: उनकी कार्रवाइयों में पूर्ण संगति नहीं थी। इस कारण नीतियों और कार्रवाइयों में कई बार परिवर्तन भी करना पड़ा। ऐसे में मणिपुर की जनता के एक हिस्से में यह भावना पैदा हुई कि केन्द्र सरकार उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसके साथ ही आर्थिक विकास में कमी, खराब ढांचागत संरचना तथा क्षेत्र के सभी नस्ली समुदायों के बीच संवाद के अभाव ने स्थिति और खराब की है। हालांकि, राज्य और केन्द्र सरकारों ने विभिन्न नस्ली समुदायों के बीच संवाद बहाल करने के अनेक प्रयास किए, पर उनका कोई खास नतीजा नहीं निकला। विद्रोही समूहों के साथ बार-बार शांति वार्ताओं के टूटने से भी जनता में निराशा की भावना पैदा हुई। 'अफस्पा' के चलते सेना की व्यापक उपस्थिति से भी समस्यायें पैदा हुई हैं। सेना के खिलाफ मानवाधिकार हनन के आरोप भी लगे हैं। मणिपुर में नागरिक-अधिकार आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। इसके कारण न्याय व जवाबदेही तथा नीतिगत परिवर्तनों की मांग उठती रही है। 'मियेरा पाइबी' जैसे महिला समूह रैलियों में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। हालांकि, मणिपुर में कुछ समय पहले तक लग रहा था कि शांति स्थापित हो रही है, पर चुनाव के पहले और बाद में हिंसा बढ़ी है जिसके राजनीतिक कारण हो सकते हैं। मणिपुर में हिंसा की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले नशे और हथियारों के व्यापार तथा सरकारी व वन भूमि पर कब्जा करने वाले नस्ली समूहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। पड़ोसी म्यांमार में जारी गृहयुद्ध से भी ऐसे उग्रवादी समूहों को खाद-पानी मिला है। सरकार द्वारा उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रतिक्रिया में हिंसा बढ़ी है। मणिपुर में शांति स्थापना के लिए सर्वोपरि कानून-व्यवस्था की समस्या से निपटने के साथ ही विकास गतिविधियां तेज करते हुए विभिन्न समुदायों के बीच संवाद विकसित करना जरूरी है।

तमिलनाडु और केरल में भाजपा

हालांकि, सही समय आ गया है, पर उत्तर की राजनीति की तमिलनाडु व केरल में नकल नहीं हो सकती है। भाजपा को जमीनी स्थितियों पर गौर कर आगे बढ़ना होगा।

के.एस. राधाकृष्णन
(लेखक, वकील हैं)

तमिलनाडु में 1967 में कांग्रेस की पराजय के बाद से राज्य की राजनीति दो पार्टियों के बीच केन्द्रित हो गई है। केवल दो द्रविण पार्टियां-द्रमुक और अन्नाद्रमुक फोर्ट सेंट जार्ज में पहुंच सकी हैं। ऐसे में मतदाता 'द्रविणम' कहे जाने वाले भ्रम में जाने-अनजाने फंस गए हैं और इन दो पार्टियों में से किसी एक का समर्थन करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि द्रमुक ने राजनीतिक दर्शन में जिस पैराडाइम-परिवर्तन तथा सामाजिक न्याय की अवधारणा पेश की, उसने खामोशी से इस पार्टी के प्रथम परिवार को व्यक्तिगत रूप से समृद्ध किया है। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तमिलनाडु के नागरिक 'द्रविणवाद' का चेहरा उजागर कर वास्तव में राष्ट्रवाद की भावना स्वीकार करेंगे। भाजपा इस लक्ष्य की पूर्ति कर सकती है जिसने एक दशक के भीतर भारत की वैश्विक छवि बदल दी है और वह आक्रामक, साहसी तथा सक्षम बन गया है। वैश्विक मंच पर भारत के लिए यह आक्रामकता अच्छी है। देश को 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना से एकजुट और मजबूत करने के लिए नीतियों में साहस दिखाया जा रहा है।

विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से भारत को 'विकसित भारत' बनाने की क्षमता में 'डिजिटल इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' तथा कोविड वैक्सीन भाजपा सरकार द्वारा की गई कुछ पहले हैं जिनसे भारत की आर्थिक प्रगति तेज हुई है। तमिलनाडु को इनसे बहुत लाभ होगा। लेकिन तमिलनाडु और केरल में चुनावी विजयों के संदर्भ में भाजपा को जमीनी स्थितियों पर नजर रखनी होगी।

मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले प्रमुख ओमंडुर रामास्वामी रेड्डियार 'सामाजिक न्याय' के पहले मूल प्रवर्तक थे। उनके कार्यकाल में मद्रास टेंपल इंट्री आथराइजेशन एक्ट, 1947 तथा देवदासी डेडीकेशन एबालीशन एक्ट, 1947 पास किए गए थे। उन्होंने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा कृषि के माध्यम से तमिल भाषा की असाधारण सेवा की तथा साक्षरता का प्रसार किया। 1947 में तमिल कवि और विद्वान तथा तमिलनाडु में मंत्री पी. थूरान और अविनाशलिंगम चेट्टियार के सहयोग से तमिल की पहली इन्साइक्लोपीडिया 'कलाइक कलिंजयम' का प्रकाशन हुआ। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु और केरल विशिष्ट क्षेत्र हैं और इनके लिए प्रशासन का अलग दृष्टिकोण होना चाहिए।

पांच दशक से अधिक समय से तमिलनाडु की राजनीति पर नजर रखने के बाद मैंने अनेक जटिल मुद्दों पर गौर किया है जिन्होंने इन दोनों राज्यों की सोच और अर्थव्यवस्था में स्थान बना लिया है। तमिलनाडु तक अपनी चर्चा सीमित करते हुए मेरा मानना है कि यह क्षेत्र भाषा, संस्कृति, धार्मिक व्यवहारों तथा गहरे सांस्कृतिक संबंधों के मामले में विशिष्ट है जिनका विस्तार न केवल देश के भीतर, बल्कि समुद्र पार भी होता है। दुर्भाग्य है कि जो राज्य सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच सकता था, वह पिछले पांच दशक से एक परिवार के नाम पर बारी-बारी से दो द्रविण पार्टियों के कब्जे में है। तमिलनाडु की राजनीति झूठे वादों, सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों तथा खोखली बातों तक सीमित हो गई है। गृहयुद्ध समाप्त होने के बहुत पहले से ही श्रीलंका के तमिलों को उनके उचित अवसरों और गरिमा से राजनीतिक व आर्थिक रूप से वंचित किया गया था। उनके धार्मिक विश्वासों का भी उल्लंघन हुआ था। श्रीलंका में हिंदू पूजास्थलों पर बड़े पैमाने पर गैर-हिंदुओं ने कब्जा कर लिया था, जबकि शताब्दियों पहले तमिलों ने इसे अपा देश माना था। अनुमान है कि श्रीलंका के त्रिंकोमाली में 2,000 से अधिक हिंदू मंदिर ध्वस्त किए गए थे। राजनयिक वार्ताओं के माध्यम से इस क्षेत्र को ऐसे विरासती स्थल के रूप में सुरक्षित रखने के प्रयास होने चाहिए जो तमिल विरासत का केन्द्र है।

इस मोड़ पर मुझे याद आता है कि किस प्रकार द्रमुक की लापरवाही से कांग्रेस ने तमिलनाडु के एक 'हीरे' कच्चातिबू को श्रीलंका को सौंप दिया था। भाजपा को इस समझौते की समीक्षा कर तमिलों, खासकर दक्षिण तमिलनाडु के तटवासियों की आहत भावनाओं पर मलहम लगाना चाहिए। हमें स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय तमिल एक 'बफर स्टेट' की तरह हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि श्रीलंका की तमिल समस्या का समाधान हो। इसके साथ ही मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों का निर्धारण सुनिश्चित होना चाहिए जो अक्सर श्रीलंका के मछुआरों के साथ टकराव का कारण बनते हैं। श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति न केवल तमिल मुद्दे को श्रीलंका सरकार की प्राथमिकता से दूर कर देगी, बल्कि यह भारतीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है। कोलम्बो बंदरगाह का पूर्वी टर्मिनल तथा हंबनटोटा बंदरगाह पहले ही चीन के कब्जे में जा चुका है। विवादास्पद कच्चातिबू भी चीनी प्रभुत्व से खाली नहीं है। चीन ने इस द्वीप पर विंडमिलें लगा रखी हैं और जल्द ही वह यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगा। चीन हिंद महासागर में अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और चीन के सेना प्रशिक्षण शिविर लगातार खुल रहे हैं। ऐसे में यह कहने की जरूरत नहीं कि चीन के कारण मारीशस भी भारत का दुश्मन बन रहा है। एक समय शांतिपूर्ण रहे इस क्षेत्र में दूसरे देशों का दखल बढ़ रहा है जिससे इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने के साथ ही भारत का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। भारत को पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में मालदीव तथा चीन-समर्थक श्रीलंका तथा पूरब में नेपाल व बांग्लादेश से खतरा है।

भारत में वर्तमान समय में लगभग चार लाख मंदिर हैं। इनमें से अधिकांश तमिलनाडु में हैं और इस कारण वह सनातन धर्म का केन्द्र है। वह दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों का भी केन्द्र है। तमिलनाडु की समृद्ध हिंदू विरासत और धार्मिक व्यवहार लगभग सभी पंचलोक मूर्तियों के खुदाई में मिलने से स्पष्ट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-एएसआई व किसानों ने 'संगम युग' की पत्थर की मूर्तियां खोजी हैं। हाल में 6,000 साल पुराने इतिहास तथा 3,200 साल की सभ्यता की खोज को देखते हुए भाजपा को तमिलों के इस हृदय स्थल को स्वीकृति देनी चाहिए। मोदी ने आश्चर्यजनक और प्रशंसनीय रूप से देश और दुनिया में तमिल भाषा और संस्कृति का प्रचार किया है।

उन्होंने इसके लिए 'सेंगोल' तथा 'काशी तमिल संगमम' का प्रयोग किया। पूरे देश को तमिल भाषा, संस्कृति व विरासत की समृद्धि का परिचय कराने में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण सहयोग किया है। भाजपा को इसके आधार पर एक मंच बनाना चाहिए और इसे अपने तीसरे कार्यकाल में नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी दलबदलुओं की पार्टी है।

द्रमुक के पुराने कार्यकर्ताओं को कलैनार के वारिस एम.के. स्टालिन ने हाशिए पर धकेल दिया है। द्रमुक से बाहर गए वाइको ने पहले स्टालिन का विरोध किया था, पर अब वे उनके साथ हैं। द्रमुक में आज महत्वपूर्ण स्थान पर अन्नाद्रमुक के विधायक हैं। ऐसे में यह विश्वास करना कठिन है कि अवसरवादियों से भरी यह पार्टी जनता के लिए काम करेगी। लेकिन उत्तर की राजनीति की तमिलनाडु व केरल में नकल नहीं की जा सकती है। ये दोनों राज्य अपने आप में विशिष्ट हैं, जैसा कि रामास्वामी रेड्डियार ने बहुत पहले ही कह दिया था। उनकी समृद्ध हिंदू विरासत, लोगों की उद्यमी प्रकृति तथा सैकड़ो व हजारों साल से जारी समुद्री व्यापार इनमें प्रमुख है।

इसके साथ ही साक्षरता, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक संकेतकों पर उनका स्तर ऊंचा है। ऐसे में आवश्यतानुसार 'सबके लिए एक नियम' को छोड़ कर इन दोनों राज्यों के लिए विशिष्ट प्रकार की रणनीतियां और कार्ययोजनायें बनाई जानी चाहिए। भाजपा के सामने तमिलनाडु व केरल के किले तोड़ने की कठिन चुनौती है। केन्द्र सरकार के प्रमुख के रूप में इन दोनों राज्यों में चुनावी विजय के लिए आगे बढ़ना काफी नहीं है। इसके लिए जमीनी स्थितियों पर नजर रखना तथा जनता के लिए काम करना जरूरी है जिससे उनमें स्वीकार्यता मिल सके। भाजपा को इन दोनों राज्यों की भावनाओं के अनुरूप काम करना होगा। वर्तमान समय में दोनों राज्यों की स्थिति परिवर्तन के लिए अनुकूल है। देखना होगा कि भाजपा इस अवसर का लाभ उठा पाती है या नहीं?

बच्चों पर मोबाइल विकिरण का प्रभाव

> बच्चों पर मोबाइल फोन के उपयोग का प्रभाव माता-पिता, शिक्षकों और कई स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच बढ़ती चिंता का विषय है।

शाइनी शर्मा
(लेखिका, शिक्षाविद हैं)

जैसा कि हम जानते हैं कि स्मार्टफोन अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी डिवाइस हैं, जिनके कई उपयोग हैं जो उन्हें आधुनिक जीवन में अपरिहार्य बनाते हैं, लेकिन बच्चों पर मोबाइल फोन के उपयोग का प्रभाव माता-पिता, शिक्षकों और कई स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच बढ़ती चिंता का विषय है। आज, मोबाइल डिवाइस कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और विभिन्न मैसेजिंग ऐप के माध्यम से तुरंत संचार की अनुमति देते हैं, जबकि लोग अपने स्थान की परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर जुड़े रहते हैं।

यह दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों और व्यवसायों के साथ आसान संचार को सक्षम बनाता है। वेबसाइट ब्राउज़ करना, जानकारी खोजना, समाचार एक्सेस करना, वीडियो देखना और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ना, ये सब अपनी हथेली से। जबकि मोबाइल फोन एक ही समय में कई लाभ प्रदान करते हैं, वे कई संभावित जोखिम भी पैदा करते हैं, जिनके प्रभावों को मोटे तौर पर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, कल्याण, सामाजिक विकास और शैक्षणिक प्रदर्शन में वर्गीकृत किया जा सकता है।

मोबाइल फोन द्वारा उत्सर्जित रेडियोफ्रीक्वेंसी विकिरण के लंबे समय तक संपर्क में रहना एक चिंता का विषय है, हालांकि इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में शोध जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस विकिरण को संभवत: कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत करता है, लेकिन बच्चों पर इसके प्रभावों के बारे में निश्चित निष्कर्ष अभी भी स्थापित नहीं हुए हैं।

आजकल के बच्चे मोबाइल फोन पर निर्भरता विकसित कर सकते हैं, जिससे लत जैसी आदतें विकसित हो सकती हैं,

जहाँ वे अपने डिवाइस पर अत्यधिक समय बिताते हैं, जिससे अन्य गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। चिंता का कारण यह है कि बच्चे अधिक विकिरण अवशोषित करते हैं क्योंकि वे वयस्कों के समान ही विकिरण के संपर्क में आते हैं क्योंकि वयस्कों की तुलना में उनकी खोपड़ी पतली, सिर छोटा और दिमाग छोटा होता है, जिससे डिजिटल आई स्ट्रेन हो सकता है, जिससे सूखापन, जलन और धुंधली दृष्टि जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा, स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन (नींद को नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन) के उत्पादन में बाधा डालती है, जिससे नींद आने में कठिनाई हो सकती है और नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है क्योंकि ये उत्सर्जन मस्तिष्क को यह एहसास नहीं करा पाते हैं कि रात हो गई है।

इसके अलावा, मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग एक गतिहीन जीवनशैली में भी योगदान देता है, जिससे बच्चे शारीरिक गतिविधियों पर कम समय बिताते हैं, जो उनके समग्र स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक है। सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में चिंता, अवसाद और अकेलेपन के स्तर में वृद्धि हुई है।

मोबाइल फोन से लगातार उत्तेजना के कारण बच्चों के लिए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है, जिससे संभावित रूप से ध्यान की कमी और शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी आई है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे उपकरणों के उपयोग से बच्चों के लिए आमने-सामने सामाजिक संपर्क में शामिल होने के अवसर भी कम हो गए हैं, जिससे सामाजिक कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास में कमी आई है।

हर तकनीक और प्रौद्योगिकी में एक अंतर्निहित विचारधारा होती है। प्रत्येक तकनीकी उपकरण के साथ जिसे कोई व्यक्ति या बच्चा अपनाता है, विश्वदृष्टि उसे समायोजित करने के लिए थोड़ा बदल जाती है और ऐसे उपकरण एक दृष्टिकोण या मूल्य को दूसरे पर अधिक महत्व देते हैं।

इसे कम करने का एकमात्र तरीका माता-पिता और अभिभावक मोबाइल उपकरणों के मध्यम और निगरानी वाले उपयोग को प्रोत्साहित करना, कॉल के लिए हैंड्स फ्री विकल्पों का उपयोग करना और सोने से पहले स्क्रीन का समय सीमित करना है। साथ ही, कम विशिष्ट अवशोषण दर मान वाले उपकरणों को चुनने से विकिरण के संपर्क को कम करने में मदद मिल सकती है।

आप की बात

राहुल की दुविधा

राहुल गांधी आजकल दुविधा ग्रस्त हैं। वे सोच रहे हैं कि उत्तर में जाऊं कि दक्षिण में, अपनी कमाई सीट छोड़ूं कि दादी के आशीर्वाद से क्षमा मांगू, वायनाड छोड़ूँ कि रायबरेली। 14 दिन पूरे होने वाले हैं ऐसे में उनके लिए कानूनन एक सीट छोड़ना जरुरी है। वैसे अधिकांश लोगों का मानना है कि राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ देंगे और वहां के कांग्रेस नेताओं ने इसके लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। राहुल ने अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा में यह डींग हांकी कि यदि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़तीं तो मोदी तीन-चार लाख से चुनाव हार जाते। लेकिन सवाल है कि फिर उनको वाराणसी से चुनाव मैदान में उतारने की हिम्मत कांग्रेस ने क्यों नहीं दिखाई? जहां उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी 6 सीटों पर चुनाव जीतने से बहुत प्रसन्न हैं और राहुल गांधी को रायबरेली सीट पर बने रहने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं केरल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। माकपा नीत सरकार के दो कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव में मिले संकेतों के अनुसार वहां कांग्रेस नीत मोर्चे की सरकार बन सकती है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शायद ही सपा की जूनियर पार्टनर बनने को तैयार हो। इसे देखते हुए राहुल की दुविधा और बढ़ गई है।

–**शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव

मंगलवार 5 नवंबर 2024 बस कुछ ही माह दूर है। इस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। 2019 के चुनाव में सामाजिक विभाजन, नस्लभेद, अवैध आप्रवासी एवं उग्र राष्ट्रवाद, आदि विषयों पर चुनाव लड़ा गया था। इसमें डोनाल्ड ट्रम्प को पराजय का सामना करना पड़ा था। उस पराजय को सहन नहीं कर पाने का परिणाम ये हुआ कि राजधानी के संसद भवन कैपिटल हिल में ट्रम्प के इशारे पर उग्र दक्षिणपंथी उग्रवादियों ने हमला बोला था। मगर 2024 के चुनाव में अभी तक मुद्दे स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। ट्रम्प को एक पोर्न स्टार को गुप्त धनराशि का भुगतान करने एवं अपने व्यापार को बढ़ाने के वास्ते अनैतिक तरीके अपनाने का दोषी ठहराया जा चूका है। इसके साथ ही जो बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन को बंदूक कानूनों के उल्लंघन के सभी तीन आरोपों में दोषी पाया गया है। हंटर बाइडेन ने बन्दूक खरीदते समय अपनी नशाखोरी का उल्लेख नहीं किया, जबकि वे उस समय नशामुक्ति का इलाज करवा रहे थे। ट्रंप पर लगे आरोपों की तुलना में यह बहुत हल्का आरोप है, लेकिन इसे रिपब्लिकनों द्वारा देश के सर्वाधिक वृद्ध राष्ट्रपति बाइडेन पर हमले के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

–**जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

फारूक का पुराना राग

जम्मू-कश्मीर में पाक-प्रायोजित आतंकी घटनाओ में वृद्धि के बीच फारूक अब्दुल्ला ने फिर से पाकिस्तान के साथ बातचीत का पुराना राग अलापना शुरु कर दिया है। उनका यह कहना कतई उचित नही है कि जब तक हम अपने पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे, हम आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। वे पाकिस्तान की खोटी नीयत से जानबूझकर अंजान बन रहे हैं। वे यह क्यों भूल जाते हैं कि बातचीत के बहाने विगत मे पाकिस्तान ने भारत को हजारों घाव दिए हैं। उनके पास इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजना बंद कर देगा? पाकिस्तान के नेताओं ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने को गलत बताया है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती तथा ऐसे ही अन्य लोग उन पुराने दिनों की याद कर रहे हैं जब वे जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझते थे, केन्द्र सरकार से मिलने वाला पैसा हड़प जाते थे तथा पाकिस्तानी राजनयिकों के साथ दावतें उड़ाते थे। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने रिकार्ड मतदान कर उमर अब्दुला को भी हरा दिया है। ऐसे में अब फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों के पुराने राग को कोई सुनने वाला नहीं है, भले ही उनको मीडिया में इससे जगह मिल जाती हो।

– **विमलेश पगारिया,** बदनावर

सांसद निधि

देश के सभी सांसदों को अपने क्षेत्र में जन-सुविधाओं पर खर्च के लिए 5 करोड रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष के कार्यकाल में 25-25 करोड रुपए दिए जाते हैं। इस तरह सरकारी खजाने से अरबों रुपए विकास के नाम पर इन्हें दिए जाते हैं। मगर अधिकांश सांसद इसका उपयोग अपनी इच्छानुसार करते हैं। तो कई सांसद इसे खर्च कर ही नहीं पाते हैं। सांसद निधि के प्रयोग में भारी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि 20 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से हर सांसद अपने चुनाव का खर्च इस संसद निधि से ब्याज सहित निकाल लेता है। सांसद निधि समाप्त करने की मांग बार-बार होती रही है, लेकिन कोई राजनीतिक दल ऐसा करने की स्थिति में नहीं है। अतीत में सांसद निधि बढ़ाने के नाम पर सत्ता व विपक्ष की आश्चर्यजनक एकता देखने में आई है। ऐसे में सांसद निधि के उपयोग पर और कठोर नियम बनाने जरूरी हैं। सांसद निधि प्रयोग के लिए जनता से आनलाइन सुझाव मांगने की परंपरा शुरू की जा सकती है। देश की जनता अपने मोबाइलों के माध्यम से सांसद निधि का उपयोग सुनिश्चित कर सकती है।

– विभूति बुपक्या, खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

इस बार नई संसद के तेवर अलग नजर आएंगे

18वीं लोकसभा की पहली बैठक 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगी। इसमें प्रोटेम स्पीकर चुनकर आए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, जिसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार अपनी कार्य की दशा-दिशा बताएगी। संसदीय लोकतंत्र में सदन का चलना सरकार की जिम्मेदारी है। पहले से ताकतवर विपक्ष को साधना मुश्किल होगा। स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से होने की परम्परा रही है, जो इस बार टूट सकती है। इसका कारण विपक्ष का यह दावा है कि संविधान के अनुच्छेद 93 में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर के चुनाव की अपरिहार्यता के बावजूद पिछले सदन के पूरे काल में यह पद सत्ता-पक्ष ने खाली रखा। पिछली लोकसभा में कई अहम बिल जैसे तीन किसान बिल, तीन तत्काल बिल और तीन नए अपराध न्याय बिल बगैर किसी चर्चा के पारित हो गए थे, जबकि संसद से रिकॉर्ड संख्या में विपक्षी सांसदों को निर्लंबित किया गया। चुनाव परिणाम के बाद से ही सत्ताधारी भाजपा ने संसद में ' देश के विकास के लिए' सहमति के बारे में बात करना शुरू कर दी है। चूंकि 1977 की विपक्षी एकता के बाद यह पहली वास्तविक विपक्षी एकता है जो अस्तित्व में आई है। लिहाजा विपक्ष का रवैया शायद ही समझौतावादी हो। सरकार को पिछले सदन जैसा द्वंद्वात्मक रवैया छोड़ना होगा।

प्रेरणा

जीवन में यदि आपको पीछे नहीं जाना है तो कभी भी पीछे मुड़कर न देखें। - हेनरी डेविड थोरो

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

ptvijayshankarmehta.com

परिवार 'हम' की वृत्ति से बचते हैं, 'मैं' छोड़ना पड़ेगा

मैं और हम, इन दो शब्दों में बहुत पुरानी प्रतिस्पर्धा है। और इसी चक्कर में इनमें झगड़ा भी हो जाता है। हम का मतलब सब मिलकर। मैं का मतलब अहंकार की घोषणा। मैं ही कर सकता हूं। मैं ही करूंगा। यदि मैं नहीं हूं, तो कुछ भी नहीं होगा। हम का मतलब सबके साथ मिलकर चलना। परिवारों में जब मैं हावी होता है तो परिवार टूटते हैं। परिवार बचते ही हम की वृत्ति से हैं। हमें अपने परिवारों में बहुत सारे 'मैं' को ढूंढने की दृष्टि रखना पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे 'मैं' मिलकर हम बन तो जाते हैं, लेकिन अगर 'मैं' को गलाया नहीं गया तो ऊपर से तो सब हम दिखेंगे। लेकिन भीतर से हर एक का 'मैं' अंगड़ाई लेगा और हम वाली व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी। शिवाजी का प्रताप बढ़ता जा रहा था। उनके गुरु रामदास जी ने एक दिन घूमते-घूमते एक स्थान पर एक चट्टान को फोड़ने को कहा और उसे फोड़ा तो उसमें से कीड़ा निकला। गुरु कुछ बोले नहीं पर योग्य शिष्य शिवाजी समझ गए गुरु ये बताना चाहते हैं कि एक पत्थर के भीतर भी कीड़ा जिंदा रह सकता है। कौन रखता है? कोई है ताकत जो हमसे ऊपर है। ईश्वर कहें या सुप्रीम पावर, लेकिन वो है। और जितना उस पर भरोसा बढ़ाओगे उतना मैं गलेगा और हम निर्मित होगा। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • मतदाता ने 'पॉज़' बटन दबा दिया है...

राजनीति की रोमांचक कहानी में आ गया है एक 'इंटरवल'

राजदीप सरदेसाई

वरिष्ठ पत्रकार

rajdeepsardesai52@gmail.com

एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने का सबसे बड़ा मजा इंटरवल का होता है, जो अक्सर तब आता है जब कहानी नाटकीय मोड़ पर होती है। इंटरवल के दौरान ही आप सिनेमाई अंधेरे से बाहर निकलकर रोशनी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। भारत की चुनावी राजनीति भी एक दशक के बाद एक बहुत जरूरी इंटरवल में प्रवेश कर चुकी है, जो एक्शन और नाटकीयता से भरपूर एक दशक के बाद आ रहा है। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, तब से खबरों का चक्र अंधाधुंध रहा है। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक, सांसदों के निलंबन से लेकर किसानों के विरोध तक- हमें सांस लेने के लिए भी मुश्किल से ही समय मिला है। लेकिन अब आखिरकार मतदाता ने 'पॉज' बटन दबा दिया है।

यही कारण है कि 2024 के जनादेश में जरूरत से ज्यादा उधेड़बुन करना एक बड़ी गलती होगी। मोदी प्रशंसक इस बात पर जोर देते हैं कि प्रधानमंत्री अभी भी निर्विवाद नेता नंबर एक हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि भाजपा की 240 सीटें पिछले तीस वर्षों में कांग्रेस के किसी भी प्रदर्शन से अधिक हैं। वहीं मोदी विरोधी आपको बताते हैं कि यह मौजूदा सरकार के खिलाफ जनादेश है : एक सरकार जो '400 पार' का दावा कर रही है, वह अपने दम पर 272 से बहुत कम सीटें ला पाई है लेकिन सच्चाई- जैसा कि अक्सर होता है- इन दोनों अतियों के कहीं बीच में है।

लोकसभा चुनाव परिणामों से भाजपा का अश्वमेध यज्ञ यकीनन थम गया है। देश के तीन बड़े राज्यों- यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल- में पार्टी दूसरे स्थान पर रही। कहां पर गड़बड़ी हुई? इस पर आरोप-प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन यह मान्यता बन गई है कि सर्वशक्तिशाली दिखने वाली भाजपा की चुनावी-मशीन अब अजेय नहीं रही। सीएसडीएस के चुनाव-पश्चात सर्वेक्षण से पता चलता है कि नेतृत्व के सवाल पर यूपी में राहुल गांधी अब मोदी से भी आगे बढ़ चुके हैं। पिछले एक दशक में यह पहली बार है, जब उन्होंने किसी प्रमुख हिंदी भाषी राज्य में मोदी पर बढ़त बनाई है।

और इसके बावजूद कांग्रेस सीटों और वोट-शेयर के मामले में देशभर में भाजपा से काफी पीछे है। भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई में जीती गई सीटों का अंतर उतना तो नहीं है, जितना पांच साल पहले था, लेकिन फिर भी यह काफी हद तक भाजपा के पक्ष में है। एकमात्र राज्य जहां कांग्रेस ने वास्तव में दबदबा बनाया, वह केरल था। लेकिन वहां उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा नहीं, बल्कि वामपंथी थे। कांग्रेस शासित कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन चुनावी अंकगणित 2024 की कहानी का केवल एक हिस्सा बताता है। यह चुनाव इस विश्वास से प्रेरित था कि अकेले 'मोदी की गारंटी' भाजपा को निर्णायक जनादेश दिलाने के लिए पर्याप्त होगी।

यहीं पर भाजपा के चुनाव अभियान प्रबंधकों ने गलती की। वे भूल गए कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कोई भी व्यक्ति लोगों से बड़ा नहीं हो सकता। भाजपा के सौ से अधिक उम्मीदवारों को अन्य दलों से 'आयातित' किया गया था और 132 वर्तमान सांसदों को बदल दिया गया- यह एक अति-आत्मविश्वासी रणनीति को दर्शाता है, जो 'एक नेता, एक राष्ट्र' के नारे के इर्द-गिर्द घूमती है। इस नीति के तहत अन्य सभी उम्मीदवारों को नगण्य माना जाता है।

लेकिन यह रणनीति अब थकावट के बिंदु पर पहुंच गई है। गुजरात और एमपी जैसे भाजपा के 'बैंकर' राज्यों को छोड़कर देश के विभिन्न हिस्सों में मतदाताओं ने किसी व्यक्ति-विशेष से प्रभावित होने के बजाय अधिक स्थानीय विकल्प चुनना पसंद किया है। तीन नतीजे उल्लेखनीय हैं। वाराणसी, जहां जीत के अंतर में 3.2 लाख वोटों की गिरावट देखी गई। फैजाबाद-अयोध्या, जहां जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन को हिंदुत्व के चरम-क्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया था, वहां दलित समुदाय के एक नए चेहरे वाले नेता ने दो बार के अनुभवी सांसद को हराया। और राजस्थान का बांसवाड़ा, जहां मुसलमानों को 'मंगलसूत्र' दिए जाने का डर दिखाया गया था, वहां भारत आदिवासी पार्टी के एक युवा नेता ने जीत हासिल की।

राजनीति में यह 'इंटरवल' कितने समय तक चलेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। यह विधानसभा चुनाव के अगले दौर के नतीजों पर निर्भर हो सकता है। लेकिन यह साफ है कि मतदाताओं ने सहमति, विनम्रता, संघवाद और विविधता को चुना है।

पुनश्च : मीडिया में हममें से कुछ लोगों को भी विनम्रता दिखाते हुए एग्जिट पोल को 'सटीक' बताने के लिए माफी मांगनी चाहिए। हमें भी एक ब्रेक लेने और चुनाव की कहानी को बताने का एक बेहतर तरीका खोजने की जरूरत है, जो सनसनीखेज दावों से कम और मतदाताओं की सामान्य समझ से ज्यादा प्रेरित हो।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस आलेख पर सुझाव एवं प्रतिक्रिया देने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें

नजरिया • पर्सनैलिटी-कल्ट संघ की शैली नहीं है...

क्या हैं भाजपा और संघ के बीच बढ़ती दूरियों के मायने

आरती जेरथ

राजनीतिक टिप्पणीकार

aratijerath@gmail.com

प्रथम दृष्टया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन-सरकार चलाने की लगती है। इसके बावजूद दो ऐसे मोर्चे हैं, जो कठिन हैं, और उन्हें तुरंत नियंत्रण में लाना होगा। एक तो पार्टी के भीतर बढ़ता असंतोष है, जिसने यूपी, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे भाजपा के प्रमुख गढ़ों की अनेक सीटों पर पार्टी की हार में योगदान दिया। पार्टी ने इन चार राज्यों में 59 सीटें खो दीं। 2019 की तुलना में 2024 के चुनावों में इतनी सीटों पर हार के कारण ही भाजपा लोकसभा में 272 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में विफल रही थी। दूसरी समस्या संघ से संबंधों की है। हाल ही में दोनों के बीच तनाव बढ़ा है, जिसके कारण संघ ने भाजपा के लिए हर बार जितने उत्साह से काम नहीं किया। यह भी कई राज्यों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन का एक कारण है।

मतभेद अब सार्वजनिक हो चुका है। सबसे पहले इसको उजागर करने वाले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, जिन्होंने कहा था कि भाजपा को अब संघ की जरूरत नहीं है। उन्होंने चुनाव-प्रचार के बीच में ही यह धमाका कर दिया था। इससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत झटका लगा, जो संघ को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। चुनाव के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत की पहली टिप्पणी ने भी पुष्टि की कि भाजपा-संघ के संबंधों में सच में ही कुछ तनावपूर्ण घटित हो रहा है। भागवत ने अहंकार को लोकसेवक के लिए अनुचित बताया, कटु चुनाव प्रचार के दौरान शिष्टाचार की कमी पर दुःख जताया और संसद चलाने के लिए आम सहमति की आवश्यकता पर जोर दिया।

मोदी 3.0 के लिए अपने ही परिवार के भीतर की समस्याएं अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने से कहीं मुश्किल चुनौती साबित हो सकती हैं। यह टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जदयू के नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बिठाने से भी कठिन हो सकता है। जैसे-जैसे भाजपा के गढ़ों, खासकर यूपी में उसकी हार की भयावहता का अहसास तीखा हो रहा है, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आम कार्यकर्ताओं की आवाजें उभर रही हैं। वे दूसरी पार्टियों से आए दलबदलुओं के लिए उन्हें दरकिनार किए जाने का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। हरियाणा कैडर तो कुप्रबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण साबित हुआ। वहां की दस लोकसभा सीटों में से छह पर भाजपा ने नए-नए उसमें आए कांग्रेसी नेताओं को मैदान में उतार दिया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यकर्ताओं ने खुलकर विद्रोह किया। पार्टी ने पांच सीटें उस राज्य में खो दीं, जहां उसने 2014 और 2019 में एकतरफा जीत दर्ज की थी।

एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द कांग्रेस जैसी हाईकमान-संस्कृति को विकसित करने के खतरे अब साफ नजर आने लगे हैं। विगत दस वर्षों में, भाजपा हाईकमान ने इंदिरा गांधी मॉडल को अपनाया और क्षेत्रीय नेताओं को हाशिए पर करने की नीति लागू की। उनकी जगह एक-आयामी मॉडल विकसित किया गया, जिसके चलते बिना किसी सवाल के दिल्ली से आने वाले आदेशों का पालन करना अपेक्षित था। यह राजनीतिक-प्रबंधन किसी राज्य में भले काम कर सकता हो, लेकिन भारत जैसे बड़े, विविधतापूर्ण देश के अनुकूल नहीं है।

इंदिरा गांधी के हाईकमान-मॉडल ने कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचाया है, उसे समझने के लिए पार्टी के संगठन की दयनीय स्थिति को देखना भर काफी होगा। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय राजनीति की सबसे पुरानी यह पार्टी मजबूत क्षेत्रीय नेताओं की कमी के कारण उन राज्यों में भी निष्प्रभ हो गई है, जो कभी उसके गढ़ हुआ करते थे। वास्तव में, पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि वह इस बार अपने सहयोगियों के साथ 328 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सौदेबाजी नहीं कर सकी, जो अब तक की उसकी सबसे कम संख्या थी।

अटल और आडवाणी जैसे नेता पार्टी में अपने उत्तराधिकारियों को तैयार करके गए थे। भाजपा और संघ के कार्यकर्ता इसी मॉडल के आदी हैं। उनके लिए कांग्रेस जैसी दिखने वाली भाजपा में काम करना मुश्किल साबित हो रहा है।

संघ को 'पर्सनैलिटी-कल्ट' की शैली पसंद नहीं आती है। अटल-आडवाणी ने भी इस शैली को नहीं अपनाया था और राज्य के नेताओं को पोषित किया था। वास्तव में मोदी भी ऐसे ही एक क्षेत्रीय नेता थे। अटल-आडवाणी अपने उत्तराधिकारियों को तैयार करके गए थे। भाजपा और संघ के कार्यकर्ता इसी मॉडल के आदी हैं। उनके लिए कांग्रेस जैसी दिखने वाली भाजपा में काम करना मुश्किल हो रहा है। अगले चार महीनों में तीन महत्वपूर्ण चुनाव (महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड) हैं और फिर 2025 में दो और चुनाव (दिल्ली और बिहार) होने वाले हैं। आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए भाजपा को जल्दी से जल्दी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPdf

भास्कर खास

ब्रांड सक्सेस स्टोरी

एयरबीएनबी | होमस्टे मार्केटप्लेस कंपनी, **कब बनी**- 2008, **मार्केट कैप**- 7.93 लाख करोड़ रु.

एक बेड से शुरू हुई एयरबीएनबी, आज 98% दुनिया में इसकी 77 लाख प्रॉपर्टी

ओला, उबर, जोमैटो या फिर एयरबीएनबी में क्या कोई एक कॉमन चीज है? दरअसल इनका बिजनेस मॉडल एक जैसा है। इन कंपनियों ने खुद की कोई संपत्ति खड़ी करने में खर्च नहीं किया। शेयरिंग आधार पर बिजनेस को आगे बढ़ाया, इसी आर्थिक मॉडल पर आज 133 देशों की 9 हजार से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। आप अपने घर का एक कमरा होटल की तरह गेस्ट के लिए खोलना चाहें या पूरा का पूरा घर कुछ दिनों के लिए किराए पर देना चाहें, एयरबीएनबी के साथ करार कर सकते हैं। इस कंपनी की दुनियाभर में कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन अनोखे बिजनेस आइडिया वाली, 7.93 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप की इस कंपनी ने ट्रैवल और स्टे के बाजार को पूरी तरह बदल दिया है।

सबसे अनोखी प्रॉपर्टी को 1 लाख डॉलर का इनाम देती है एयरबीएनबी

यह तस्वीर कोस्टा-रिका स्थित एयरबीएनबी की एक प्रॉपर्टी की है। इसने एयरबीएनबी की ओएमजी स्कीम के तहत 1 लाख डॉलर का इनाम जीता था।

एयरबीएनबी की सफलता का राज सस्ता किराया है। समुद्री तट, दुर्गम पहाड़ों पर मौजूद घर- बंगले के साथ सेकंड होम रेंटल दुनियाभर में लोकप्रिय हैं। एक सर्वे में अमेरिका के 53 फीसदी लोगों ने माना कि सस्ते दाम के कारण वह होटल्स की तुलना में एयरबीनबी को प्राथमिकता देते हैं। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन जैसे बड़े शहरों में कुल ट्रैवल डिमांड के 10 से 12 फीसदी पर एयरबीएनबी का कब्जा है।

कैसे हुई शुरुआत

बेड और ब्रेकफास्ट के आइडिया से शुरु हुई थी कंपनी

• साल 2007 की बात है। अमेरिका के सैन-फ्रांसिस्को में दो नौजवान ब्रायन चेस्की और जो गेबिया (नेट ब्लेकार्जिक बाद में जुड़े) पैसों की कमी के कारण अपने घर का किराया नहीं भर पा रहे थे। उसी समय सैन-फ्रांसिस्को में एक कांफ्रेंस थी। उन्हें लगा कि इसमें हिस्सा लेने के लिए कई मेहमान आएंगे। ऐसे में वे कुछ मेहमानों को अपने घर पर रुकवा सकते हैं। बदले में थोड़ी कमाई हो जाएगी और उन्होंने एक एयर मैट्रेस (बेड) के साथ रात रुकने का ऑफर देते हुए विज्ञापन किया। इस सर्विस को नाम दिया- 'एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट'। और इस तरह महज 16 साल पहले 2008 में इस कंपनी की शुरुआत हुई।

• संस्थापकों ने होटल इंडस्ट्री में मांग और आपूर्ति में अंतर को महसूस किया, फिर विस्तार किया। एयरबीएनबी होटल की तर्ज पर एक रात से 28 दिन तक रुकने की इजाजत देती है।

क्या चुनौतियां झेली

निवेशकों ने डराया- नकारा, अब होटल इंडस्ट्री के लिए ये चुनौती

• किसी पराए शहर में जाएं तो रुकने के लिए होटल आदि का ही विकल्प हुआ करता था। लेकिन एयरबीएनबी ने लोगों को अपने घर का अतिरिक्त कमरा, दूसरा घर, बंगलो, कॉटेज आदि पर किराए से देने का विकल्प खोल दिया। इससे लोगों को विविधता से भरी और नई-नई जगहों पर रुकने के विकल्प मिल गए। यहां एयरबीएनबी ने बस एक माध्यम बनकर मेजबान और मेहमानों को आपस में मिलाया। यही उसकी कमाई का फॉर्मूला भी बन गया। हर बुकिंग में कमीशन लेकर यह आज दुनिया की दिग्गज कंपनी बन गई है। हालांकि जब इसके संस्थापकों ने यह आइडिया सामने रखा, तो निवेशकों ने इसे सिरे से नकार दिया था।

• 2014 में हुई रिसर्च में पता चला कि एयरबीएनबी से अमेरिका में होटल्स की बुकिंग में 1.3% की गिरावट आई। न्यूयॉर्क में होटल्स को 450 मिलियन डॉलर का सालाना घाटा हुआ।

सेलिब्रिटीज़ को भी जोड़ा

सितारों के बंगले भी किराए पर, भारत की जीडीपी में योगदान

• एयरबीएनबी ने साल 2016 से भारत में अपना कारोबार शुरू किया था। इसकी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भारत में गोवा में है, इसके बाद मुंबई-दिल्ली में हैं। एयरबीएनबी पर्यटकों द्वारा किए खर्च में भी गोवा का हिस्सा सबसे ज्यादा है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एयरबीएनबी ने साल 2022 में गोवा में 850 करोड़ रु. का निवेश किया और अकेले 2022-23 में 11,500 से ज्यादा नौकरियां सृजित कीं। वहीं भारत की जीडीपी में 7,200 करोड़ रु. से ज्यादा का योगदान दिया और 12 महीनों में (मार्च 2023 भी शामिल) 85 हजार से ज्यादा नौकरी दी।

• प्रमोशनल एक्टिविटी के तहत एक दिन के लिए शाहरुख खान का दिल्ली स्थित बंगला एयरबीएनबी पर लिस्ट किया गया था। इस साल भी जाह्नवी कपूर, युवराज सिंह, बाइचुंग भूटिया की प्रॉपर्टी इस पर लिस्ट की गईं।

रोचक : औसतन 4 रातें लोग एयरबीएनबी की प्रॉपर्टीज में बिताते हैं

200 से ज्यादा देशों की 77 लाख प्रॉपर्टी इस पर किराए के लिए उपलब्ध हैं

6 लोग हर सेकंड एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी में चेकइन करते हैं

11 लाख औसतन कमाई हुई एयरबीएनबी होस्ट की, अमेरिका में बीते साल

85 हजार करोड़ रुपए की कमाई रही साल 2023 में, 17% की ग्रोथ रही

40 हजार करोड़ रु. का शुद्ध मुनाफा हुआ, इसमें 153% की ग्रोथ दर्ज हुई

स्रोत : एयरबीएनबी एन्युअल रिपोर्ट

पीपुल भास्कर

चर्चा में | **पवन कल्याण,** दक्षिण भारतीय फिल्मों के स्टार और आंध्र के उप-मुख्यमंत्री

सुसाइड की कोशिश कर चुके हैं, तीन शादियां की, पवन को किताबों का जुनून

जन्म: 2 सितंबर 1968, गोदावरी आंध्र प्रदेश
शिक्षा: दसवीं।
परिवार : पत्नी-अन्ना लेजनेवा। दो बार तलाक, चार बच्चे।
संपत्ति- करीब 165 करोड़
चुनावी शपथ पत्र के अनुसार

एक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, स्टंट कोआर्डिनेटर और अब आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री। यह परिचय है फिल्मों की तरह राजनीति की ब्लॉकबस्टर शुरुआत करने वाले सुपर स्टार पवन कल्याण का। 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट के साथ विधानसभा की 21 सीटें जीतने वाले पवन अब सीधे उपमुख्यमंत्री बने हैं।

हालांकि पवन का व्यक्तिगत जीवन काफी उथल-पुथल भरा रहा। एक साक्षात्कार में वे बताते हैं कि पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। उन्हें कम उम्र में अस्थमा हो गया। लोगों से मिलना-जुलना कम कर दिया तो डिप्रेशन में चले गए। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भाई चिरंजीवी की पिस्टल से खुद को शूट करने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों ने बचा लिया। ऐसा ही कुछ उनका वैवाहिक जीवन भी रहा। उन्होंने तीन शादियां की हैं। उनकी दो शादियां असफल रहीं। 1997 में नंदिनी से शादी की जो 10 साल चली। 2009 में उन्होंने को-स्टार रही रेनू देसाई से शादी कर ली। इससे उनके दो बच्चे हैं। यहां भी पारिवारिक विवाद के कारण दोनों 2012 में अलग हो गए। 2013 में उन्होंने रूसी मॉडल अन्ना लेजनेवा से शादी की। अन्ना तलाकशुदा थी। उन्हें पहले से एक बेटी थी। शादी के बाद अन्ना ने बेटे को जन्म दिया। अब पवन कुल चार बच्चों के पिता हैं।

फिल्मों में ज्यादातर स्टंट खुद करते हैं

शुरुआती जीवन : पढ़ाई में मन नहीं लगा, केवल दसवीं पास

पवन कल्याण के नाम से मशहूर पवन का असली नाम कोनिडेला कल्याण बाबू है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में कोनेडेला वेंकट राव और अंजना देवी के घर हुआ था। पिता कांस्टेबल थे, जिनका नियमित रूप से स्थानांतरण होता रहता था। पवन का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि यही कारण रहा कि वे दसवीं की पढ़ाई तक कई बार फेल हुए। उनके पवन कल्याण नाम अपनाने को लेकर भी एक रोचक कहानी है। पवन करते में ब्लैक बेल्ट हैं। एक दिन मार्शल आर्ट का प्रेजेंटेशन था। इस इवेंट के पहले उन्होंने अपने नाम में पवन जोड़ लिया। इस तरह कल्याण बाबू, पवन कल्याण बन गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपर स्टार चिरंजीवी और फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर नागेंद्र बाबू उनके बड़े भाई हैं। पवन कल्याण ने तीन शादियां की हैं।

करियर : एक्सीडेंटल स्टार से आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री के पद तक

पवन शुरुआत में खेती करना चाहते थे, लेकिन उनकी भाभी सुरेखा ने उन्हें फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1996 में फिल्म 'अक्कड़ा अम्मायी, इक्कदा अब्बायी' से फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद 1997 से 1999 के बीच लगातार चार हिट फिल्में देकर स्टार बन गए। इसलिए उन्हें एक्सीडेंटल स्टार भी कहा जाता है। पवन ने अब तक लगभग 33 फिल्में की हैं, जिसमें कई ब्लॉकबस्टर हैं। वे तेलुगू फिल्मों के सर्वाधिक फीस लेने वाले एक्टर रह चुके हैं। उन्होंने 2008 में भाई चिरंजीवी की पार्टी प्रजा राज्यम के अध्यक्ष के रूप में राजनीतिक करियर शुरू किया। 2011 में चिरंजीवी की पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। चिरंजीवी के इस फैसले से पवन नाखुश हुए। इसके बाद 2014 में उन्होंने जनसेना पार्टी बना ली और कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ का नारा देते हुए कांग्रेस का विरोध किया। 2020 में उन्होंने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। अब वे आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री बन गए हैं।

रोचक : हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने स्पीच देने के लिए किया था आमंत्रित

- उनकी पार्टी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश की 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी जीती हैं।
- 2012 से अब तक फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की सूची में कई बार शामिल हो चुके हैं।
- 2017 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंडिया कॉन्फ्रेंस 2017 के 14वें संस्करण में उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था।
- दक्षिण भारतीय फिल्मों के स्टार एक्टर रामचरण तेजा, अल्लू अर्जुन और वरुण तेज उनके भतीजे हैं।
- पवन को दर्शन, इतिहास और साहित्यिक किताबे पढ़ने का जुनून है। सोशल मीडिया पर फैंस को भी किताबें पढ़ने का सुझाव देते रहते हैं।
- वे अधिकांश फिल्मों में एक्शन सीन खुद करते हैं।
- पवन कल्याण दक्षिण भारत के पहले सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने पेप्सी का प्रचार किया है।
- पवन 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सेलिब्रिटी कैंडिडेट रहे हैं।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 14 जून • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

दस हजार किताबों को पढ़ने से बेहतर, दस हजार मील की यात्रा करना है।

-चीनी कहावत

कुवैत में दर्दनाक हादसा

कुवैत के मंगाफ शहर में आग से जल कर 42 भारतीयों की मौत वाकई तकलीफदेह है। एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में अधिकांश भारतीय नागरिक थे। इनमें सबसे ज्यादा केरल के लोग थे। इनके अलावा, तमिलनाडु और उत्तर भारत के नागरिक भी अच्छी-खासी संख्या में थे। बताया जा रहा है कि इस छह मंजिला इमारत में जो भवन लिया गया था, उसकी क्षमता बेहद कम थी, जबकि वहां 200 से ज्यादा श्रमिकों को ठहराया गया था। स्वाभाविक रूप से यह संवेदनहीनता और घोर लापरवाही का मामला दिखता है। पहले भी यह देखा गया है कि हमारे यहां से बाहर जितनी संख्या में मजदूरों को ले जाया जाता है, उन्हें वैसी सुविधा मय्यसर नहीं होती। इन लोगों को मवेशियों

की तरह ठूंस कर रखा जाता है। यहां तक कि सुवधाओं का सब्जबाग दिखाकर उन्हें बेहद तकलीफ वाली रोजमर्रा की जिंदगी जीने को मजबूर किया जाता है। इस मामले में एक तथ्य ज्यादा गंभीर और युक्तिसंगत है। हमारे देश में रोजगार की जो बुरी गत है, वह किसी से छिपी नहीं है। न केंद्र सरकार के पास रोजगार की कोई संभावना है और न राज्य सरकारों के पास। नतीजतन, युवा बाहरी मुल्कों की तरफ जाते हैं। बिना यह सोचे-समझे कि वहां उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी और क्या विशेषाधिकार मिलेंगे। सही-गलत का तार्किक विश्लेषण करने की बजाय युवा किसी भी कीमत पर नौकरी पाना चाहता है। कुवैत की घटना इसलिए मायनेखेज है कि जिस कंपनी ने इन लोगों को अपने पास बुलाया था, वह इन्हें नौकरी देना तो दूर इनकी जान तक नहीं बचा सकी। ऐसे कई उदाहरण अतीत में देखे गए हैं कि फलां कंपनी ने श्रमिकों को अपने यहां बुलाया और फिर बंधक बना लिया। कइयों की तो वहां मौत भी हो गई। बाहरी देशों में दूतावासों की भूमिका भी सुस्त और गैर-जिम्मेदाराना देखी गई है। क्या बाहरी मुल्कों में भारतीय दूतावास इस बात की पड़ताल नहीं कर सकते कि भारतीय मजदूरों से कंपनी का समझौता किन शर्तों पर हुआ है? सिर्फ रस्मअदायगी करने से हादसे को रोकना नामुमकिन है। रोजगार को लेकर अपने यहां की सरकार को ज्यादा गंभीर बनना होगा। इस बात की पड़ताल भी उन राज्य सरकारों को करनी होगी, जिनके यहां से मजदूर बाहर जा रहे हैं। जब तक सरकारी मशीनरी एकजुट होकर काम नहीं करेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा।

युद्धग्रस्त लाचार बच्चे

संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रपट के अनुसार दुनिया भर में संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के दरम्यान फंसे बच्चों के खिलाफ हिंसा 2023 में चरम पर पहुंच गई। इस्राइल, फिलिस्तीन, सूडान, म्यामार और यूक्रेन में बड़ी संख्या में हत्याएं हुईं और लोग घायल हुए। रपट में सशस्त्र संघर्ष में 18 से कम उम्र वाले बच्चों के खिलाफ हिंसा के मामलों में 21% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। इसमें कांगो, बुर्किना फासो, सोमालिया और सीरिया का भी हवाला दिया गया है। बच्चों की हत्या और उन्हें दिव्यांग बनाने, स्कूलों/अस्पतालों पर हमला करने के लिए इस्राइली सेना को काली सूची में डाला गया। हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादियों को भी बच्चों की हत्या, उन्हें

घायल करने और उनका अपहरण करने के कारण पहली बार सूचीबद्ध किया गया। रूसी सशस्त्र बलों और संबद्ध सशस्त्र समूहों को यूक्रेन में बच्चों की हत्या, उन्हें दिव्यांग बनाने, अस्पतालों-स्कूलों पर हमला करने के कारण लगातार दूसरे साल संयुक्त राष्ट्र ने काली सूची में रखा। गाजा में इस्राइल के आक्रमण के बाद तीस हजार से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अनाथ, बीमार और अभावग्रस्त बच्चे अन्य युद्धग्रस्त पीड़ितों के साथ भुखमरी के शिकार हैं। वहां के करीब दस लाख लोग खाद्य असुरक्षा के चलते दाने-दाने को मोहताज हैं। सूडान में ऐसे लोगों की संख्या पचास लाख से ज्यादा बताई जा रही है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं, जहां किसी भी तरह की राहत पहुंचाना दुष्कर कार्य हो चुका है। ऐसे में इन लाचार बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सैन्य हमलों या आतंकी वारदात को तत्काल रोकने के प्रयास होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाले मासूमों के प्रति अपना क्रूर रवैया बदलते नहीं नजर आ रहे। हमलों को रोकने या युद्धविराम लागू करने और अंतरराष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों का इस्तेमाल कर अब इन बच्चों को सुरक्षा देने के प्रयासों में देरी नहीं की जानी चाहिए। भोजन, दवाइयों और समुचित इलाज की व्यवस्था करने के साथ ही उनके रहने के समुचित इंतजाम भी करने चाहिए। इसके लिए जरूरी है विश्व बिरादरी पहल करे। इस प्रकार की हिंसा को किसी एक देश तक सीमित मानना सही नहीं होगा।

चिंता/ललित गर्ग

बुजुर्गों से दुराव क्यों

देश ही नहीं, दुनिया में वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार, प्रताड़ना, हिंसा बढ़ती जा रही है, जो जीवन को नरक बनाए हुए है। बच्चे अपने माता-पिता के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते। यही पीड़ा वृद्धजन को पल-पल की घुटन, तनाव एवं उपेक्षा से निकल कर वृद्धाश्रम जाने के लिए विवश करती है। एक बड़ा प्रश्न है कि वृद्धों की उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार के इस गलत प्रवाह को किस तरह से रोके? क्योंकि सोच के गलत प्रवाह ने न केवल वृद्धों का जीवन दुश्वार कर दिया है, बल्कि आदमी-आदमी के बीच के भावात्मक फासलों को भी बढ़ा दिया है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को 'एकल, या बार-बार की गई हरकत, या उचित कार्रवाई की कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी भी रिश्ते में घटित होती है, जहां विश्वास की उम्मीद होती है, जो किसी बुजुर्ग को नुकसान या परेशानी पहुंचाती है।' यह एक वैश्विक सामाजिक एवं पारिवारिक मुद्दा है और जो ऐसा मुद्दा है जिस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देने की आवश्यकता है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2024 की थीम 'सभी पहचानों की बुजुर्ग पीड़ितों के लिए सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देना' है। याद रखें, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने में छोटे-छोटे कदम भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन लोगों की आवाज बनें जो खुद के लिए बोलने में सक्षम नहीं हैं, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें। साथ मिलकर, हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर बुजुर्ग अपने बुढ़ापे को गरिमा, आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वस्थता के साथ जी सके। हमारा देश तो बुजुर्गों को भगवान के रूप में मानता है। फिर क्यों आधुनिक समाज में वृद्ध माता-पिता और उनकी संतान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आज वृद्धों को अकेलापन, परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा, दुर्व्यवहार, तिरस्कार, कटुक्तियां, घर से निकाले जाने का भय या एक छत की तलाश में इधर-उधर भटकने का गम हरदम सालता रहता। वृद्ध समाज इतना कुंठित एवं उपेक्षित क्यों है, एक अहम प्रश्न है। वृद्धावस्था मानसिक व्यथा के साथ सिर्फ सहानुभूति की आशा जोहती रह जाती है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां काम करती हैं। वृद्धजन अव्यवस्था के बोझ और शारीरिक अक्षमता के दौर में अपने अकेलेपन से जूझना चाहते हैं पर इनकी सक्रियता का स्वागत समाज या परिवार नहीं करता और न करना चाहता है।

कुंद होती संवेदनाएं

मैन्युअल स्कैवेजिंग

वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

जून 2 से 12 मई, 2024 के बीच उप्र और दिल्ली में सीवर सफाई के दौरान आठ लोगों की मृत्यु के समाचार थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018-23 के पांच सालों के बीच 339 लोग मरे थे। ऐसी मौतों से यह भी उजागर होता है कि भारत में अभी भी असुरक्षित मैनुअल स्कैवेंजिग यानी हाथों से मानवीय अपशिष्ट मल उठाना और ढोना जारी है जबकि मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और सूखे शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के लागू होने के साथ ही मैनुअल स्कैवेंजिग गैर-कानूनी हो गई थी। 2008 में भारत सरकार ने अध्यादेश ला सफाई के लिए उपकरण देना अनिवार्य कर दिया था । इसके बाद प्रोहिबिसन ऑफ एम्पलॉयमेंट ऐज मैनुअल स्कैवेन्जर्स एंड दियर रिहैबलीटेशन एक्ट, 2013 ने स्थिति को और भी पुष्ट कर दिया था। कुछ लोग सफाईकर्मियों की सीवरों में मौतों को हत्याएं कहते हैं वहीं समाचारों के अनुसार 2019 में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ भी कह चुकी है कि दुनिया में कोई दूसरा देश इस तरह अपने लोगों को गैस चेम्बर में मरने को नहीं भेजता।

न्यायालयों की चिंता यह भी रहती हैं कि मैला सफाई के लिए सीवरों और सैप्टिक टैंकों में जाने का दबाव दलितों पर ही रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2024 में मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गंगापुरवाला और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की बेंच ने एक सुनवाई के दौरान बिना लाग लपेट सुना दिया था कि मैले की हाथों से साफ-सफाई करवाना गहराई में जड़ जमाए जातिवाद और भेदभाव भी दर्शाता है और इसे एक तरह से राज्य से स्वीकृति प्राप्त है।

बेंच ने मैनुअल स्कैवेंजिग एकदम समाप्त करने संबंधी निर्देश भी दिए। इसके पूर्व अप्रैल, 2021 में तमिलनाडु हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीब बैनर्जी की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि सीवर सफाई करते सीवर टैंक में उतरे किसी सफाईकर्मी की यदि मौत होती है तो उसके लिए निकाय प्रमुखों को जिम्मेदार बना उनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हों। पीठ का कहना था कि जब तक यह नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। तब तमिलनाडु में फरवरी, 2021 से अप्रैल, 2021 तक 6 सफाईकर्मियों की सीवरों में मौत हो गई थी। आधिकारिक रूप से 30 जुलाई, 2023 तक देश में 58,098 हाथ से मैला साफ करने वाले चिन्हित कर लिए गए थे।

विडम्बना है कि खुले में शौच से मुक्ति के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बने व बनते

लाखों शौचालयों के सैप्टिक टैंकों के भरने पर उनको खाली करने के लिये मैनुअल स्कैवेजिंग की जरूरत और ही बढ़ी है। उनका सीवर लाइनों से जुड़ना बहुत बाद में होता है। हमें न भूलना होगा कि सीवरों और सैप्टिक टैंकों में घुसे श्रमिक मल निकासी या अवरोधों को खोलने में जब हादसों के शिकार होते हैं तभी खबरें बनती हैं अन्यथा प्रति दिन ही सैकड़ों जगह सीवरों में सैप्टीक टैंकों में श्रमिक बिना सुरक्षा उपकरणों के उतरे रहते हैं। दुखद तो यह है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को जो नगर निकाय या ठेकेदार सीवर सफाई के काम पर रखते हैं वे भी कई बार तो उनके कर्मियो की मौतों और हादसों की जिम्मेदारी भी नहीं लेते।

आक्रोशित और चिंतित न्यायालयों की सख्त टिप्पणियां समाज को आईना दिखाती हैं और यथार्थपरक और संवेदना जगाने वाली अवश्य रही हैं। कोर्ट निर्देशों और आदेशों के देने से ज्यादा कर सकते हैं। वे सीवरों में मौतों का स्वतः संज्ञान भी ले रहे हैं-3 मई, 2024 मप्र हाईकोर्ट ने ग्वालियर के बिरला नगर में सीवर चेम्बर सफाई के दौरान दो श्रमिकों की मौत की संज्ञान याचिका ली थी किन्तु जैसा कानूनों का ठीक से पालन हो तो सीवर से संबंधित दुर्घटनाओं में कमी आ जाए। हर जिम्मेदार अधिकारी, ठेकेदार या आम नागरिक यदि यह तय कर ले कि अपने देखे अपनी मौजूदगी में वह बिना सुरक्षा उपकरणों या कवचों के किसी सफाईकर्मी को सीवरों और सैप्टिक टैंकों में घुसने नहीं देगा तो सफाईकर्मियों की मौत या स्थायी और अस्थायी दिव्वयांगता की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी किन्तु संवेदनाएं इतनी चूकी हुई हैं कि नामी-गिरामी मॉल्स, अस्पतालों, संस्थानों और आवासीय परिसरों में जहां अच्छे-खासे शिक्षित और रसूखदार लोग रहते हैं, वहां के सीवरों में भी मैनुअल स्कैवेंजर्स अपनी जान, अपनी चेतना और अंगों की कार्यशीलता खो रहे हैं। 21 अगस्त, 2017 में जब दिल्ली के एक प्रमुख अस्पताल में एक सफाईकर्मी की मौत हुई थी तब वह वह एक महीने के भीतर दिल्ली में दसवीं मौत थी।

दुखद है कि देश के सरकारी अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में भी ऐसी मौतें हो रही हैं। यही नहीं आम नागरिक भी अपने घरों के सैप्टिक टैंकों की सफाई के लिए अनियोजित क्षेत्र के मजदूरों को बुलाते हैं, तो वे नहीं देखते कि वह बिना सुरक्षा उपकरणों के ही काम कर रहा है। उप्र में 3 मई, 2024 को नोएडा में निजी आवास के सैप्टिक टैंक की सफाई में दो दिहाड़ी मजदूरों की मौत हुई थी।

जरूरत श्रमिकों को भी इस बारे में जागरूक करने की है कि कौन-कौन ऐसे सुरक्षा उपकरण हैं जिनके साथ ही उन्हें सीवरों में उतरना चाहिए। इनको उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदारों पर भी दबाव बनाना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। सीवरों में जा अचेतों को खुद को बचाते हुए ऊपर पहुंचवाने के लिए भी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। हम जाड़ों में दिल्ली के अतिशय गंभीर हालात की गैस चेम्बरी वातावरण से तुलना कर देते हैं। बताने लगते हैं कि यहां रहते जीवन कितना कम हो रहा है किन्तु सीवरों और सेप्टिक टैंकों के वास्तविक गैस चेम्बर में नित काम करने वाले दलितों पर संवेदनाएं कुंद रहती हैं। 20 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अधिकारियों को सीवर सफाई करते हुये मृतकों को तीस लाख रुपये, स्थायी विकलांगता के लिए 20 लाख मुआवजा और अस्थायी विकलांगता के लिए कम से कम दस लाख का मुआवजा देना होगा।

> हर जिम्मेदार अधिकारी, ठेकेदार या आमजन तय कर ले कि अपने देखे अपनी मौजूदगी में बिना सुरक्षा उपकरणों के किसी सफाईकर्मी को सीवरों और सैप्टिक टैंकों में घुसने नहीं देगा तो सफाईकर्मियों की मौत या स्थायी/अस्थायी दिव्वयांगता की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी किन्तु संवेदनाएं इतनी चूकी हुई हैं कि नामी-गिरामी मॉल्स, अस्पतालों, संस्थानों और आवासीय परिसरों, जहां अच्छे-खासे शिक्षित लोग रहते हैं, में भी मैनुअल स्केवैजर्स अपनी जान खो रहे हैं

- रक्तदान करने वाले की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वजन कम से कम 50 किग्रा. होना चाहिए -उसे कोई गंभीर बीमारी या कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। टैटू बनवाने के बाद छह महीने तक रक्तदान नहीं करना चाहिए
- महिलाएं मासिक धर्म, गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान रक्तदान नहीं कर सकतीं। रक्तदान करने वाले ने पिछले 12 महीनों में किसी दूसरे शख्स से रक्त न लिया हो

मीडिया इनपुट्स

जहां हमें मस्तिष्क-तर्क बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए उस राजनीति में हृदय और भावनाओं से काम लेते हैं। जहां केवल निर्मल-निश्छल हृदय ही काम आता है उस धर्म-भक्ति-अध्यात्म में मस्तिष्क-तर्क वितर्क का प्रयोग करते हैं।

राहुल देव, पत्रकार
@rahuldev2

वैश्विक परिदृश्य में हिंदी भाषा का प्रसार

दूरवर्ती शिक्षा **प्रो. सरोज शर्मा**

भाषा मात्र अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति के भावों, विचारों, विश्वासों, रीति-रिवाजों, सभ्यता और संस्कृति की संवाहिका भी है। यदि भारत की संस्कृति और आचार-विचार के विभिन्न आयामों को जानना-समझना है तो हिन्दी भाषा और साहित्य को सीखना आवश्यक हो जाता है। यदि भारतीय जनमानस तक अपनी बात पहुंचानी हो तो हिन्दी की शरण लेनी ही होगी। दैनिक जीवन, राजनीति, व्यवसाय, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया, फिल्मों और इसी प्रकार के विविध क्षेत्रों में हिन्दी का प्रभाव व्याप्त है।

यह परिलक्षित हो रहा है कि हिन्दी धीरे-धीरे विश्व-भाषा का गौरव प्राप्त कर रही है। विश्व के अनेक देशों में हिन्दी पढ़ी, लिखी ,बोली और समझी जाती है। यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज हिन्दी में विश्व की रुचि भारत में वैश्विक रुचि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। विदेशी भारत में काम करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, नये कौशल सीखना चाहते हैं। यदि वे हिन्दी जानते हैं तो उनके लिए किसी अन्य भाषा की भांति एक पूर्णतया नई दुनिया के द्वार खुल जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध भारत को देखने की उत्कंठा से बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक भारत आते हैं। विदेशी नागरिक भारतीय समाज का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति और रीति-रिवाजों को जानना चाहते हैं। हिन्दी सीखे बगैर भारत की धड़कन को समझना संभव नहीं है।

अपनी लोकप्रियता के कारण हिन्दी बहुत समय से विश्व पटल पर छाई है। विश्व भर में रोजगार के लिए गए भारतीयों ने हिन्दी के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक पहचान को संजीवित रखा है। हिन्दी के महत्त्व को देखते हुए विश्व के कई देशों जैसे-मॉरीशस, अमेरिका, ट्रिनिडाड और टोबैगो तथा दुबई के रेडियो से हिन्दी में समाचार और हिन्दी फिल्मों के गीतों और वार्ता के प्रसारण का चलन भी बढ़ा है। इससे हिन्दी की लोकप्रियता और बढ़ी है। नेशनल ज्यॉग्राफिक और डिस्कवरी जैसे चैनल भी ज्ञान-विज्ञान से जुड़े अपने कार्यक्रम हिन्दी में प्रसारित कर रहे हैं।

विश्व भर में हिन्दी की लोकप्रियता को बढ़ाने में फिल्मों ने बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में हिन्दी

को संपर्क भाषा के रूप में सशक्तता से विकसित करने के लिए विदेशियों और हिन्दीतर भाषी लोगों के लिए हिन्दी का पठन-पाठन अत्यंत आवश्यक है। ऐसा देखा गया है कि औपचारिक विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में भाषा अध्ययन करने के बाद भी हिन्दीतर भाषी शिक्षार्थी परीक्षा तो पास कर लेते हैं परंतु भाषा के व्यावहारिक उपयोग में कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। अनौपचारिक रूप से सीखी हिन्दी औपचारिक विद्यालयों में द्वितीय भाषा के रूप में सीखी हिन्दी से अधिक कारगर सिद्ध होती है। भाषा एक प्रमुख उपकरण है जिसे हम वास्तविक समाज में व्यवहार करने के लिए सीखते हैं। द्वितीय भाषा के शिक्षार्थी को भी हिन्दी भाषा का वास्तविक स्थितियों में प्रयोग करना आना चाहिए। कोई भाषा सीखना केवल शब्दों को जानना, व्याकरणिक अभ्यास करना मात्र ही नहीं, अपितु भाषा में सोचने के लिए अभिप्रेरित करना भी है। अतः ऐसी पाठ्यचर्या तैयार की जाने की आवश्यकता है, जो द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में संप्रेषण के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने एक नूतन प्रयोग करते हुए प्रारंभिक स्तर पर छह माह की अवधि के लिए 'आरंभिका' पाठ्यक्रम विकसित किया है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिन्दीभाषियों के साथ सामान्य बातचीत करने की क्षमता विकसित करना, आवश्यकताओं को व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना है। साथ ही, अभिवादन, दैनिक गतिविधियों, सामान्य वस्तुओं की खरीदारी जैसी रोजमर्रा की स्थितियों में बातचीत करने की क्षमता विकसित करने के अलावा यह बाजारों, पर्यटन स्थलों आदि जहां हिन्दी भाषा प्रचलित है, वहां स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की क्षमता विकसित करने में सहायता करेगा। हिन्दी के माध्यम से भारतीय समाज, जीवनशैली, संस्कृति, भोजन आदि का ज्ञान प्रदान करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है।

इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य समूह किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति है जो प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी बोलना और वास्तविक परिस्थितियों में इसका उपयोग करना चाहता है। इसमें विदेशी नागरिक, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग और वे भारतीय जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, और हिन्दी सीखना चाहते हैं, वे सभी शामिल हैं। एनआईओएस द्वारा अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से विविध देशों में हिन्दी भाषा के प्रसार और भारतीय संस्कृति से परिचित कराने का लक्ष्य है। साथ ही 'आरंभिका' पाठ्यक्रम को प्रसारित करने की योजना है ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इसी प्रकार के अन्य उपयोगी कदम भाषा और संस्कृति के पोषक बनेंगे।

समाज निर्माण **श्रीराम शर्मा आचार्य**

हममें से हर व्यक्ति अपने को समाज का अविच्छिन्न अंग माने। अपने को उसके साथ अविभाज्य घटक माने। सामूहिक उत्थान और पतन पर विश्वास करे। एक नाव में बैठे लोग जिस तरह एक साथ डूबते या पार होते हैं, वैसी ही मान्यता अपनी रहे। स्वार्थ और परमार्थ को परस्पर गूंथ दें। परमार्थ को स्वार्थ समझें और स्वार्थ सिद्धि की बात कभी ध्यान में आए तो वह संकीर्ण नहीं उदात्त एवं व्यापक हो। मिल-जुल कर काम करने और मिल-बांट कर खाने की आदत डाली जाए। मनुष्यों के बीच सज्जनता, सद्भावना एवं उदार सहयोग की परंपरा चले। दान विपत्ति एवं पिछड़ेपन से ग्रस्त लोगों को पैरों पर खड़े होने तक के लिए दिया जाय। साधारणतया मुफ्त में खाना और खिलाना अनैतिक समझा जाए। भिक्षा व्यवसाय पनपने न दिया जाए। हर क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने के लिए उदार श्रमदान और धनदान को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाए। किसी मान्यता या प्रचलन को शाश्वत या सत्य न माना जाए, उन्हें परिस्थितियों के कारण बना समझा जाए। उनमें जितना औचित्य, न्याय और विवेक जुड़ा हो उतना ग्राह्य और जो अनुपयुक्त होते हुए भी परंपरा के नाम पर गले बंधा हो, उसे उतार फेंका जाए। संयुक्त परिवार से लेकर संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त विश्व को लक्ष्य बना कर चला जाए। सभी प्रकार के विलगावों को निरस्त किया जाए। व्यक्ति की सुविधा की तुलना में समाज व्यवस्था को वरिष्ठता मिले। प्रशंसा ऐसे ही प्रयत्नों की हो जिन्हें सर्वोपयोगी कहा जाए। व्यक्तिगत समृद्धि, प्रगति एवं विशिष्टता को श्रेय न मिले। अवांछनीय मूढ़ मान्यताओं और कुरीतियों को छूत की बीमारी समझा जाए। वे जिस पर सवार होती हैं, उसे तो मारती ही हैं, अन्यान्य लोगों को भी चपेट में लेती और वातावरण बिगाड़ती हैं। इसलिए उनका असहयोग, विरोध करने की मुद्रा रखी जाए। समाज के किसी अंग पर हुआ अनीति का हमला समूचे समाज के साथ बरती गई दुष्टता माना जाए और उसे निरस्त करने के लिए जो मीठे-कड़ुवे उपाय हो सकते हों, उन्हें अपनाया जाए। अपने ऊपर बीतेगी तब देखेंगे, इसकी प्रतीक्षा करने की अपेक्षा कहीं भी हुए अनीति के आक्रमण को अपने ऊपर हमला माना जाए और प्रतिकार के लिए दूरदर्शितापूर्ण रणनीति अपनाई जाए।

रीडर्स मेल

रोकना होगा युद्ध

रूस-यूक्रेन युद्ध मानवता को शर्मसार कर रहा है। इस युद्ध में लाखों निर्दोष लोगों की बलि चढ़ गई। युद्ध को रोकने के सारे प्रयास विफल साबित हुए, क्योंकि प्रारंभ से ही अमेरिका अग्नि में घी डालने का कार्य कर रहा है। युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों के बिक्री बढ़ गई है। पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ मची है। अभी तक इस युद्ध में हार-जीत का निर्णय नहीं हो सका है। भारत शुरू से ही शांति बहाल करने की अपील करता रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। यूक्रेन एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों की अगुआई में स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारतीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था, लेकिन प्रधानमंत्री अपने स्थान पर विदेश सचिव को भेज रहे हैं। भारत के विदेश सचिव के पास युद्ध रोकने का एक अवसर है, उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता से युद्ध रोकने का प्रयास करना चाहिए।

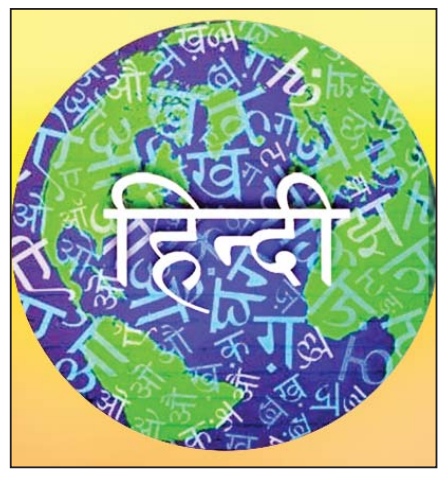

हिमांशु शेखर , गया

तकलीफ की बात

अहिंसा, शांति, विश्व कल्याण व मानवता के सच्चे पक्षधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा कनाडा के बाद इटली में तोड़ी गई। जब जी-7 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है उसके ठीक पहले जब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इटली की यात्रा कर रहे हैं, उसी समय इस तरह की नाकारात्मक पक्ष रखना व चरमपंथी खालिस्तानी समर्थकों द्वारा विृव शांति दूत महात्मा गांधी जी की प्रतिमा में तोड़फोड़ करना बहुत गलत कृत्य है। किसी पंथ धर्म या जात-पात से अलग विशेषता सिर्फअपने राष्ट्र को महत्त्व देना चाहिए। जिस अहिंसा के लिए महात्मा गांधी जी शहीद हुए उनकी प्रतिमा को विश्व में कहीं भी हो; उसे तोड़ना विश्व शांति व मानवीय मूल्यों का पतन ही कहा जाएगा। जो बात अहिंसा के पंथ पर चलकर महात्मा गांधी जी ने पूरे विश्व के पटल पर रखी थी उस महान व्यक्तित्व पर इस तरह के चरमपंथी खालिस्तानी समर्थक भारत के खिलाफ जो आग उगल रहे हैं वह बहुत ही तकलीफदेह है।

हरिहर सिंह चौहान, इंदौर

सांसद निधि का सदुपयोग हो

तीन दशक पूर्व नरसिंह राव के कार्यकाल में शुरू हुई 'सांसद निधि' योजना का औचित्य बेशक प्रशासनिक लालफीताशाही के मद्देनजर स्थानीय बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रहा होगा किंतु इस निधि का सदुपयोग सांसद अपने राजनीतिक दुराग्रहों के कारण अक्सर करते नहीं दिखते हैं, जिसके कारण सांसद निधि कई बार लैप्स हो जाती है। सांसद यदि अपने राजनीतिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों को छोड़ अपने-अपने क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, पुस्तकालय, शौचालय, औषधालय एवं जलाशय जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरी करने के लिए इस निधि को खर्च कर दें तो यह योजना बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बेशक गांवों में सफाई, जन परिवहन, बदहाल सड़कें, संकरी गलियां, तंग रास्ते और दूषित पानी के लिए पानी-पानी होती बस्तियां सांसद निधि से संवारी जा सकती हैं। अतः लाजिम है सांसद निधि को खर्च करना सदस्य के लिए सांविधिक प्रावधान किया जाए तभी इसका औचित्य बना रहेगा।

मामचंद सागर, ई मेल से

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 301
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

निवेश वृद्धि की आशा

निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलायी जा रही उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ स्कीम) से दूरसंचार, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण, वाहन, विशिष्ट इस्पात, बैटरी, दवा समेत 14 क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इससे निर्यात, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा एवं चिकित्सा उपकरण, मशीन आदि, में भी उत्साहजनक वृद्धि हुई है. इस आधार पर यह आशा जतायी जा रही है कि आगामी चार वर्षों में इस योजना के तहत तीन से चार लाख करोड़ रुपये का निवेश हो सकता है. निवेश एवं रेटिंग के क्षेत्र में सक्रिय स्वतंत्र संस्था आइसीआरए का अनुमान है कि उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निजी निवेश आकर्षित होगा. इस निवेश से सेमीकंडक्टर, सोलर मॉड्यूल, दवा आदि अनेक क्षेत्रों में व्यापक विकास होने की संभावना है. इससे दो लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की आशा भी है. केंद्र सरकार ने 2021 में 14 क्षेत्रों में पीएलआइ स्कीम की घोषणा की थी. इस योजना का कुल आकार 1.97 लाख करोड़ रुपये है. नवंबर 2023 तक इसमें एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ चुका था तथा 6.78 लाख से अधिक लोगों को रोजगार हासिल हो चुका है. उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' का आह्वान किया था. इसमें यह संकल्प लिया गया है कि भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकाधिक उत्पादन अपने देश में ही करे. हमारा घरेलू बाजार बहुत बड़ा है और विदेशों से भी बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति होती है. ऐसे में उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता उत्कृष्ट हो. जब गुणवत्ता उत्कृष्ट होगी, तो हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उन्हें बेच सकते हैं. साथ ही, भारत सरकार का लक्ष्य है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हमारी हिस्सेदारी बढ़े. इसके लिए यह योजना लायी गयी है, जिसमें उत्कृष्ट उत्पादन एवं निर्यात के लिए सरकार कुछ अनुदान और छूट मुहैया कराती है, जो कुल उत्पादन खर्च का चार से छह प्रतिशत होता है. भारत देशी-विदेशी कंपनियों को भी अर्थव्यवस्था के विकास का सहयात्री बना रहा है. विभिन्न कारणों से अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की तुलना में सरकार का खर्च अधिक रहा है. लेकिन अब स्थिति बदल रही है. हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक दर से आगे बढ़ रही है तथा निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ना यह इंगित करता है कि दूसरे देशों में भारतीय उत्पादों के प्रति भरोसा बढ़ रहा है. ऐसे में घरेलू और विदेशी निवेशकों का आकर्षित होना स्वाभाविक ही है.

आगामी चार वर्षों में पीएलआइ योजना के तहत तीन से चार लाख करोड़ रुपये का निवेश हो सकता है.

नीट मामले के दोषियों को कड़ी सजा मिले

विराग गुप्ता
वकील, सुप्रीम कोर्ट
@viraggupta

नीट परीक्षा में धांधली पर कई चरणों में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के खुलासों से साफ है कि दाल में बहुत कुछ काला है. बिहार और गुजरात पुलिस की जांच से अगर पेपर लीक भी साबित हो जाए, तो फिर पूरी दाल ही काली हो सकती है. पेपर लीक के बारे में एनटीए ने इनकार किया है. लेकिन नकल और इंपर्सोनेशन, यानी किसी दूसरे ने परीक्षा दिया है, के आरोप सही साबित हो रहे हैं. नीट ने अब मान लिया है कि अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के 63 मामले सामने आये हैं. इनमें से 23 को अलग-अलग अवधि के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया गया है और शेष उम्मीदवारों के नतीजे रोक दिये गये हैं. केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार ग्रेस मार्क को खत्म कर 1,563 छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. उनका रिजल्ट 30 जून के पहले आने से काउंसिलिंग में ज्यादा विलंब नहीं होगा.

बड़े विरोध और सोशल मीडिया में बढ़ रहे दबाव के बाद केंद्र सरकार ने आंशिक कार्रवाई की है. पूरे मामले में कई तरह की विसंगतियां, विरोधाभास और आपराधिकता के पहलुओं पर जांच और कार्रवाई का मुद्दा अभी बरकरार है. परीक्षा में आवेदन करने की तारीख में बेवजह बढ़ोतरी और दो हफ्ते पहले ही रिजल्ट घोषित करने से पैदा हुए संदेह का निराकरण भी जरूरी है. परीक्षाओं और नौकरियों में बढ़ रही धांधली का नेताओं और राजनीति से चोली-दामन का साथ है. लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने हजारों शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी. इसलिए चुनाव परिणाम वाले दिन एडवांस तरीके से रिजल्ट घोषित करने पर हो रही आलोचना पर सरकार की ओर से साफगोई जरूरी है. राज्यों में पुलिस की जांच, निष्क्रिय केंद्र सरकार, एनटीए की संदिग्ध जांच समिति, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जलेबी की तरह जटिल होते मामले से छात्रों और उनके परिजनों में गुस्सा और निराशा बढ़ रही है. लोकसभा चुनाव में एक-तिहाई वोटरों ने वोट नहीं डाला क्योंकि युवाओं में सिस्टम के प्रति निराशा थी. चुनावों में रोजगार और शिक्षा के मुद्दे सबसे अहम थे. नीट परीक्षा में हुई धांधली पर समय से कार्रवाई नहीं हुई, या इस पर व्यापम की तरह लंबी खिचड़ी पकी, तो युवाओं का संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा और डगमगा सकता है. जिन सेंटरों में नकल, फर्जीवाड़ा और गलत तरीके से ग्रेस मार्क देने के आरोप हैं, ऐसे सभी संदिग्ध छात्रों, उनके अभिभावकों, कोचिंग संस्थानों और परीक्षा केंद्र के इंचार्ज लोगों का लाइव नार्को टेस्ट होना चाहिए. इससे मेरिट वाले छात्रों का सिस्टम में भरोसा बढ़ने के साथ भविष्य में धांधली करने वालों के मंसूबे ध्वस्त होंगे. पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से ठोस कार्रवाई कर नयी सरकार को जनता का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए. अन्यथा तमिलनाडु सरकार की यह बात सही साबित होगी कि नीट की परीक्षा प्रणाली गरीब और ग्रामीण विरोधी है. तक्षशिला और नालंदा के दिनों से भारत में विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता उच्च कोटि की रही है. विकसित भारत के लिए हम जनसांख्यिकीय लाभांश की बात करते हैं, पर लालफीताशाही और भ्रष्टाचार के कारण योग्य बच्चे अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाकर पैसा और नाम कमाने में ज्यादा इच्छुक हैं.

उदारीकरण के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मुनाफे की संस्कृति बढ़ी. मेडिकल की पढ़ाई सबसे ज्यादा खर्चीली है. नीट परीक्षा पास कराने के नाम पर कोचिंग और सॉल्वर गैंग का बढ़ता जाल देश का बड़ा कैंसर हैं. महामारियों और बीमारियों से निपटने के लिए हमें योग्य, मानवीय और बेहतरीन डॉक्टर चाहिए. संसद में एक-तिहाई सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिससे लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है. इस तरह अगर कोचिंग माफिया के भ्रष्ट सहयोग से गलत लोग मेडिकल प्रोफेशन में आ गये, तो भयावह स्थिति पैदा हो जायेगी. राजनीतिक हस्तक्षेप, कोचिंग माफिया, धन-बल के बढ़ते प्रभाव से धांधली के चलते शिक्षा के साथ नौकरियों की गुणवत्ता गिरने से शैक्षणिक अराजकता बढ़ रही है. कोचिंग माफिया और सॉल्वर गैंग की भ्रष्ट मिलीभगत से अयोग्य और धनपशुओं के मेडिकल प्रोफेशन में आने से पूरी सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है. व्यापम घोटाले से साफ है कि पुलिस और सीबीआइ की लंबी जांच के बाद पीड़ित लोगों का भविष्य अंधेरी सुरंग के हवाले हो जाता है. जनहित याचिका के नाम पर पब्लिसिटी का कारोबार बढ़ने के बावजूद पीड़ितों को न्याय नहीं मिलना बेहद चिंताजनक है. वर्ष 2022 की नीट परीक्षा से जुड़े लंबित मामले को अर्थहीन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने याचिका को निरस्त कर दिया है. यह मामला व्यापम की तरह न भटक जाए, इसके लिए हाईकोर्ट में चल रहे सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट को अपने पास हस्तांतरित कराना चाहिए. अपराध और धांधली के सभी पहलू अदालत के सामने आ सकें, इसके लिए एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र वकील) नियुक्त करने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़े मामले में मई में ही त्वरित सुनवाई होती, तो शायद इतना बवाल नहीं होता. अगर नीट की पवित्रता प्रभावित हुई है, तो समय पर न्याय देकर जजों को संविधान की शपथ पूरी करनी ही चाहिए. मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सोशल मीडिया में नेशनल ठगी एजेंसी नाम से शर्मसार किया जा रहा है. डॉक्टरी की प्रवेश परीक्षा नीट में अनेक तरह की धांधली, मक्कारी और पेपर लीक से लाखों परिवारों का सपना टूटने के साथ बच्चे मनोरोग और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. मेडिकल वाली नीट में ऑफलाइन परीक्षा और इंजीनियरिंग की जेईई में ऑनलाइन परीक्षा के दोहरे रवैये से भी समाज में बेचैनी है. प्रतिभा को बढ़ावा देने के नाम पर बनाये गये एनटीए की परीक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत मेरिट को आंकने की सही प्रणाली नहीं बनने से कोचिंग संस्थानों का धंधा और जोर पकड़ता जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अमेरिका में एक भाषण में कहा था कि सभी मामलों को अदालतों में ठेलना अच्छी बात नहीं है. परीक्षाओं में धांधली और कोचिंग के गोरखधंधे को रोकने के लिए नीट विवाद से जुड़े सभी दोषियों को जल्दी कठोर दंड मिलना चाहिए.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

सुप्रीम कोर्ट में नीट से जुड़े मामले में मई में ही त्वरित सुनवाई होती, तो शायद इतना बवाल नहीं होता. अगर नीट की पवित्रता प्रभावित हुई है, तो समय पर न्याय देकर जजों को संविधान की शपथ पूरी करनी ही चाहिए. मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और यूनिवर्सिटी-कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सोशल मीडिया में नेशनल ठगी एजेंसी नाम से शर्मसार किया जा रहा है.

उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता

प्रो शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित
कुलपति
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली
santishreepandit@gmail.com

चुनावी हलचल के थमने और नयी सरकार के पदभार संभालने के साथ आगामी पांच वर्षों के एजेंडे को लेकर चर्चा तेज हो गयी है, जिसमें उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है. राजनीतिक शक्ति आख्यान की शक्ति पर निर्भर होती है. बड़े बदलावों की बात क्या करें, बीते एक दशक में आख्यान में परिवर्तन के लिए भी कुछ खास नहीं किया गया. यह समय है कि बौद्धिक और विद्वान बड़े बदलाव के लिए प्रयासरत हों, जो विविधता को मान देते हुए समावेशी हो. एक समानता और केंद्रीकरण आख्यान की शक्ति को अवरुद्ध कर सकते हैं. सार्वजनिक शिक्षा में निवेश सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.3 से बढ़ाकर छह प्रतिशत नहीं हो सका है, जबकि इसे 10 प्रतिशत होना चाहिए क्योंकि शिक्षा जहां है, वहीं आख्यान की शक्ति है. दस वर्ष पूर्व सरकार के सामने लंबित कार्यों और अप्रभावी संस्थाओं की चुनौती थी, जिनके कारण आर्थिक विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में बाधा आयी. इसलिए एक दशक से सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उन खामियों को दूर करने में लगी हुई थी. इस अवधि में अप्रासंगिक नीतियों की जगह नयी नीतियां लागू हुईं और संस्थानों में सुधार किये गये.

शिक्षा में ठहराव का मुख्य उदाहरण 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जो अहम वैश्विक परिवर्तनों के बीच पीछे रह गयी थी. इसके स्थान पर सरकार ने 2020 में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, जो विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक दूरदर्शी दस्तावेज है. लेकिन अनेक बाधाओं और जटिलता से इसका कार्यान्वयन अवरुद्ध हुआ है. शिक्षा संविधान की सातवीं अनुसूची में एक समवर्ती विषय है. राजनीतिक कारणों एवं जागरूकता के अभाव में कुछ संस्थान इस नीति को लागू करने में हिचक रहे हैं या उनकी गति धीमी है. यह नीति स्थानीय भाषाओं में उच्च शिक्षा देने, बहुविषयक शिक्षण बढ़ाने तथा विश्लेषणात्मक क्षमता की पैरोकारी करती है. इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान भी है. इस नीति में समता और समावेश पर जोर दिया गया है. नीति को इस तरह बनाया गया है, जिससे एक समावेशी शिक्षा तंत्र बने, जिससे सभी को समान अवसर मिल सके और देश की आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. शिक्षा नीति और अन्य नियामक नीतियां अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए आधार हैं तथा इन्हें शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से लागू करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए.

'विकसित भारत' के व्यापक उद्देश्य के अंतर्गत, नयी सरकार को बहुत सक्षम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक उच्च शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए संस्थागत एवं व्यक्तिगत हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देनी चाहिए. विज्ञान से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के प्रशंसनीय योगदानों के बावजूद हमारी उच्च शिक्षा को समुचित वैश्विक पहचान नहीं मिल सकी है. इस कारण क्षमता एवं संभावना के बावजूद विदेशी सहभागिता और अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपेक्षा के अनुरूप आकर्षित नहीं किया जा सका है. फिर भी, एक उल्लेखनीय बदलाव से इंगित होता है कि उच्च शिक्षा के प्रति रवैये में परिवर्तन आ रहा है. यह बदलाव है- स्नातकों की संख्या बढ़ाने की जगह कौशलयुक्त श्रमबल का विकास. यह बदलाव उच्च शिक्षा में अंतर्विषयक और बहुविषयक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है. उदाहरण के लिए, आईआईटी में समाज विज्ञान तथा मानविकी में तकनीकी एवं कोडिंग पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है. उच्च शिक्षा के विकास के बारे में विमर्श अक्सर इंजीनियरिंग, बायोटेक, विज्ञान और तकनीकी के इर्द-गिर्द घूमता है, पर यह समझना जरूरी है कि मानविकी और समाज विज्ञान भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं. इनमें दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता है.

हालिया चुनाव में जिस तरह से भ्रामक सूचनाओं और तथ्यों से खिलवाड़ किया गया, वह अभूतपूर्व है. ऐसा विशेष रूप से मीडिया और सोशल मीडिया के जरिये हुआ. बिना किसी आधार के दुष्प्रचार से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश होती रही. हालांकि चुनाव ने ऐसी बातों को गलत साबित कर दिया, पर भारतीय मानस और देश की वैश्विक छवि को इससे बहुत नुकसान हुआ है. ऐसी चीजों के प्रतिकार के लिए सरकार को समाज विज्ञान के विकास पर जोर देना चाहिए ताकि ऐसे युवा तैयार हों, जो चाटुकार या विचारक होने की जगह तार्किक, अभिव्यक्ति-कुशल और सक्षम व्यक्ति हों. अंतरराष्ट्रीय संबंध, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और जनसंचार में शिक्षा को मजबूत करना नयी सरकार का अहम एजेंडा होगा. इससे आख्यान की शक्ति बढ़ेगी, जो राजनीतिक शक्ति को आधार देगी तथा नेतृत्व के समक्ष वास्तविकता का आईना रखेगी. तीसरे कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए सरकार को महत्वपूर्ण अवसर मिला है. सभी विषयों में व्यापक विकास आवश्यक है. केवल फैशनेबल विषयों पर ही एकतरफा ध्यान नहीं होना चाहिए. सरकार, शिक्षक, छात्र, प्रशासक- सभी को मिलकर इस अवसर को सार्थक बनाना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की निरंतरता का लाभ उठाया जाना चाहिए ताकि भारत और भारतीय विचारों के वैश्विक परिदृश्य में स्पर्धा कर सकें, अपनी दृष्टि को प्रस्तुत कर सकें और विकसित भारत के लिए ठोस तर्क रख सकें.

(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)

तीसरे कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए सरकार को महत्वपूर्ण अवसर मिला है. सभी विषयों में व्यापक विकास आवश्यक है. केवल फैशनेबल विषयों पर ही एकतरफा ध्यान नहीं होना चाहिए. सरकार, शिक्षक, छात्र, प्रशासक- सभी को मिलकर इस अवसर को सार्थक बनाना चाहिए.

देश दुनिया

इयू द्वारा लेबनान को एक अरब यूरो देने का अर्थ

पिछले महीने, यूरोपीय संघ (इयू) ने लेबनान के लिए एक अरब यूरो के सहायता पैकेज के बारे में बताया था. बेरूत की यात्रा के दौरान, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने घोषणा की कि यूरोपीय संघ लेबनान की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता में योगदान देना चाहता है. यह धनराशि बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने, वित्तीय सुधार लागू करने, लेबनानी सुरक्षा बलों का समर्थन करने और प्रवासन के प्रबंधन में खर्च की जायेगी. जिसे भी हताश शरणार्थियों और इयू में प्रवेश के इच्छुक प्रवासियों के विरुद्ध यूरोपीय संघ की सीमा एजेंसी 'फ्रोंटेक्स' द्वारा किये गये दुर्व्यवहारों की जानकारी है, उसके लिए यह बात चिंता का कारण होगी. भूमध्य सागर में काम करने वाले एक खोज और बचाव संगठन 'सी वॉच' ने इस समझौते को 'सीमा पर होने वाली हिंसा के लिए एक और नकद समझौता' के रूप में वर्णित किया है, जिसमें यूरोप सीमा पर हिंसा और मौत के लिए धन का लेन-देन कर रहा है. वास्तव में, यूरोपीय संघ के वित्तीय समर्थन से लोगों के अपराधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निसंदेह इस कारण शरणार्थियों, विशेषकर सीरियाई लोगों को और अधिक पीड़ा उठानी होगी, जो पहले से ही लेबनान में दुर्व्यवहार और कठिनाई का सामना कर रहे हैं. यह धन भ्रष्ट और बेहद निष्क्रिय राजनीतिक अभिजात वर्ग से छुटकारा पाने के लेबनानी लोगों के किसी भी प्रयास और उम्मीद को भी कमजोर कर देगा. लेबनान के लिए यूरोपीय संघ के सहायता पैकेज की घोषणा माइग्रेशन से निपटने के लिए क्षेत्र के अन्य देशों द्वारा उठाये गये कदमों का ही अनुसरण है. लीबिया, जिसे वर्षों से ब्रुसेल्स से वित्तीय सहायता मिलती रही है, वहां से प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार के अनेक मामले सामने आये हैं. मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं के बीच इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि लेबनान भी शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

-एलिआ जे अयूब

बोधि वृक्ष

तीसरी आंख

कहते हैं, चेहरा हमारे मन का सूचकांक है और आंखें आत्मा का दर्पण हैं. सच्चे अर्थों में देखा जाये, तो हमारी आंखें हमारे भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसे बखूबी प्रकट कर देती हैं, तभी तो कहते हैं कि चेहरा झूठ बोल सकता है पर आंखें नहीं. हम आंखों द्वारा प्रेम, घृणा, सहानुभूति और कई ऐसी भावनाएं प्रकट करते हैं. हमारे मन की स्थिति अपनी पसंद और नापसंद, गर्व और पूर्वाग्रहों के अनुसार कार्य करने के लिए हमारी आंखों को निर्देशित करती हैं. हमारे शरीर के पांच संवेदी अंगों में से आंखें सबसे शक्तिशाली हैं क्योंकि ये आत्मा की अनुभूति का द्वार हैं. इसी के माध्यम से आत्मा हर चीज की अनुभूति करती है. अमूमन, आंखों के विषय में जब बात होती है, तब हमारी दो आंखों की ही बात होती है, मगर हम सभी के पास एक 'तीसरी आंख' भी है. उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होती. भला ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वह गैर भौतिक है, इसलिए उसे 'अदृश्य आंख' भी कहा जाता है, जिसे भौतिक आंखों से देखा नहीं जाता. अपितु, उसके लिए 'दिव्य बुद्धि' या 'दिव्य अंतर्दृष्टि' की आवश्यकता पड़ती है जो केवल सर्वशक्तिमान परमात्मा से ही प्राप्त की जा सकती है. जब हमारी 'तीसरी आंख' अर्थात ज्ञान का नेत्र खुलता है, तब प्रकाश हमारे जीवन में आता है और हमारी सोच में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है. इस नयी दृष्टि द्वारा हम स्वयं के एवं अन्य के वास्तविक रूप को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं. दया, सत्य और प्रेम हमारे विचारों में समाविष्ट हो जाते हैं और सर्व के प्रति हमारी दृष्टि बिना किसी द्वंद्व के स्वच्छ और आत्मीय बन जाती है. इस तीसरी आंख को खोलने की विधि क्या है? इसके लिए हमें केवल 'ध्यान' का नियमित अभ्यास करना होगा, क्योंकि 'ध्यान साधना' द्वारा हमें स्वयं को अधिक गहराई से समझने की शक्ति प्राप्त होती है, जो हमें अपने आप को आंतरिक रूप से बहाल करने में मदद करती है. 'ध्यान' द्वारा प्राप्त शांति का अनुभव हमें हमारी मूल प्रकृति के साथ संपर्क में लाने के लिए सक्षम बनाता है और स्वयं के साथ-साथ अन्य के जीवन को भी प्रबुद्ध करता है.

-ब्रह्माकुमार निकुंज जी

विश्व रक्तदान दिवस

रक्तदान के लिए जागरूकता

हर वर्ष 14 जून को रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'विश्व रक्तदान दिवस' मनाया जाता है. रक्त मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण घटक है. यह शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है, अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. दान किया गया रक्त तीन लोगों की जान बचाने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसे अलग-अलग घटकों- लाल कोशिकाओं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में विभाजित किया जा सकता है.

नियमित रक्तदान स्थिर रक्त आपूर्ति बनाये रखने में सहायक होता है, जो आपातकालीन स्थितियों और नियमित चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है. रक्त बैंकों और अस्पतालों को रक्त की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, ताकि वे रोगियों की जरूरतों को पूरा कर सकें. इसलिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए नियमित स्वैच्छिक रक्तदान अपरिहार्य है. उल्लेखनीय है कि रक्त नहीं मिलने के कारण भारत में प्रतिवर्ष 15 लाख लोगों की मृत्यु हो

देवेंद्रराज सुथार
टिप्पणीकार
devendrakavi1@gmail.com

जाती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुसार, किसी भी देश में, किसी भी स्थिति में उसकी जनसंख्या का कम से कम एक प्रतिशत रक्त आरक्षित होना ही चाहिए. उक्त मानक के अनुसार, हमारे देश में कम से कम एक करोड़, तीस लाख यूनिट रक्त का हर समय आरक्षित भंडार होना चाहिए. परंतु पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार हमारे पास प्रतिवर्ष रक्त की औसतन 90 लाख यूनिट ही उपलब्ध हो पाती है. इसका कारण है, भारत में रक्तदान के प्रति लोगों में उदासीनता या झिझक. यह उदासीनता जागरूकता की कमी, गलत धारणाओं और सांस्कृतिक दृष्टिकोण सहित कई कारकों के संयोजन से उपजी है. कुछ लोगों का मानना है कि रक्तदान करने से उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है. इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान सुविधाएं या तो दुर्लभ हैं या खराब हैं. पहुंच की यह कमी रक्तदाताओं को हतोत्साहित करती है, क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. सो, देश में रक्तदान के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और प्रचलित मिथकों को दूर करने के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता है.

भारत जैसे भौगोलिक विभिन्नता वाले देश में, जहां कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं अक्सर दस्तक देती हैं, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हमारे जवान खून बहाते हैं तथा हमारे पड़ोसी हमेशा युद्ध जैसे हालात पैदा करते हैं, ऐसे में रक्त का पर्याप्त आरक्षित भंडार होना अत्यंत आवश्यक है. अतः देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्वसुविधायुक्त ब्लड बैंक स्थापित करने की आवश्यकता है.

आपके पत्र

भीषण गर्मी में बरतें विशेष सतर्कता

दिनों दिन बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया है. लू की चपेट में आने से कई की जान भी जा चुकी है. इसलिए, सावधानी जरू-री है. प्रशासन ने स्कूल व कोचिंग को बंद करा दिया है. गर्मी की चपेट में आने से बच्चे, वृद्ध, जवान व महिलाएं आ रही हैं. स्कूल बंद होने के बाद भी शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ रहा है. इससे शिक्षक भी लू के शिकार हो रहे हैं. इस पर सरकार व प्रशासन को विचार करना चाहिए. सभी को बारिश का इंतजार है. किसान पानी की कमी के कारण धान का बिचड़ा नहीं डाल पा रहे हैं.

सरोज शुक्ल, पटना

आतंकियों की सक्रियता चिंतनीय

जम्मू में चार दिनों में चार आतंकी हमला होना, चिंता का विषय है. हालांकि, सुरक्षाकर्मी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं. आतंकी निर्दोष लोगों के साथ सुरक्षा बलों को भी निशाना बना रहे हैं. इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष बैठक की. साथ ही ठोस कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया. यह सच है कि पाकिस्तान किसी तरह जम्मू-कश्मीर में अशांति बनाये रखना चाहता है. सुरक्षा बलों को रणनीति में बदलाव कर आतंकियों की मदद करनेवालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए. इससे आतंकी अपने मंसूबे में सफल नहीं होंगे.

रवींद्र कुमार, आरा